



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—प-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

26138
16-1-86

सं० 460J
No 460J

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 1985/आश्विन 3, 1907
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 1985/ASVINA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग सकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

का आ 696(अ) — राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 77 के खण्ड
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य
आवृत्त) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाते हैं अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आव-
ृत्त) (एक सौ चौहत्तरवां संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 भारत सरकार (कार्य आवृत्त) नियम, 1961 को अनुसूचियों
के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

प्रथम अनुसूची"

(नियम 2)

सचिव, विभाग सचिवालय तथा कार्यालय

1 द्वितीय मंत्रालय

(1) कृषि और सतहकारिता विभाग

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

859 GI/85—1

(III) ग्रामीण विकास विभाग

(IV) उर्वरक विभाग

2 वाणिज्य मंत्रालय

(1) वाणिज्य विभाग

(II) वस्त्र विभाग

(III) पूति विभाग

3 संचार मंत्रालय

(1) डाक विभाग

(II) दूर संचार विभाग

4 रक्षा मंत्रालय

(1) रक्षा विभाग

(II) रक्षा उत्पादन और पूति विभाग

(III) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

5 ऊर्जा मंत्रालय

(1) कोयला विभाग

(II) विद्युत विभाग

(III) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

(I)

- 6 पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण वन तथा वन जीव विभाग
- 7 विदेश मंत्रालय
- 8 वित्त मंत्रालय
(1) आर्थिक कार्य विभाग
(ii) व्यय विभाग
(iii) राजस्व विभाग
- 9 खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(1) खाद्य विभाग
(ii) नागरिक पूर्ति विभाग
- 10 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(1) स्वास्थ्य विभाग
(ii) परिवार कल्याण विभाग
- 11 गृह मंत्रालय
(i) अन्तरिक्ष सुरक्षा विभाग
(ii) राज्य विभाग
(iii) राजभाषा विभाग
(iv) गृह विभाग
- 12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय -
(i) शिक्षा विभाग
1) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग
ii) महिला कल्याण विभाग
(iv) कला विभाग
(v) संस्कृति विभाग
- 13 योग मंत्रालय
(i) औद्योगिक विकास विभाग
(ii) कृषि कार्य विभाग
(iii) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
(iv) रणकरी, उद्यम विभाग
- 14 सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- 15 श्रम मंत्रालय
- 16 विधि और न्याय मंत्रालय
(1) विधि कार्य विभाग
(ii) विधायी विभाग
(iii) न्याय विभाग
- 17 सार्वजनिक कार्य और पर्यटन मंत्रालय
(i) सम्पूर्ण कार्य विभाग
(ii) पर्यटन विभाग
- 18 एक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा वेतन मंत्रालय
(1) कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(iii) वेतन और वेतन भागीकरण विभाग
- 19 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
- 20 योजना मंत्रालय
(1) योजना विभाग
(ii) सांख्यिकी विभाग
- 21 कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- 22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- 23 इस्पात और खान मंत्रालय
(i) इस्पात विभाग
(ii) खान विभाग
- 24 परिवहन मंत्रालय
(1) रेल विभाग
(ii) नागरिक विमानन विभाग
(iii) जल मूलत परिवहन विभाग
- 25 शहरी विकास मंत्रालय
- 26 जनसंसाधन मंत्रालय
- 27 कल्याण मंत्रालय
- 28 परमाणु ऊर्जा विभाग
- 29 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
- 30 महासागर विकास विभाग
- 31 अंतरिक्ष विभाग
- 32 मन्त्रिमंडल सचिवालय
- 33 राष्ट्रपति सचिवालय
- 34 प्रधान मंत्री कार्यालय
- 35 योजना आयोग

द्वितीय अनुसूची

(नियम 3)

विभागों में विषयों के वितरण

कृषि मंत्रालय

क कृषि और सहकारिता विभाग

भाग-1

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान के सप्तम अनुसूची की सूची 1 में के अंतर्गत हैं --

1 अन्तर्गोष्ठीय कृषि संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ सम्पर्क कोआपरेटिव फार्म अमेरिकन रलीफ एग्रीकल्चर (मी ए आर ई) के कृषि आदि से संबंधित मूल का प्राप्ति करता।

2 कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों सम्मेलन तथा अन्य क्रिया में भाग लेना और वहां पर लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन।

3 टिड्रो नियंत्रण का अभियान।

4 पशु संरक्षण योजना।

5. वे उद्योग, जिनके लिए समूह ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे
समूह के नियंत्रण लक्षित में मर्यादित हैं वहां तक वे
निम्नलिखित से सम्बद्ध हैं --

(क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध, शिगू, दुग्ध आहार, मास, मित्रि,
दुग्ध आहार, सफाई दुग्ध, घी और अन्य डेरी उत्पाद),
मांस और मांस उत्पादों का समायोजन और प्रशोधन,

(ख) कृषि उद्योग (मशीनरी, उर्वरक, बीज और पशु खाद्य सहित)
का इस परिभाषा के साथ विकास कृषि उद्योगों (मशीनरी
और उर्वरक सहित) के विकास के बारे में कृषि विभाग के
वर्तमानों के आकलन और चर्चा के निम्न में अधिक न
है,

(ग) शक्कल उद्योग

(घ) मछलियों का संसाधन (जिनके अंतर्गत डी.बो में बंद करना
और हिमनिरक्षण भी सम्मिलित है),

(ङ) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना
और उसकी प्रवृत्ति व्यवस्था और

(च) मत्स्य संसाधन उद्योगों का तकनीकी सहयता और सहायता

6. अन्वेषण और सतुदी मछली पकड़ने और मछली क्षेत्र।

7. राज्य क्षेत्रीय समुद्र में परे मछली पकड़ने और मछली क्षेत्र
(जिनके अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का स्टेशन सम्बद्ध है)।

8. कृषि संबंधी गणना और पशुगणना

9. अखिल भारतीय सेवाएं--भारतीय कृषि सेवा।

10. ग्राम विकास समीक्षा

11. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए नुकसान और
पशुधन का हानि हानि समीक्षा

12. महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण
मानव जीवन और सम्पत्ति को हानि वाली हानि से संबंधित मामले।

13. महामारियों से भिन्न, सभी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण
अवश्यक राहत उपायों का समन्वय।

14. भारतीय जन दुर्घटना

भाग--III]

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची
की सूची III के अंतर्गत हैं, (केवल विधान की बाबत) --

15. खाद्य पदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों में अपमिश्रण।

16. आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी)।

17. वृत्तियां (पशु चिकित्सा व्यवसाय)

18. पशुओं या वनस्पतियों को हानि पहुंचाने वाले सक्तामक या
समयिक रोगों या नाशकशीलों के, जिनके अंतर्गत टिटुडिया भी है, एक
राज्य में दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।

19. खाद्यान्न, शर्करा वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और
बना, जन्म, रूई और चाय के निवारण कृषि वस्तुओं की कीमत का
नियंत्रण।

20. निर्यात का उत्पादन।

21. राज्य अपने अधिकारों द्वारा या सहकारी समीक्षा द्वारा डेरी
विकास। स्वामी या भारत के उपर लेने वाले विभिन्न राज्यों को
लेने की शक्ति का रूप।

22. जड़ उत्पादन I और II तथा उनमें सम्बद्ध सभी मामलों।

23. पशुओं के प्रति निर्यात का निवारण।

भाग--III

सब राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और II में वर्णित विषय
जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त
निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की
सूची II के अंतर्गत हैं --

24. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न), मारकों से रोगों
और पादप रोगों का निवारण।

25. पशु रोगों का परीक्षण, संरक्षण और उन्नति और पशु रोगों
का निवारण, शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।

26. प्रतिपालक अधिकरण।

27. कृषि क्षेत्र में सहयोग, कृषि ऋण और ऋण प्रस्तुत।

28. कृषि उत्पाद के विपणन संबंधी सामान्य नीति जिसमें कीमत-
निर्धारण, निर्यात आदि सम्मिलित हैं।

29. बीमा (फसल और पशु बीमा)

30. सभी संकटों से सहकारिता और सहकारी क्रियाकलापों के
समन्वय के क्षेत्र में आधारण नीति (संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में
सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी हैं)

31. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामलों।

32. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

33. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का चले उद्देश्य एक राज्य तक
सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।

34. सहकारी, विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों को
प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की
शिक्षा सम्मिलित है)।

भाग--IV

साधारण और पारिजातिक

35. जहां तक कृषि और सहकारी विषयों का संबंध है वहां तक
विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध
सब मामलों, जिनके अंतर्गत वे सभी मामलों हैं, जो कृषि और सहकारी
विषयों के क्षेत्र में भारत द्वारा विदेशों को दी गई सहायता से सम्बद्ध हैं,
किन्तु जिनके अंतर्गत कृषि, गवेषणा और शिक्षा तथा सहकारी विषयों
के क्षेत्र में के ऐसे मामलों नहीं हैं जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा
विभाग को विनिर्दिष्ट समनुविष्ट किए गए हैं।

36. कृषि और उद्यान कृषि।

37. बायोएथेटिक योजना।

38. पशुपालन जिसके अंतर्गत (क) काजी हाउस और पशु-उत्पत्ति

(ख) बारा वा उपयोग और वध है।

39. कृषि उत्पादन अधिकार और चारा उत्पादन।

40 भूमि उद्धार

41 राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड।

42 रई और पटमन का विकास।

43 विकास कार्यक्रमों से सम्बद्ध मूद्रा सर्वेक्षण।

44 राज्य भू-संरक्षण और वन विकास स्कीमों का वित्तीय सहमता।

45 उर्वरक और खाद (माता का आकलन तथा का नियतन और उर्वरकों का वितरण)।

46 (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 और (ख) उर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन।

47 कीटनाशी अधिनियम, 1968 का प्रशासन।

48 कृषि उपकरण और मशीनरी।

49 देश में विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास।

50 सघन कृषि विकास कार्यक्रम।

51 सघन कृषि क्षेत्र।

52 फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएँ और कृषक संगठन।

53. भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्कीमें।

54 यांत्रिक फार्म।

55 इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी सलान और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

56 ऐसे परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट आवंटित हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएँ।

57 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

58 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी के प्रयाजनों के लिए जाच और साक्ष्यकी।

59 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी की बाबत फीते उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं।

ख कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।

भाग- -I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैं --

1 विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय कृषि गवेषणा और शिक्षा संस्थाओं और संगठनों से संबंध, जिसके अंतर्गत कृषि गवेषणा और शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सगमों और अन्य निवाया में भाग लेना और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि में किए गए विनिश्चयों का अभिपूरति करना है।

2 मौलिक, अनुप्रयुक्त और सहायक गवेषणा और उच्चतर शिक्षा जिसके अंतर्गत ऐसी गवेषणा का समन्वय तथा कृषि, पशुपालन, डेरी

उद्योग और मानवश्रम में उच्चतर शिक्षा जिसे कृषि-अर्थशास्त्र और विषयन।

3 उच्चतर शिक्षा या गवेषणा का मन्त्रालय तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं में तथा समन्वय लागू और माता का निरीक्षण जहां तक वे खाद्य और कृषि से जियावे अंतर्गत पशुपालन डेरी उद्यान और मीन उद्यान हैं सम्बंधित हैं।

4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चाय कम्पा और खेड संघों कार्यक्रमों में भिन्न बन्धु अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्तपाषण के लिए उपकरण।

5 गन्ना अनुसंधान।

भाग- -II

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत, विद्यमान हैं, और इनके अनिश्चित निम्न-लिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैं --

6 कृषि शिक्षा और गवेषणा।

भाग- -III

साधारण आर पारिणामिक

7 जहां तक कृषि गवेषणा और शिक्षा तथा सहवृद्ध विषयों का संबंध है वहां तक विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त विदेशी सहायता से सम्बद्ध सब मामलों, जिनके अंतर्गत वे सभी मामले हैं जो कृषि गवेषणा और शिक्षा सहवृद्ध विषयों के क्षेत्रों में भारत द्वारा विदेशों को दी गई सहायता से संबंध है।

8 पादप प्रवर्तन और संग्रहण।

9 गवेषणा, प्रशिक्षण सह-संबद्ध, बर्गीकरण मूदा मानचित्रण और निर्वचन से संबंध अखिल भारतीय मूदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण।

10 राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों का कृषि गवेषणा आर शिक्षा स्कीमों तथा कार्यक्रमों की सघन वित्तीय सहायता।

11 राष्ट्रीय निरूपण

12 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके सघटक अनुसंधान संस्थान, स्टेशन प्रयोगशालाएँ और केन्द्र।

13 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।

14 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जाच और साक्ष्यकी।

15 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी की बाबत फीते उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं।

ग ग्रामीण विकास विभाग।

1 पचायती राज से संबंधित सभी मामलों।

2 भूमि मुधार भूमि पारण अधिकार भूमि रकार्ड, जोता की बर्क बन्दी तथा अन्य संबंधित मामलों।

3 भूमि अर्जन अधिनियम 1891 का प्रशासन और सघ के प्रयोजन लिए भूमि अर्जन संबंधी अन्य मामलों।

194

पायराण्टम कालेतम एव अमिः म लि ।

उद्योग विभाग में निर्मित विधियाँ से स्वरूप प्राप्त है।
परिचयनाएँ उन परिणामों का हैं जो छात्रों को प्राप्त करने के लिए
विभाग की विधिद्वारा आयोजित की गई हैं।

४. इमं मतान्त्य व आगत विनिर्दिष्ट विषया मं से हिन्तु स मो
सद्विधित गुभा गतन् अधनस्य वार्यान्ध क्कवा अन्य न्ध टन।

क वाणज्य रिना ग

१. अन्तराष्ट्रिय वाणज्यिक न ति ।

२. वर्णज्य नति से सबधिन अन्तराष्ट्रिय अस्विकरण (जैसे कि यू.एन.सी.टी.ए.ड. ई.एन.सी.ए.पी., ई.सी.ए. ई.सी.एन.ए., ई.ई.सी., ई.एफ.टी.ए., न.ए.टी.टी.)।

3 गह से भिन्न वनरार्ष्ट्रिय वस्तु- करार ।

4 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न तः सत्रेण अन्य विषय जिन मे टैरिफ और टैरिफ-इनर अवगोत्र सम्मिलित हैं।

(2) विदेश व्यापार

5 विदश व्यापार से संवाधत अन्य विषय जिनमे व्यापार बार्ता कार (जिनमे टैरिफ और व्यापार नियमन प्राधरण करार और मडल टैरिफ अधिमन गन्मिनिा हैं) व्यापार मिशन और प्रतिनिधि- द, व्यापार सहयोग और सबद्धन और विदेशस्य भारतय व्यापारियो कता का सुरक्षण समिसित ह ।

6. आयात और निर्यात व्यापार नति आर नियंत्रण जिसमे निम्न-
वृत्त विषय सम्मिलित नहा ह

(1) क्या चित्रा का आयात,

(iii) भारतीय फिल्मों का निर्माण दर्शन और अधु काय चित्र ज्ञान,

(111) फ़िल्म उद्योग द्वारा प्रसारित सिनेफ़िल्म (अनुप्रापित) और अन्य ओ का जाया और वितरण।

7 મુજબ નિયંત્રક, બાયાત કાર નિયોત ।

(2) राज्य व्यापार

8 राज्य व्यापार के नीतियाँ तथा इस उद्देश्य के लिए स्थापित संग-
का काय-नियमादन जिनमें ये सम्मिलित है

(1) हस्तशिल्प और हैंडलूम शिर्षा निगम तथा केशरीय कुटार निगम के स्विच राज्य व्यापार निगम तथा उनके सहयोग समूह।

(II) खनिज और प्रातु व्यापार निगम तथा उनके सहायक संगठन।

(4) शत्रु क साथ व्यापार शत्रु सपत्ति ।

9 शत्रु व पाप व्यपार—शत्रु करों और पाप मय प्रतिहानिपूर्ण। (अमृत गिणित उत्तरकर म भिन्न) शत्रु व्यपार नियंत्रण, भारत क लिए शत्रु ते अभिरक्षक।

10 टैलिफ अयाः स नवविं अशुद्धि य मया अनुरोधाय
नशुल्क व्ययः।

2. दूर संचार के पूज बजट के प्रति विचारों सत्रमों का निष्पादन जोर समिती द्वारा।

3. भारत के विमान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए...

4. भारतीय विमान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए...

5. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए...

6. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए...

7. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए...

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

1. भारत के तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा...

2. मध्य रक्षा बल, अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना।

3. थलसेना, नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।

4. प्रादेशिक थलसेना और सहायक वायुसेना।

5. राष्ट्रीय कैंडेट कोर सहायक कैंडेट कोर और लोक हायक सेना

6. थलसेना, नौसेना वायुसेना से संबंधित सर्कर्स और आर्डिनेंस...

7. रिमाउंट, पशु चिकित्सा और फार्म सगठन।

8. कैंपटीनूड विभाग (भारत)।

9. निम्नलिखित सेवाओं जिनके लिए रक्षा प्राक्कलनों में मदाय किया...

10. जप राशि नववर्ष और नए परिष्कृत मद्रो चाटों को तैयार...

11. छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिस्मन आच्छेदन, क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तिया तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है)।

12. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, रक्षा और त्याग। रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों को को।

13. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मिले जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी हैं।

14. रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग

1. रक्षा उत्पादन और निरीक्षण सगठन।

2. हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड।

3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड।

4. मजगाव डाक्स लिमिटेड, मुम्बई।

5. गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, कलकत्ता।

6. प्रागापट्टस कारपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद।

7. भारत अर्थ मवर्स लिमिटेड।

8. वैमानिकी से संबंधित सब विषय (जो उन विषयों से भिन्न हो जिन पर पर्यवेक्षण और निगरान विधानन मंत्रालय से है और उन विषयों

जो निम्नलिखित विभागों में अंतर्भूत हैं, जिनमें से प्रत्येक विभाग को सहायक विभागों के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

(क) वैमानिकी उद्योग का विकास और उद्योगों को बचाने का प्रयत्न

(ख) वैमानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का समन्वय विभाग अंतर्गत विमान, प्रक्षेपास्त्र भी हैं,

(ग) वैमानिकी में रणनीति और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक मन्त्रालय अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा अन्य अधिकरणों या निकायों को विनीय सहायता देना।

9. रक्षा प्रयोजनों के लिए, विशिष्टित इन्फ्रानिक्स, उपकरण निर्माण, वाहन और फौज-निर्माण के क्षेत्र में आया आवश्यकताओं के प्रतिस्थापन के लिए योजना बनाना तथा इस विषय में बरीबारी स्कीमे तैयार करना।

10. देश के औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने हुए अनुसंधान और विकास तथा निर्माण के लिए ऐसी स्कीमे का कार्यान्वयन।

ग रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. रक्षा मंत्री और तीना सेनाओं और अन्त सेवा गठनों को कोजी कार्यवाही उपस्कर और सैन्य तत्त्व (लाजिस्टिक्स) संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना।

2. निम्नलिखित के बारे में अनुसंधान विज्ञान और विषय संबंधी योजनाएँ तैयार करना--

(क) युद्ध-सामग्री

(ख) विस्फोटक पदार्थ

(ग) इलेक्ट्रानिक्स

(घ) इंजीनियरी

(ङ) राकेट और प्रक्षेपास्त्र

(च) वाहन

(छ) वैमानिकी

(ज) नौसेना समुद्र विज्ञान संबंधी मदे

(झ) अग्नि अनुसंधान

(ञ) तीना सेनाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अन्य मशीनरी और उपस्कर।

3. सगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं सहित रक्षा अनुसंधान और विकास सगठन का प्रशासन।

4. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियमावली, 1978 और रक्षा अनुसंधान और विकास सगठन (डी आर डी ओ) से संबंधित अन्य सेवा नियमों का प्रशासन।

5. रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद।

6. विभाग के नियंत्रण के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी कामिकों से संबंधित सभी मामले।

7. अन्योन्य और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए जिनसे रक्षा अनुसंधान और विकास का उत्पन्न हो वैज्ञानिक संस्थाओं, अनुसंधान, प्रयोगशालाओं तथा अन्य अधिकरणों या निकायों को वित्तीय सहायता देना।

8. देश में हो रहे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास कार्य का रक्षा अनुसंधान और विकास सगठन के कार्य के साथ समन्वय।

9. विदेशों में अनुसंधान और विकास सगठनों के साथ संपर्क, खासकर रक्षा के क्षेत्र में परामर्श पहलुओं के बारे में।

ऊर्जा संसाधन :

(क) कोयला विभाग

1 भारत में कोकिंग और नन-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के निक्षेपों का अन्वेषण और विकास।

2 कोयले के उत्पादन, पूर्ति विवरण और कोयलो से संबंधित सभी मामलों।

3 इस्पात विभाग जिनके नियंत्रण में है उनमें मिश्र कोयला वाह-रियों का विकास और संचालन।

4 कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से सशुद्ध तेल का उत्पादन।

5 कोयला खान (सुरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।

6 कोयला खान भविष्य निधि संगठन।

7 कोयला खान कन्याय संपन्न।

8 कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।

9 कोयला खान श्रम कन्याय निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन।

10 खानों में उत्पादन और प्रेषित कोयल और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अंतर्गत नियम।

11 कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।

12 कोयले और लिग्नाइट से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम।

13 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य केन्द्र कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इन प्रकार के प्रजायुत से प्रसंगिक कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

(ख) विद्युत विभाग।

1 ऊर्जा के क्षेत्र में साधारण नीति।

2 अनुसंधान विकास, तकनीकी सहायता और जल-विद्युत और उष्मीय शक्ति से संबंधित सभी मामलों।

3 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9)

4 विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54)

5 केन्द्रीय विद्युत बोर्ड।

6 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

7 मध्य राज्य क्षेत्र में विद्युत स्कीम।

8 दामोदर घाटी निगम।

9 नेशनल प्राजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड।

10 भाषा प्रवर्ध बोर्ड और ध्यान परियोजना (सिंचाई से संबंधित मामलों को छोड़कर)।

11 (1) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम।

(2) राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।

(4) उत्तर-पूर्व विद्युत शक्ति निगम।

(ग) प्रपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

1 बायो-मैस का अनुसंधान और विकास तथा बायो-मैस इन्टिरो में मध्य कार्यक्रम।

2 अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (सी ए एन ई)

3 मोर प्रकाश बोन्टीय यंत्र उनके विकास, उत्पादन और अनुप्रयोगों सहित।

पर्यावरण तथा वन संसाधन

पर्यावरण वन और वन्यजीव विभाग

1 पर्यावरण और परिसंस्थिति विभाग, जिसमें राष्ट्रीय मन्द मेनश्री और प्रवाल भित्तियों का पर्यावरण शामिल है, लेकिन खूने सागर में मन्दरी पर्यावरण शामिल नहीं है।

2 भारतीय वनस्पति विज्ञान संरक्षण।

3 भारतीय प्राणि-विज्ञान संरक्षण।

4 प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय।

5 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974।

6 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकरण अधिनियम, 1977।

7 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981।

8 जीव मनु रिजर्व कार्यक्रम।

9 राष्ट्रीय वन नीति और देश में सामाजिक वानिकी सहित वानिकी विकास।

10 वन नीति तथा वनों और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामलों जहां तक कि उनका संबंध अडमान और निकोबार द्वीप समूह से है।

11 भारतीय वन सेवा।

12 वन्य जंतुओं का परिरक्षण तथा वन्य पक्षियों और जीव जंतुओं का संरक्षण।

13 वानिकी में उच्च शिक्षा और उसके सम्बन्ध सहित मौलिक अनुसंधान।

14 पदमजा नायडु हिमानयन प्राणि-विज्ञान पार्क।

15 राष्ट्रीय भूमि उपयोग और वन भूमि विकास परिषद।

16 राष्ट्रीय वन भूमि विकास बोर्ड।

विदेश मंत्रालय

1 वैदेशिक मामलों।

2 विदेशी राज्यों एवं राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध।

3 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद।

4 भारत में विदेशी राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों और समुक्त राष्ट्र अधिकारियों और उनके विशेषता प्राप्त अधिकारों से संबंधित सभी मामलों।

5 पासपोर्ट और वीजा जिनके अंतर्गत भारत में प्रवेश के लिए वीजाओं का प्रदान या पृष्ठाकन नहीं आते, किंतु इसके अंतर्गत अधिकार (वर्षिक अफीका) नियम, 1944 के अधीन भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों को प्रवेश अनुज्ञापत्रों का प्रदान और मिशनरियों को छोड़कर श्रीलंका के राष्ट्रियों के लिए प्रवेश वीजाओं का प्रदान आता है।

6 अपराधियों और अभियुक्त व्यक्तियों का भारत से विदेशों एवं राष्ट्रमंडल देशों को और विदेशों एवं राष्ट्रमंडल देशों से भारत को प्रत्यर्पण तथा भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1903 (1903 का 15) का अन्वेषण प्रशासन, और राज्य क्षेत्रांतर्गत।

6 विदेशों में वाणिज्यिक उपहार देने के लिये अनु।

II अर्थिक विभाग के लिये विदेशी सहायता

7 निम्नलिखित व अन्य भारत द्वारा प्राप्त की गई तकनीकी और अभियंत्रण सहायता --

- (क) बालम्बो योजना के तकनीकी सहकारिता स्कीम।
- (ख) समुक्त राज्य का चतुर्थ मूल कार्यक्रम।
- (ग) समुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम।
- (घ) विभिन्न विदेशों से तकनीकी सहायता के सदर्थ प्रस्ताव।

8 बालम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के मध्यम दशों को भारत द्वारा की गई तकनीकी सहायता।

9 ओलम्बो योजना परिषद और योजना की परामर्शदात्री समिति के अधिवेशनों से संबंधित सभी मामले और--

- (1) समुक्त राज्य तकनीकी सहकारिता मिशन।
- (2) समुक्त राज्य विकास उधार निधि।
- (3) कोलम्बो योजना।
- (4) तार्विजियन सहायता।
- (5) फोर्ड फाउन्डेशन और राकफेलर फाउन्डेशन।
- (6) विदेशों से उधार और प्रत्यय।
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि आयात-निर्माण बैंक आदि से उधार और प्रत्यय।

10 इंडिया कन्सोर्टियम से संबंधित सभी मामले।

11 नेपाल, भूटान और बंगलादेश को छोड़कर अन्य देशों को ऋण और उधार मंजूर करने से संबंधित सभी मामले।

12 यूनाइटेड नेशन्स फंड फार पापुलेशन एक्टिविटीज (यू०एन०एफ० पी००) से संबंधित और राष्ट्रमंडल सच के विशिष्ट अभिकरणों तथा अन्य राष्ट्रसंघ विभागों को अगदानों से संबंधित नीति संबंध मामले।

13 (यू०एन०वी० के अन्तर्गत बहिंगमि, वालटियरो के अतिरिक्त) यूनाइटेड नेशन्स वालटियर्स सहित भारत में विदेशी वालटियर कार्यक्रम से संबंधित सभी विषय।

14 भारत का प्राप्त होने वाले अथवा विदेशी सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता जिसमें वे नहीं हैं जिनका समग्र किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों से हो।

III आन्तरिक वित्त

15 करों और सिकका निर्माण, अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित विषय --

- (क) प्रतिभूति मुद्राणालय और टकसालें, जिनके अन्तर्गत परब विभाग और चांदी परिष्करण परियोजना है--
- (ख) सिकका निर्माण,
- (ग) नोट जारी करना।

16 भाग्य के पूर्व विन्यासों के कोषपाल के कृत्य।

17 जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और सामान्य बीमा निगम की विनिधान पालिसी सहित विनिधान नीति।

18 कर्मचारी भविष्य निधि और इसी प्रकार की अन्य भविष्य निधियों के लिये विनिधान का टाका।

4 आर्थिक सहाय

19 उन मामलों पर ग्राह्य गजटों पर प्रकाशित नियमों के अन्तर्गत और नए पहलुओं का समाविष्ट करना है।

20 ऋण संधी राजस्व सहायता सहायता नीति।

5 बजट

21 अर्थोपय।

22 रेल बजट को जिसमें अनुपूर्व अतिरिक्त अनुदान भी हैं, को छोड़कर केन्द्रीय बजट तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा मध्य राज्य क्षेत्र के संबंध में सांविधानिक तंत्र को विफलता के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रवर्तनीय हो, तो ऐसे राज्य अथवा मध्य राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना।

23 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उधार लिया जाना और बाजार उधार का चालू किया जाना।

24 लोक निष्ठाओं जैसे निगमों, नगरपालिकाओं, आदि द्वारा उधार लिया जाना।

25 लोक ऋण अधिनियम का प्रशासन।

26 व्याज की दरें जिनके अन्तर्गत व्याज की दरें उत्पादकता परीक्षण दरें आदि हैं, नियत करना।

27 लेखा और लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ जिनके अन्तर्गत व्यवस्थाओं का वर्गीकरण है।

28 विभाजन, फेडरल वित्तीय एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित वित्तीय मामले।

29 भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 49)।

30 केन्द्रीय अनिशेषों के पुनर्गठन राजकीय विपन्न, जिनके अन्तर्गत तदर्थ राजकीय विपन्न हैं।

31 स्टॉकिंग पेंशन यू०के० सरकार को उत्तरदायित्व का अन्तरण अंतर्गत दायित्व के वित्तांकिक गणना।

32 केन्द्रीय और राज्य सरकार के बजटों का दिग्दर्शन।

33 वित्त आयोग।

34 कराधान ज्ञान आयोग।

35 अल्प बचनें, जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत संगठनों का प्रशासन है।

36 नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ

37 ससद के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखना और आर्थिक कार्य विभाग के सभी लेखा परीक्षा रिपोर्टों लाक लेखा समिति रिपोर्टों और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों का समन्वयन।

38 वित्तीय आयात।

6 शेयर बाजार

39 प्रतिभूति सचिवा विनियमन अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशासन।

40 शेयर बाजार का विनियमन।

7 स्टॉक पुरोधरण

41 ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों द्वारा पूँजी के पुरोधरण पर नियंत्रण।

7 क प्रकीर्ण अधिनियम

42 सरकारी बचन बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5)।

43 विनिधानों से संबंधित भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20।

44 घात सिकका अधिनियम, 1889 (1889 का 1)।

72. उपर्युक्त 65 से 71 प्रविष्टियाँ से संवद्ध सभी कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रकाशन ।

1. केन्द्रिय राजस्व बांढों से संबंधित सभी मामले ।

13 तमक पर विभाजित पुनः । शून्य न पार। न दाना न स
माभिल ।

3 विनियम पल्ला चौको, रुको, वहन पत्रो साख पत्रो, व मा पावि-
मियो, शेवरो व प्रतरण डिदवरो पराया। पल्ला गौर रस दो पर स्टाम्प
इल्क ।

4. सब प्रकार के स्टाम्पो का प्रदाय और वितरण।

५. आयकर (आयकर अपल अधिकरण सवध प्रश्नो को छोटकर) नियम कर, पूजा, अग्निताम कर, अग्निताम कर, कारवार लाम कर और सम्पदा शुल्क, धने कर, व्यय कर और दान कर, सवध सम प्रश्न और रेल यात्र, भाडा अधिनियम सवधो प्रश्न ।

6 सघ राज्य क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क का प्रशासन, अर्थात् निम्नलिखित
वैयक्तिक सभ मामले --

(क) मानव उपभोग के लिए मध्यमार्गिक लिक्वर।

(ख) अफ म, भाग-गाजा वर्ग पदार्थ और स्वापक औषधिया और स्वापक पदार्थ ।

7 ऐम् औषधिया तथा प्रसाधन निर्मितिया, जिनमे मद्यमार ग्रथवा
6(ख) के अतगत आने वाले किम पदार्थ का समावेश हो ।

8 अफीम, जहाँ तक उसके खती, विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय का मवध है।

9 'खतनाक औषधि' १२४ अन्तर्राष्ट्रिय करार और उसका कार्यान्वयन ।

10. मैं माशुल्क (समुद्र और भूमि) सवर्ध, मम मामले, जिनके अंतर्गत सं मा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) टैरिफ मूल्यांकन, सं मा-शुल्क, महकवरिता परिपद्, सं मा-शुल्क शब्दावली और ऐसे ही विषय है आयात या निर्यात किए गए माल पर शुल्क, आयातों और निर्यातों पर राजस्व के हित में अधिरोपित प्रतिषेध और निबन्धन और सीमा-शुल्क टैरिफ का निर्वचन ।

११ केन्द्र य उत्पाद शुल्क और स्वर्ग नियन्त्रण प्रशासन सबधे सभी मामले ।

12 विक्रय कर --

() विभाग (माल्यकरण) अधिनियम 1956
(1956 का 7) का प्रशासन,

(11) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विन्धन पर कर का उद्ग्रहण—केन्द्रीय विन्धन कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के प्रशासन में उत्पन्न समस्याएँ,

(iii) सविधान के अनुच्छेद 286 (3) के अधिन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के मगन जान वाले मान क घोषणा—उन शर्तों और निर्बंधना का अधिकथन जिनके अध्वधन वे राज्य विधिया होंगे जो उन पर कर के उद्घूहण के लिए उपबन्ध करन हैं ,

(iv) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा विषय कर के प्रतिस्थापन से संबंधित सभी प्रश्न, जिनके दायरगत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष मरुत द्वा माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) का प्रमाणन है।

(v) राज्यों में विक्रय कर के उद्ग्रहण से संबंधित वे सब विषयक आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों, सिफारिशों या अनुमति के लिए आए ,

(VI) मध्य राज्य क्षेत्रों में विक्रय कर से संबंधित विधायन मामले.

(vii) राज्यों में गन्ना उपकर उद्घाटन के अविधिमाय किए जाने से उत्पन्न समस्याएँ जिनके अन्तर्गत ऐसे उद्घाटनों का विधि-

१. अथ नस्य सग्न - -

(ग) आयक-विभाग

(८) म. म. पु. विभाग,

(ग) केय उत्पाद-शुल्क विभाग

(घ) स्वापक पदार्थ विज्ञान तथा

10 विदेश मन्त्रा के संरक्षण या तत्पर के निवारण से संबंधित
कार्यों के लिए निरर्थक निराश, ऐसे निराश के ग्रह न-यक्ति।

16 प्रवर्तन, अर्थात् विदेशी मद्रा विनियमन अग्रिम 1973 (1973 वा 46) के अधिन सगता के कारण उद्भूत हाा बाव मामला का अन्वेषण, न्याय निर्णयन और अभियोजन, राजस्व अग्रिमूचना महानिदे-
शालय तथा प्रवर्तन निदेशालय।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय

क खाद्य विभाग

I निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान का सन्तान अतिसूच के सूच I के अन्तर्गत हैं --

1 सिविल और सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निपटारा।

2 खाद्य में संवर्धित मसूमेलेनो, सगमो तथा अन्य निकायो जैसे कि अन्तर्गोष्ठीय गेहूँ, परिपद, अन्तर्गोष्ठीय शर्करा परिपद विश्व खाद्य परिपद, अन्तर्गोष्ठीय खाद्य नैति अनुसंधान संस्थान, मे भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

3 विदेशों से सधि और करार करना और खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबन्ध में विदेशों से क. गई सधिया, करारों और अभिसमयों की अभिवृत्ति।

4 खाद्यान्नों के, जिनके अन्तर्गत शकरा है, भंडारकरण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और उनका अर्जन, खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिए भूमि पट्टे पर लेना या उसका अर्जन।

5 खाद्यान्न तथा अथ खाद्य पदार्थों के वाहन, जिनके अन्तर्गत शर्करा है, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य।

6 व उद्घाटन जिनके लिए समझ न विधि द्वारा घादना है कि उन पर सध का नियमन लोकहित म समर्पण है वहा तक गहा तक उनका सुवध निम्नलिखित से है ---

(क) फल और सज्ज, समाधान उद्याग (जिनके अन्तर्गत हिम करण और निर्जल करण आते हैं) ,

(ख) शंकरा उद्याग (जिसके अन्नगत गुड अंर खाप्पार आने है)
और

(ग) खाद्यान्न पिसाई उद्योग ।

7 केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगम।

II निम्नलिखित विषय जो भारत सरकार के विधान के पन्चम अनुसूची के सूच III के अन्तर्गत हैं (केवल विधान के वाक्य) —

8 खाद्यान्नों का व्यापार और वाणिज्य तथा उका प्रदाय और वितरण।

9 शकरा म ग्रौर खाद्यान्नो ये विप्र खाद्य पदार्थो म पाप्मर और
वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।

10 खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और शर्करा व केमट निर्यात।

III भाग I और भाग II में उल्लिखित विषयो तथा दिल, अङ्गमान और निकाबार द्वयममूह और लक्षद्वय के खास प्रशामन के लिए ।

कारण और पाठ्यपुस्तक —

11 विज्ञानसत आयता र सम्बद्ध सभी —

(i) खाद्य विभाग क अधीनस्थ कार्यालय।

(ii) शर्करा निर्यात नई दिल्ली।

(iii) राष्ट्रीय शर्करा सम्मान कार्यालय।

12 शर्करा उद्योग विकास परिषद् नई दिल्ली से संबंधित मामलों।

13 इस विभाग का आवंटित विषयों में से संप्रति विधियों के विवरण प्रकाशित।

14 इस विभाग के प्राबल्य विषयों में से किसी के प्रमोशन के लिए जांच और प्रमाण।

15 इस विभाग का आवंटित विषयों में से किसी की वास्तव कीर्ति, उन कालों व मित्रों के सम्मान में ली जाती है।

ब नागरिक प्रति विभाग

I आन्तरिक व्यापार

1 आन्तरिक व्यापार

2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, स्पिरिट युक्त निर्मितया (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य) नियन्त्रण, अधिनियम, 1955।

3 वायदा बाजार का निगमन (अग्रिम सविदा) (विनियमन) अधिनियम 1952।

4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीर्ति और वितरण, जो विनिर्दिष्ट, किसी अन्य मन्त्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं है)।

5 चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1950 निरोध क अधीनस्थ व्यक्ति।

6 उपभोक्ता महकारी मन्त्रालय।

7 लोक वितरण प्रणाली।

8 कर्मियों का परिक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।

9 राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

10 पैक मी हुई वस्तुओं का विनियमन।

11 कार्गो मापविद्यालय पश्चिम।

12 वेडरिंग जिसके द्वारा सम्बद्ध विविधता घटाना की है कि उनपर वष का निरोध लावाहत में समीचीन है जहां तक वे वनस्पति, धी, निरुद्ध, वनस्पति तेल, छल, और धरा से सम्बद्ध है।

13 वनस्पति धी निरुद्ध वनस्पति तेल खली और वषा का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य नियन्त्रण, प्रति और वितरण।

14 वनस्पति धी वनस्पति तेल और वषा निदेशालय।

II व्यापार चिह्न आदि

15 व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958।

16 संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रदाय का निवारण) अधिनियम, 1950।

17 ग्राह और माप मानक (वाट और माप मानक) अधिनियम 1955 ग्राह और माप मानक अधिनियम, 1970।

18 भारतीय मानक मन्त्रालय (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952।

19 इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी मन्त्रालयों में प्रदानक कार्यालय या अन्य मांडन जिसमें कारवर्ट मन्त्रालय, नई दिल्ली में सम्मिलित है।

य स्वास्थ्य विभाग।

I स्वास्थ्य विभाग।

1 राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में सम्मान या विवरण व्यवस्था की प्राप्ति के लिए मध्य अधिवर्ण और राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित से नए सभी मानक आते हैं —

(i) कन्द्रीय अनुसंधान, कर्गोली

(ii) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता

(iii) एडिजन उत्पादन एकक कलकत्ता।

(iv) भारतीय मन्त्रालय मन्त्रालय, दिल्ली।

(v) केन्द्रीय औषधि प्रदायशाला, कलकत्ता।

(vi) परिचर्या कालेज, नई दिल्ली।

(vii) लेडी रोडिंग स्वास्थ्य स्कूल और रामचन्द्र लोहिया शिशु कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली।

(viii) मानसिक रोग अस्पताल, रांची।

(ix) राम मनोहर लोहिया अस्पताल और परिवर्तन गृह नई दिल्ली,

(x) मफदरजग अस्पताल, नई दिल्ली।

(xi) सिविल और मैनिफ औषधालय और एक्सपरे प्रविष्टान, गिफला।

(xii) डमडम और सम्मानक एयरपोर्टों में स्थित औषधालय।

(xiii) चिकित्सा भंडारण और कारखाने।

(xiv) बी सी जे वैज्ञानिक प्रयोगशाला, गिफली।

(xv) मेडिकल कालेज, पांडिचेरी।

(xvi) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारों से सेवा और उनके कुटुम्बों के सदस्यों के लिए अभिवादी स्वास्थ्य सेवा योजना, और

(xvii) भारत सरकार का सीरम विज्ञान और रसायन परीक्षण, कलकत्ता।

2 पतन-अन्तर्गत (समुद्र और वायु) नाविक और समुद्रीय अस्पताल और पतनकारत्तान से सम्बद्ध अस्पताल।

3 पतन और एयरपोर्ट स्वास्थ्य मण्डल।

4 नाविकों की स्वास्थ्य पराक्षा।

5 अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता विनियम।

6 विश्व स्वास्थ्य मण्डल (ड्यू एच ओ)

7 राफेलर फाउण्डेशन कार फाई फाउण्डेशन।

8 खाद्य प्रसमिषण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन स्थापित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला।

9 चिकित्सीय और सहायक विषयों में विदेशों में उच्चतर प्रशिक्षण।

10 कालम्बी और चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम के अधीन सहायता।

11 राष्ट्रीय मन्त्रालय उन्मूलन कार्यक्रम।

12 राष्ट्रीय फाउलरदा नियन्त्रण कार्यक्रम।

13 कार्यक्रम राग मन्त्रालय मन्त्रालय। औषधि आपूर्ति कुपोषण के प्रभाव और पेयजल का कमी से जिनमें प्राकृतिक विरतिता क परिणाम स्वास्थ्य विभिन्न रोग पैदा होते हैं, सम्बद्ध सम्मरण।

II मध्य राज्य क्षेत्रा विषयक विचारणीय और कार्य लक्ष्य प्रयाजना के लिए कार्यसूची

14 लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय।

15 भारत में ग्राहक मन्त्रालय का तीर्थस्थानों से भिन्न तीर्थस्थान।

- 16 कृषि और वन्यजीव संरक्षण और संयोजन नीति।
- 17 सरसों और मगस वाले।
- 18 सिलबाना प्रारंभ बुनन का प्रदाय और वितरण।
- 19 विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध वैज्ञानिक सोसाइटीया और संगम।
- 20 विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध पूर्ण और धार्मिक विन्यास।

III उस राज्य की सूची जिमें कवल सघ के लिए विधायी हैमियत में और सभा में राज्य क्षेत्रों के लिए विधायी, हर कार्यपालक दोनों हैसियत में कन्द्रीय सरकार व्यवहृत करती है।

- 21 चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सीय शिक्षा।
- 22 परिचर्या वृत्ति और परिचर्या शिक्षा।
- 23 भेषजिक वृत्ति और भेषजिक शिक्षा।
- 24 दन्त चिकित्सा वृत्ति और दन्त चिकित्सीय शिक्षा।
- 25 होम्योपैथी।
- 26 पागलपन और बुद्धि-युनता।
- 27 औषधिया के मानक।
- 28 औषधि और आपष पञ्चमी आपत्तिजनक विज्ञापन।
- 29 मानवों पर प्रभाव डालने वाले सत्रयक और ससर्गन्न रोगों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण।
- 30 खाद्य पदार्थों और औषधियों में अपमिश्रण।
- 31 स्वदेशी चिकित्सा पद्धति।
- 32 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा।

IV प्रकरण कार्य

- 33 भारतीय चिकित्सा परिषद्।
- 34 केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्।
- 35 सैन्य-वियोजित चिकित्सीय और सहायक चिकित्सीय कामिको का पुनःस्थापन।
- 36 युद्ध बंदियों और अन्य युद्ध पीड़ितों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं को छोड़कर, रेडक्रस।
- 37 भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्।
- 38 भारतीय परिचर्या परिषद्।
- 39 भारतीय फार्मेसी परिषद्।
- 40 भारतीय भेषज काप समिति।
- 41 शयरोन के विरुद्ध बी. सी. जी का टीका लगाना।
- 42 (i) उन सेवकों से, जो रेल सेवा में हैं
- (ii) उनसे जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों से प्रदायगी की जाती है,
- (iii) उन अधिकारियों से जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1954 द्वारा शासित हैं और
- (iv) उन अधिकारियों से जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 1955 द्वारा शासित हैं भिन्न केन्द्रीय सरकारों सेवकों के लिए चिकित्सीय परिचर्या और चिकित्सा की रियायत।
- 43 उन केन्द्रीय सिविल सेवाओं से जो रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त हैं और उनसे, जिन्हें सिविलियन सेवाओं के निवास स्थान प्राक्कलनों से प्रदायगी की जाती है, भिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा जोड़े।
- 44 भारतीय रडक्रस साम हटा।

संयोजन और वन्यजीव संरक्षण और संयोजन नीति।

- 46 वन्यजीव नाई पट्टेय श्रमिका सम्मेलन।
- 47 भौतिक चिकित्सा और पुनर्वासन का अधिन भारतिय सम्मेलन, मुम्बई।
- 48 आरोग्य श्रमस्थान और आरोग्यधाम।
- 49 स्थानिय निवास, राज्या और सघ क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण और समन्वयन।
- 50 द्रव्यमा मादर्यों परियाजना।
- 51 कुष्ठ नियंत्रण स्वाम।
- 52 विदेशों से प्राप्त अशोध चिकित्सीय सामान के दान पर सीमा-शुल्क की प्रविष्टि।
- 53 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
- 54 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली।
- 55 चित्तरजन राष्ट्रीय केन्द्र अनुसंधान बन्द बलकता।
- 56 केन्द्रिय देशा चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान, जामनगर।
- 57 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर।
- 58 शारीरिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, किंग एडवर्ड मैमोरियल अस्पताल, मुम्बई।
- 59 केन्द्रीय कुष्ठ अछापन और अनुसंधान संस्थान, मद्रास।
- 60 अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बंगलौर।
- 61 पोषण अनुसंधान संस्थान बृनूर।
- 62 इस सूची के विषयों में से किसी की बावत विधियों के विरुद्ध अपराध।
- 63 इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जाच और आकड़े।
- 64 इस सूची के विषयों में से किसी की बावत फीसे, किन्तु इनके अन्तर्गत किसी न्यायालय में नौ जान बानों फीसे नही आती है।

ख परिवार कल्याण विभाग

- 1 परिवार नियोजन के लिए नीति और संगठन।
- 2 मातृत्व और शिशु-कल्याण।
- 3 परिवार नियोजन के सभी पहलूओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संगठन और निदेशन, जिसके अन्तर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है।
- 4 परिवार नियोजन के महाम्या के उत्पादन और प्रदाय।
- 5 परिवार नियोजन से संबंधित विषयों के बारे में विदवा और अन्तर्राष्ट्रीय नियमों से सम्पर्क।
- 6 परिवार नियोजन से संबंधित जाच और आकड़े।
- 7 जनसांख्यिकी अध्ययन का अन्तरराष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई।
- 8 श्रम-दृश्य माधन का विकास और उत्पादन, जनसंख्या और परिवार नियोजन में संबंधित विचार शिक्षा और जानकारी।
- 9 स्वेच्छित संगठना और मानव विकास के परिवार नियोजन के माध्यम से विकास के माध्यम से उत्पादन।
- 10 हिन्दुस्तान नैटवर्क निमिटेड।
- 11 परिवार नियोजन का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली।

समान्य

क. गृह और सशस्त्र निष्ठा

(i) पुलिस

- 1 अग्रिम गश्क
- 2 सीमा सुरक्षा बल
- 3 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस अनुसंधान और विज्ञान ब्यूरो, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा काग्रेस और राष्ट्रीय अभिनियमन सेवा आयोग से संबंधित मामले ।
- 4 भारतीय पुलिस सेवा में जिनके मतर्गत भाग शामिल हैं, संबंधी मामले ।
- 5 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संबंधी मामले ।
- 6 नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और गश्ती मिश्रित आपात दल संबंधी मामले ।
- 7 किसी राज्य के पुलिस दल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का, उस राज्य के बाहर के किसी क्षेत्र पर विस्तार किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर के किसी क्षेत्र में, बिना उस राज्य की सहमति के, जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों का प्रयोग और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके, किसी राज्य के पुलिस दल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य के बाहर के रेल क्षेत्रों पर विस्तार ।

8 अन्तरराष्ट्रिय पुलिस वेतार प्रणाली

9 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

10 पुलिस परक

(ii) कानून और व्यवस्था

- 11 आतंकवादी और विध्वंसकारी नियायन (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) ।
- 12 आतंकवादियों में प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984—विशेष और अतिरिक्त न्यायालयों का स्थापना, और उस अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले ।
- 13 उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्रों (अर्थात् सविधान को पृष्ठ अनुसूची के पैरा 20 के साथ सलन सारणी के भाग "ख" विनियमित असम के अज्ञात जिलों) का, उनके अंतर्गत उन क्षेत्रों में सड़क मकनों के नियोजन पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं आता है, प्रशासन ।
- 14 खुफिया ब्यूरो, समन्वय विंग, केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली, केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो का केन्द्रीय अगुवी छाप ब्यूरो ।
- 15 भारत में प्रवेश के लिए बीजा देना और पृष्ठांकन तथा भारत में विदेशियों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुण, नागालैण्ड उत्तरपूर्व सीमान्त एजेंसी और मणिपुर स्थित सरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुज्ञा देना भी है ।
- 16 भारत में म्यांमार से उद्धार के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रियों को भारत के लिए बचा देना ।
- 17 विदेशी राज्यों के राष्ट्रियों को भारत से विवासन ।
- 18 छोड़े गए पाकिस्तानी बन्धियों का पाकिस्तान को संप्रत्यावर्तन ।
- 19 सरकारी सेवक जिनके कटुस्व पाकिस्तान में हैं—सरकारी सेवकों को पाकिस्तान जान को अनुज्ञा दिए जाने के मामले ।
- 20 भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा ।

21 केन्द्रीय सशस्त्र सुरक्षा संगठन तथा मामले ।

22 अवांछनीय साहित्य के भारत में आने का सामान्य सीमाशुल्क अधिनियम की प्राग 19 के अंतर्गत निवारण ।

23 आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1981 ।

24 सविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (i) के अंतर्गत जारी की गई किसी उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान सरकार सेवकों की किसी कर्तव्य के लिए सेवाओं की अद्यपेक्षा ।

25 जमीन मालानय अथवा विभागा को विनिश्चितता आवांछित विभाग नव को छोड़कर निवारक निरोध, ऐसे निरोध के अद्यधीन व्यक्ति ।

26 बन्धियों अतिरिक्त व्यक्तियों तथा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में दूसरे राज्य को हटाया जाना ।

27 दण्ड विधि ।

28 दण्ड प्रक्रिया ।

29 नागालैण्ड राज्य से संबंधित मामले ।

30 मिज़ोरम राज्य से संबंधित मामले ।

31 आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण (अग्रिम) अधिनियम, 1980 ।

32 रेलों में अपराधों रेल संपत्ति के लूण से संबंधित अपराधों से निवारण, से संबंधित मसौदा प्रश्न ।

33 शस्त्रास्त्र, अस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 से संबंधित मामले ।

34 अभिनियमन सेवा विकास ।

(iii) पुनर्वास

35 अनुपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ।

सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित हैं — शिविरो की स्थापना, नगर क्षेत्रों का भुगतान, अन्य सुविधाओं और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था ।

पुनर्वास निम्नलिखित सम्मिलित हैं — आवास प्रशिक्षण और रोजगार, भूमि, कारखाने उद्योगों और अन्य रूप में व्यवसायों के सहाय में पुनर्स्थापन ।

36 प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रियों का गृह और उनका पुनर्वास ।

37 तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास ।

38 जम्मू और कश्मीर में छद्म क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास । छद्म विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण ।

39 दण्डकारण्य विकास योजना और दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ।

40 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय शिविरो, कार्यस्थल शिविरो के लिए और कर्मों शिविरो का प्रशासन ।

41 पुनर्वास उद्योग निगम ।

42 पश्चिमी बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आने विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्ट समस्याएं ।

43 बंगला देश से आये शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं ।

44 जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान अधिभूत क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों की अवशिष्ट समस्याएं ।

45 समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास ।

46 भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ।

47 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में आये विस्थापित व्यक्तियों के आवासीय भवन का अन्वेषण।

48 निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव —

- (क) निष्ठापन मर्यादा का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31)।
- (ख) निष्ठापन विनियम (प्रशासन) अधिनियम 1951 (1951 का 64)।
- (ग) विस्थापित व्यक्ति (अर्थ-समझ) अधिनियम, 1951 (1951 का 70)।
- (घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44)।
- (ङ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुसूचक अधिनियम, 1954 (1954 का 12)।
- (च) निष्ठापन निक्षेपों का हस्तान्तरण अधिनियम, 1954 (1954 का 15)।
- (छ) गोवा दमन और दीव में निष्ठापन सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम 1964 में संशोधित मामले।

49 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में आये विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़े गये निष्ठापन सम्पत्ति के संबंध में पाकिस्तान के साथ वादचर्चा।

50 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से प्राप्त चलसम्पत्ति को भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित व्यक्तियों को वापस देना।

51 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में आये विस्थापित व्यक्तियों, जो अधिभूत प्रांतों और स्थानीय विवादों में सरकारी कर्मचारी थे, के पेंशन भविष्य निधि, अवकाश वेतन और प्रति-प्रति निक्षेपों संबंधी दावों का सत्यापन और भुगतान।

भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से आये विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश वेतन और अनुग्रह-पूर्वक न्याय का भुगतान, ठेकेदारों को उनके सत्यापित दावों के संबंध में सहायता के अनुदान के लिए तदर्थ योजनाएँ, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से 1-1-1961 और 25-6-1971 के बीच उनके पेंशन भोगियों का सहायता का अनुदान।

52 इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में संबंधित सभी संलग्न श्रवण अन्वेषण कार्यालय अथवा अन्य संगठन।

द्रष्टव्य — जहाँ विनिर्दिष्ट है उसे छोड़कर, सहायता और पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित और प्रशासनिक होते हैं।

ख राज्य विभाग

क केन्द्र राज्य संबंध —

1 नए राज्यों की स्थापना और उनका बनाया जाना, उनसे उद्भूत होने वाले विषय (ऐसे विषयों को जिनका संबंध सेवा-कार्मिकों के आबंटन और सेवाओं के एक करण से है तथा अन्य ऐसे मामलों को छोड़कर जो कार्मिक विभाग को आमतौर पर राज्य सेवाओं से सम्बद्ध हैं) तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन।

2 संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (22) में निर्दिष्ट भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नामों और उनके कुर्रुमों से संबंधित मामले।

3 जम्मू-नरमीर राज्य के संबंध में सार्वजनिक उपबंध और उस राज्य से संबंधित अन्य मामले, जिनके अंतर्गत वे मामले नहीं आते हैं जो विदेश स्वतंत्रता से संबंधित हैं।

4 संघ राज्य क्षेत्रों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में आगमन — अनुच्छेद 371 के तहत उपबंध।

5 अन्तराष्ट्रीय संबंध —

6 अन्तराष्ट्रीय परिषद —

7 अन्तराष्ट्रीय प्रस्ताव —

8 संघ राज्य क्षेत्रों —

9 अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपों को चार्ज वितरण।

10 संघ राज्य क्षेत्रों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में आगमन — राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों।

9 अण्डमान प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली दिल्ली, गोवा दमन और दीव, मिजोरम तथा पाकिस्तान के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए।

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II में प्रणालित मामलों की परिधि के अंतर्गत आते हैं:—

(i) सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु इसके अंतर्गत अचैनित शक्ति को सहायता के लिए सब का नौ चल या वायुमार्गों के बलों का प्रयोग नहीं आता है)।

(ii) पुलिस बल के अंतर्गत रेलवे और ग्राम पुलिस भी है।

(iii) कारागार, मुद्रासाल, बोस्टन सम्पत्ति और तदर्थ अन्य संस्थाएँ और उनमें निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्य से प्रवाह।

(iv) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका समिति का गठन और उनकी शक्तियाँ।

(v) दिल्ली अग्निशमन सेवा।

(vi) बाजी लगाना और भूत।

(vii) लोक सेवा संबंधी माध्याम प्रश्न।

(viii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध।

(ix) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी की बाबत न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ।

(x) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी की बाबत कोर्टों, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ले जाने वाले फीस नहीं आती हैं।

(xi) राज्य अधिनियमों का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार।

(xii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए ज़ाच और झाड़ें।

(xiii) अन्य विभागों में व्यवहृत विषयों से विश्व विषयों के प्रशासन के बारे में माध्याम प्रश्न।

10. अण्डमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्र के लिए।

निम्नलिखित के सिवाय सभी विषय —

(क) वन, शिक्षा, सड़कें और उन पर के पुनः मकम और पारवार्ड, और

(ख) मुख्य भूमि द्वीपों और अन्तर्द्वीपीय पोत परिवहन सेवाओं का मगडन और अन्तर्द्वीपीय

11. लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के लिए —

मुख्य भूमि के द्वीपों और अन्तर्द्वीपीय पोत परिवहन सेवाओं के मगडन और अन्तर्द्वीपीय के मिश्रण इन दोनों के संघ में सभी मामलों।

राजभाषा विभाग

1 सविधान के राजभाषा में सम्बन्धित उपबन्धों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का भाषान्वयन बढा तक के सिवाय जहाँ तक इस प्रकार का कार्यन्वयन किन्हीं अन्य विभागों का मोह दिया गया है।

2 राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों में अंग्रेज भाषा में भिन्न भिन्न भाषा का नीति प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

3 सच को राजभाषा के रूप में हिन्दू के प्रगाम प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए जिनका केन्द्र या सरकार कर्मचारियों के लिए हिन्दू शिक्षण योजनाएँ और मैगजिन, पत्रिकाओं और उससे सम्बन्धित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है, नोटय उत्तरदायित्व।

4 सच के राजभाषा के रूप में हिन्दू के प्रगाम प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामलों [जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अभिहित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) में शामिल हैं] में सामन्वय।

5 केन्द्रय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और सर्वग प्रबन्ध।

6 केन्द्रीय हिन्दू समिति, जिसमें इसका उपसमितियाँ भी शामिल हैं, से सम्बन्धित मामले।

7 विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिन्दू सलाहकार समितियों से सम्बन्धित कार्य का समन्वय।

8 केन्द्रय अनुवाद ब्यूरो से सम्बन्धित मामले।

घ गृह विभाग

1. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अधिसूचना।

2 (i) क्षमा, प्रविम्बन, मृत्यु दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण, और

(ii) जिस विषय पर सच के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस विषय सम्बन्ध किसे विधि के विरुद्ध अपराधों के लिए राज्यों के न्यायालयों द्वारा दण्डादिष्ट बन्धियों से (मृत्यु दण्डादेश से भिन्न) दण्डादेश के परिहार के लिए या क्षमा के लिए प्राप्त अर्जियाँ।

3 प्रधान मंत्री और नच के अन्य मन्त्रियों और सदस्य सचिवों के नियुक्ति और पदत्याग का अधिसूचनाएँ निकालना।

4 राष्ट्रपति के नाम से कागज पत्रों के अधिप्रमाणकरण के लिए नियम।

5. राज्य सरकारों के लिए कामकाज सम्बन्ध मानक नियम।

6 राज्य सभा और लोक सभा के लिए नाम निर्देशन।

7 राज्यपालों/उपराज्यपालों का नियुक्ति, पदत्याग और हटाए जाने का अधिसूचनाएँ निकालना।

8 (जम्मू-कश्मीर के सिवाय) राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयक, जो राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए हैं, और राज्य विधान को वास्तविक राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रय सरकार से पूर्व परामर्श।

9 राज्यों के राज्यपालों द्वारा निदाने गए अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

10 सच राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपालों, मुख्य आयुक्तों और प्रशासनिक अधिकारियों के नियुक्ति।

11 राजगाम, व्ययगन या स्वामीहू नत्व होने से सच प्रोद्भूत संपत्ति।

12 किस राज्य के जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोन जाने का भाषा के माध्य में विरोध उत्पन्न।

59 GI/85—

13 राज्यों के (विधायक सभा के सदस्यों के लिए) प्राप्ति के माध्य में अनुमोदन।

14 नागरिक मामलों में गृह विभाग के माध्यम से प्रविष्टि, विचार अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्बन्ध प्रश्न आदि अन्तर्गत प्रकाशना के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संगठन से प्राप्त विदेश प्रवक्ता आदि हैं।

15 नागरिकता प्रारंभ दण्डादेश।

16 दक्षिण अफ्रीका में सच के सिवाय विदेश और राष्ट्रमंडल देशों से या किन्हीं अन्य ऐसे देशों से आप्रानन जिनको व्यक्तिगत अधिनियम लागू है।

17 वापस हान वाले उत्प्राप्तियों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों का उन राष्ट्रमंडल देशों के सिवाय, जिन्हें व्यक्तिगत अधिनियम लागू है, राष्ट्रमंडल देशों से प्रवेश।

18 विधायकों के लिये आचरण-संहिता से सम्बन्धित मामले।

19 मन्त्रियों के लिए आचरण-संहिता।

20 सरकार सेवकों के पत्नियों या आश्रितों का भारत में विदेश भ्रमणों में नियोजन।

21 सिविल और सैनिक अधिकारियों का परस्पर आना-जाना।

22 भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार द्वारा सम्बन्धित लाटरिया।

23 जनगणना।

24 शासक्य पोशाक।

25 राष्ट्रपति और राज्यपालों के उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी विषयक अधिकार, सच के मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सदस्य सचिवों के वेतन और भत्ते।

26 राष्ट्रगान।

27 भारत का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रपति के और राज्यपाल के ध्वजध्वज।

28 राज्य संप्रतक।

29 अग्रता अधिपन्न।

30 पुरस्कार और धनकरण।

31 राष्ट्रय त्पीहार

32 राष्ट्रय एकीकरण से सम्बन्धित मामले।

टिप्पण — समग्र नीति के लिए गृह विभाग नोडिय विभाग होगा परन्तु उसके किसे, एक क्षेत्र के वास्तविक कार्यान्वयन के जिम्मेदार उस क्षेत्र से सम्बन्धित केन्द्रय मन्त्रालय अथवा विभाग के होगा।

33 शासक्य प्रयोजनों के लिए राष्ट्रय कैलेण्डर का उत्तरोत्तर प्रयोग

34 भौगोलिक नामों में परिवर्तन।

35 भारत के उच्च पदस्थों को मृत्यु पर पालन के जाने वाला औपचारिकताएँ।

36 राजनैतिक पेशर्ने।

37. गदर के बरों के आश्रितों को अनुकम्पा भत्ता।

38 जिन व्यक्तियों ने राजनीतिक, सामाजिक, परोपकार, या अन्य क्षेत्रों में अपने कार्य से राष्ट्र के सेवा के हैं उन्हें विशेष सहायता का आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करने के लिये गृह मन्त्री की वैधानिक निधि।

39 विषय।

40 ज व न सम्बन्ध साहित्यिक जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु को पंजयन भी है।

41 समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।

मानव ममाधान विकास मंत्रालय

क. शिक्षा विभाग

1. पूर्ण प्राथमिक शिक्षा ।
2. प्रारम्भिक शिक्षा ।
3. बुनियादी शिक्षा ।
4. माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन ।
5. विश्वविद्यालय शिक्षा ; केन्द्रीय विश्वविद्यालय ; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा ; उच्चतर शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की योजना और विकास में संबंधित "कारेन ऐड प्रोग्राम" ।
6. उच्चतर विद्या की (विश्वविद्यालयों से बिग्न) संस्थाएँ ।
7. बाल भवन, बालचर सग्रहालय ।
8. समाज शिक्षा और प्रौढ शिक्षा ।
9. शारीरिक शिक्षा ।
10. श्रव्य-दृश्य शिक्षा ।
11. पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन कागज और छपाई कागज उद्योग, जिससे औद्योगिक विकास मंत्रालय का संबंध है, को छोड़ कर) ।
12. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय के स्तर की पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन ।
13. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 और प्रतिलिप्याधिकार विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ।
14. शैक्षिक अनुसंधान ।
15. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी ।
16. अध्यापक प्रशिक्षण ।
17. बहुभाषी शब्दकोशों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार ।
18. हिन्दी के शिक्षण और सवर्द्धन के लिये वित्तीय सहायता देना ।
19. संस्कृत का प्रचार और विकास ।
20. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के संबंध में पुनर्वास की तथा अन्य समस्याएँ ।
21. केन्द्रीय शिक्षा मलाहकार बोर्ड ।
22. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ (यूनेस्को) और यूनेस्को से सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग ।
23. सब छात्रवृत्तियाँ जिनके अन्तर्गत वे छात्रवृत्तियाँ हैं, जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में विदेशों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की गई हैं, किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा निम्नसूचित, यायावर और अर्धयायावर जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ नहीं हैं; सामान्य छात्रवृत्ति स्कीम ।
24. विदेशस्थ भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण ; विदेशस्थ भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेशस्थ शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी सगर्भों को वित्तीय सहायता ।
25. शैक्षिक विनियम कार्यक्रम, अध्यापकों, आचार्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों आदि का विनियम; भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के विनियम का कार्यक्रम ।
26. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना ।
27. भारतीय संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
28. पूर्ण और पूर्वमस्याएँ; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध पूर्ण और धार्मिक विन्यास ।

29. विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, भूवैज्ञानिक विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न तथ्य वैज्ञानिक अनुसंधान ।

30. विज्ञान मन्दिर ।

31. गणित, भूवैज्ञानिक विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति ।

32. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय ।

33. योजना और स्थापत्य स्कूल ।

34. मुद्रण के प्रादेशिक स्कूल ।

35. तकनीकी शिक्षा के लिये राज्य सरकार की संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, सच राज्य क्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये सहायता अनुदान; शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिये सहायता अनुदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिये सहायता अनुदान, मूल अनुसंधान के लिये व्यक्तियों को अनुदान ।

36. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ।

37. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की राष्ट्रीय बिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र परीक्षाओं का संचालन ।

38. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ ।

39. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजनों के लिये वृत्तिक/तकनीकी अर्हताओं की मान्यता ।

40. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्य-पद और अध्येतावृत्ति ।

41. वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का भारत में आयोजन ।

42. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

43. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ।

44. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ।

45. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

46. भारतीय खान तथा अनुसूचित भू-विज्ञान स्कूल, धनबाद ।

47. खजपुर, मुम्बई, कानपुर, मद्रास और दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।

48. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।

49. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई ।

50. भारत में और विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह ।

51. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में किसी से संबंधित अन्य सभी संस्थान या अधीनस्थ कार्यालय या अरु संगठन ।

ख. युवक कार्यक्रम और खेल विभाग

1. खेलकूद, फ़ील्ड, बालचर, बोरखाला, राष्ट्रीय अनुशासन स्कूल, आदि ।

2. युवक कल्याण क्रिया कलाप, युवक समारोह, कार्य शिविर, आदि ।

3. भारतीय खेल प्राधिकरण

4. युवक कार्यक्रम

5. युवक होस्टल

ग. कला विभाग

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।

2. राष्ट्रीय नाट्यशाला ।

ब. संस्कृति विभाग

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक तथा ऐसी सभी अन्य संस्थाएँ जिनका वित्त-पोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद् ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की हैं ।

2. पुरातत्व, पुरातत्वीय संग्रहालय ।

3. प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 ।

4. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और छोटे कार्य के लिये विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।

5. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभियमन ।

6. स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास ।

7. कलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक निधि ।

8. गांधी स्मृति समिति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।

9. पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम (वहाँ तक जहाँ तक केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची पत्र देने का संबंध है) ।

10. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।

11. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियाँ ।

12. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा साइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक साइब्रेरी; इंदिरा आर्किव साइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक साइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; संग्रहालयों का साधारण विकास ।

13. राष्ट्रीय नव कला भवन, नई दिल्ली ।

14. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

15. निष्ठात निधि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 तथा पुरावशेषों का नियति ।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालायें और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएँ ।

17. सूचना और प्रसारण मंत्रालय को स्कीम के अधीन आने वाले प्रयोगों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।

18. दान और दूर संस्थाएँ; इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

19. छात्रवृत्तियाँ जिनके अन्तर्गत वे छात्रवृत्तियाँ भी हैं जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की जाती हैं ।

20. आधुनिक भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें ।

21. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।

22. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।

23. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।

24. विदेशों से सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियाँ ।

25. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।

26. विदेशों में सांस्कृतिक असाधियों की नियुक्ति ।

27. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।

28. विदेश परिदर्शन के लिये सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिनके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं) ।

29. विदेशों को पुस्तकें भेंट ।

30. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।

31. भारतीय बरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।

32. शासकीय प्रकाशनों की विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिये करार ।

33. विदेशों में भारतीय कला वस्तुएं भेंट करना ।

34. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्याधियों का प्रवेश ।

35. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों व नर्तकियों, संगीतज्ञों आदि का विनिमय ।

36. गणेशियों का पुनरीक्षण ।

37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शतब्दियों और शताब्दिकोत्सव मनाता ।

38. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित प्रकाशन, जानकारों और अधिकारों ।

39. इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरियंटलिस्ट्स ।

40. भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण ।

41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।

42. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।

43. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।

44. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सब संगठन या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

45. निम्नलिखित से सम्बन्धित चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन—

(i) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्रों का केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा परीक्षण और प्रमाणन ;

(ii) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ।

अ महिला कल्याण विभाग

1. कुटुम्ब कल्याण ।

2. स्त्री और बालक कल्याण और इस विषय के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।

3. स्त्रियों और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त प्रसंग ।

4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के शिक्षाओं की देखभाल ।

5. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय । प्राविद्यालय बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा ।

6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्व और धार्मिक विन्यास ।

7. इस विभाग को आबंटित विषयों के सदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संगठन या अधीनस्थ कार्यालय अथवा संगठन ।

9. स्त्री तथा लड़की जनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1986

10. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 ।

उद्योग मंत्रालय

क औद्योगिक विकास विभाग

I औद्योगिक नाति

- 1 साधारण औद्योगिक नाति ।
- 2 उद्योग (विश्व स और विनियमन) अधिनियम, 1951 का प्रशासन।
- 3 औद्योगिक प्रबंध ।
- 4 उद्योगों में उत्पादकता ।

II औद्योगिक सहकारिता

- 5 सट्टाकार चानो कारखानों के सिवाय औद्योगिक सेंक्टर में सहकारिता।

III उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

6 सभी उद्योगों का योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता, जिनमें किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते, परन्तु जिनमें डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाद्य), नाश्ते के आहार, बिस्कुट मिष्ठान (जिसके अन्तर्गत कोको ससाधन और चाकलेट बनाना भी आता है), माल्टसार पृथक्कृत प्रोटान, उच्च प्रोटान आहार, स्तन्य-त्याग-आहार, और उत्सारित (एक्सट्रडेड) खाद्य उत्पाद (जिसके अन्तर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार आते हैं) से संबद्ध उद्योग शामिल हैं ।

7 भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 और तदधीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन/केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।

8 विस्फोटक—विस्फोटक अधिनियम, 1884 और तदधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 का नहीं ।

9 केबिल ।

10 हल्के इत्र नियरो उद्योग (उदाहरणार्थ सिलई की मशीनें, टाइपराइटर, तोलने का मशीन, बाइसिकिल, आदि) ।

11 हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ प्लाइवुड, लेखन सामग्री, दियसलाई, सिगरेट, आदि) ।

12 हल्के विद्युत-इंजीनियरी उद्योग ।

13 कच्ची फ़िल्में ।

14 हर्ड बोर्ड ।

15 कागज और अखबारों का कागज ।

16 टायर और ट्यूब ।

17 नमक ।

18 सेमेट ।

19 आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पूना ।

20 इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इस्टिड्यूट, बंगलूर ।

21 सेमेट रिसर्च इस्टिड्यूट आफ इंडियन, फरोदाबाद, हरियाणा ।

22 इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

23 तकनीकी विकास इनके अन्तर्गत तकनीकी विकास का महानिदेशालय है ।

IV लघु उद्योग

24 लघु उद्योगों के विकास का समन्वय

(i) लघु उद्योग बोर्ड ।

(ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।

(iii) उन स्थानों में जहाँ परिवर्तन पकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का भार सहेन्द्रण है नियोजन का व्यवस्था करने के लिए नये उद्योगों का स्थापन ।

25 ग्रामीण और कुटीर उद्योग ।

26 ग्रामीण उद्योगीकरण से संबंधित मामलों का समन्वय ।

27 साबुन और अपमार्जक ।

V पेटेंट और डिजाइन, आदि

28 अन्तर्राष्ट्रीय उत्पदों और वच्चा सामग्री का मानकीकरण ।

29 डिजाइन अधिनियम, 1911 ।

30 पेटेंट अधिनियम, 1970

VI सामग्री योजना

31 सेक्टरों, उद्योगों और बड़े एकाओं द्वारा उत्पदों के विशिष्ट समूहों और उपलब्ध क्षमता में की गई कच्चे माल की मांगों का समन्वित निर्धारण ।

32 आयातों द्वारा प्रतिस्थापन को सम्भाव्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल का उपलब्धता का निर्धारण ।

33 तालिकाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण ।

34 कच्चे माल के आवंटन के लिए सिद्धांतों पूर्विकताओं और प्रक्रियाओं का अवधारण ।

35 नारियल जटा उद्योग ।

36 कपूर बोर्ड ।

37 सामग्री योजना से सम्बद्ध अन्य मामले ।

अन्य विषय

38 इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी सलग या अधीनस्थ कार्यालय व अन्य संगठन ।

39 ऐसी परियोजनाओं के सिवाय जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट आवंटित हैं, इन सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अन्तर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएं ।

40 सभी पब्लिक सेक्टर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर प्रभाव डालने वाली अव्यक्त प्रकृति की साधारण नीति के मामलों का समन्वय ।

41 समस्त उद्योग के लिए भारी इंजीनियरी उपस्कर का विनिर्माण ।

42 भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग ।

43 मशीनरी उद्योग जिसके अन्तर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण आते हैं ।

44 आटो उद्योग जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाला उपस्कर आते हैं ।

45 सभी प्रकार के डीजल इंजन ।

ख कम्पनी कार्य विभाग

1 कम्पनी अधिनियम, 1956 का प्रशासन ।

2 कम्पनी (राष्ट्रीय निधिया को दान) अधिनियम, 1951 का प्रशासन ।

3 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का प्रशासन ।

1. लेखा-वृत्ति (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949) लागू और सहाय लेखा वृत्ति (लागत और सहाय लेखापाल अधिनियम, 1959), इन्दी सचिवत्व वृत्ति कपनी सचिव अधिनियम, 1980।

5. कम्पनिया से सम्बंधित आकषी का संग्रहण ।

6. गारदार विधि क संघ में विधान और भारतीय नागदारी अधिनियम, 1932 के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कतिपय क्षेत्रों का निर्वाह ।

(अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है) ।

7. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ।

8. उपर्युक्त मन्त्रों में से किसी के बारे में केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से विहित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व ।

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

1. ओषधियों तथा फार्मास्यूटिकल्स ।

2. कोटनार्थो [कोटनार्थो अधिनियम 1968 (1968 का 46) प्रशासन के अतिरिक्त]

3. शोरा-वितरण और मूल्य निर्धारण ।

4. एलकोहल ओबोर्गिक और पेय, भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित ।

5. रजक-द्रव्य और रजक-मध्यक ।

6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य मंत्रालय विभाग को विनिर्दिष्टता आबंटित नहीं किए गए हैं ।

7. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना विकास तथा सहायता ।

8. इस विभाग के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी विहित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

9. इस विभाग में सम्मिलित विषयों से सम्बंधित सरकारी क्षेत्रों को पोषणाए उन परियोजनाओं को छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टता आबंटित की गई है ।

10. जननगोल पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।

11. भोपाल गैस विमिश्रिका—तत्संबंधी विशेष विधियाँ ।

12. पेट्रो-रसायन ।

13. सेलूलोज रहित सिलिस्ट फाइबर (नायलान, पोलियेस्टर, एक्रि-डिआदि) के उत्पादन से सम्बंधित उद्योग ।

14. सिलिस्ट रबड़ ।

15. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक का इस्तेमाल शामिल हैं ।

16. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों का योजना, विकास तथा सहायता ।

17. उपर्युक्त मामलों से सम्बंधित सरकारी क्षेत्रों के एकक ।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बंधित सभी संलग्न या अन्य कार्यालय या अन्य संगठन ।

भारत उद्यम विभाग

1. सरकारों उद्यम ब्यूरो जिलमें औद्योगिक प्रबन्ध पूल में सम्मिलित

2. दि हैर. इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लि., रांचा ।

3. दि माइनिंग एंड मिलायड मग नदी कारपोरेशन लि., दुर्गापुर ।

4. दि विवेणो स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद ।

5. दि तुगलक स्टाट प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लि. ।

6. दि भारत हैवी प्लेटन एण्ड इंस्ट्रुमेंट लि. ।

7. दि इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि. ।

8. भारत प्रेस एंड वाटवर्क लि. ।

9. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. ।

10. भारत प्रोसेस एंड मेकैनिक्कल इन्जिनियर्स लि. ।

11. भारत पम्प एंड कम्प्रेसर्स लि. ।

12. भारत बैंगन एंड इन्जिनियरिंग क लि. ।

13. ब्रैथवेट एंड क लि. ।

14. बर्न स्टैंडर्ड क लि. ।

15. एच.एम.टी. बियरिंग्स लि. ।

16. एच.एम.टी. लि. ।

17. एच.एम.टी. इंटरनेशनल लि. ।

18. जेसप एंड क. लि. ।

19. दि लैंगन जूट मशीनरी क. लि. ।

20. मासुति उद्योग लि. ।

21. रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लि. ।

22. स्कूटर्स इंडिया लि. ।

23. ववेड (इंडिया) लि. ।

24. ब्रैथवेट, बर्न एंड जेसप कस्ट्रक्शन लि. ।

25. हुगली डॉक एंड पोर्ट इन्जिनियर्स लि. ।

26. एण्ड्रयूले एंड क. लि. ।

27. बनारहाट टी कं. लि. ।

28. बासमतिया टी कं. लि. ।

29. भारत लैटर कारपोरेशन लि. ।

30. भारत आपपेलिमक ग्लास लि. ।

31. सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ।

32. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ।

33. हिन्दुस्तान केबल्स लि. ।

34. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. ।

35. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैग्नेटिक रेकॉर्डिंग कं. लि. ।

36. हिन्दुस्तान साइड्स लि. ।

37. हुगली प्रिंटिंग कं. लि. ।

38. हुलगुरी टी कं. लि. ।

39. इस्ट्रुमेंटेशन लि. ।

40. दि माइया नैशनल पेपर मिल्स लि. ।

41. दि मिम टी कं. लि. ।

42. मुरकुलानी (असम) टी कं. लि. ।

43. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि. ।

44. नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ।

45. दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. ।

46. नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लि. ।

47. नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल लि. ।
48. दि नेशनल स्माल इंडस्ट्रिज कार्पोरेशन लि. ।
49. रायगढ़ टा. कं. लि. ।
50. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इस्ट्रुमेंट्स लि. ।
51. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. ।
52. दामोदर सॉफ्ट एंड स्लैग लि. ।
53. सांभर साल्ट्स लि. ।
54. टैनरो एंड फुटवॉयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. ।
55. टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

I रेडियो :

1. (प्रसारण अनुज्ञप्तियां देने के सिवाय) आकाशवाणी से संबंधित सब कार्य जिसके अन्तर्गत अन्तर्देशीय कार्यक्रमों का समाचार सेवाएं विदेशों और समुद्रपारस्थ भारत में के लिए कार्यक्रम, रेडियो जनरल, प्रसारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान, विदेशी प्रसारणों को मॉनिटर करना, कार्यक्रम विनिमय और अनुलिपिकरण सेवाएं, टेलीविजन, सामुदायिक श्रवण स्कीम के अर्धन राज्य सरकारों को सामुदायिक रेडियो रिसीवर सेटों का प्रदान आदि है :

2. संघ भर में सर्वत्र प्रसारण का विकास, रेडियो स्टेशनों/ट्रांसमिटर्स का प्रतिष्ठापन और उनको बनाए रखना ।

II फिल्म :

3. (1) प्रदर्शन के और इतर प्रयोग के लिए फीचर-लम्बाई का और लघु फिल्मों का आयात;

(2) फीचर लम्बाई को और लघु भारतीय फिल्मों का निर्यात;

(3) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित चलचित्र-फिल्म (अनुद्भासित) और अन्य माल का आयात और वितरण ।

4. (1) अन्तर्देशीय और विदेश प्रचार के लिए वृत्तचित्रों और समाचार चित्रों तथा अन्य फिल्मों और फिल्मों के टुकड़ों का उत्पादन और वितरण;

(2) फिल्मों के लिए वितरण और प्रदर्शन श्रृंखलाओं का सृजन ।

5. फिल्म उद्योग से संबंधित विकासकारों और संवर्धक क्रियाएं, जिनमें शिक्षण और अनुसंधान भी हैं ।

6. (1) संघ सूच. को प्रविष्टि 60 अर्थात्, "प्रदर्शन के लिए चलचित्रों की मंजूरी" के अधिन विधायन ।

(2) चलचित्र अधिनियम, 1952 का प्रशासन जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में चलचित्र यंत्र द्वारा होने वाला प्रदर्शन शामिल है, परन्तु उसमें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्रों का केन्द्रिय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा परीक्षण और प्रमाणन शामिल नहीं है ।

7. भारत में निहित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान करना ।

8. बाल फिल्म सोसाइटी को अनुदान ।

9. फिल्म जांच समिति का सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

10. राष्ट्रीय फिल्म नियम और भारतीय चलचित्र नियमित नियम (इम्पेक)

III विज्ञापन और दृश्य प्रचार :

11. प्रेस, पोस्टरों, फोल्डरों, कैलेंडरों, ग्लाउसों, पत्रकों, विज्ञापन फलकों, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से भारत सरकार के सभी

संप्रदर्शी विज्ञापनों का उत्पादन और प्रकाशनार्थ दिया जाना, वर्गीकृत विज्ञापनों का भारत सरकार की ओर से प्रकाशनार्थ दिया जाना भी ।

12. माध्यम सूचियों की तैयारी ।

IV प्रेस :

13. भारत सरकार की नीतियों और उसके क्रियाकलाप का प्रेस के माध्यम से निरूपण और निर्वचन ।

14. प्रेस संबंधी सूचना समस्याओं पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में यथाप्रतिबिम्बित लोकमत को प्रमुख धाराओं की सरकार को जानकारी देते रहना और सरकार और प्रेस के बीच संपर्क ।

15. सशस्त्र बलों के प्रति और उनके लिए प्रचार ।

16. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 से 96 तक के प्रशासन को छोड़कर प्रेस के साथ सरकार के संबंधों का साधारण संचालन ।

17. प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 का समाचार-पत्रों से संबंध प्रशासन ।

18. समाचार पत्र (कीमत तथा पृष्ठ) अधिनियम, 1958 का प्रशासन

19. प्रेस आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

V प्रकाशन :

20. देश की तथा विदेशों की साधारण जनता को भारत के संबंध में अद्यतन तथा ठीक-ठीक जानकारी कराने की दृष्टि से अन्तर्देशीय तथा विदेश प्रचार के लिए राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा जनरलों को तैयार करना, विक्रय तथा वितरण ।

VI अनुसंधान और निर्देश :

21. (1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम एककों का उस सामग्री के संग्रहण, संकलन और तैयारी में सहायता करना जिसमें प्रकाशित कृतियों आदि में अनुसंधान करना अन्तर्गुह्य है; और

(2) मंत्रालय के माध्यम एककों के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का सार-संग्रह तैयार करना और सामयिक तथा अन्य विषयों पर मार्गदर्शी तथा पृष्ठभूमि-टिप्पणी तैयार करना ।

22. पंचवर्षीय योजना के लिए प्रचार ।

23. गायक और वादक दोनों प्रकार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों को, नर्तक-नर्तकियों को और नाटककारों को जिन्होंने आकाशवाणी और इस मंत्रालय के अन्य एककों की सफलता में सारभूत योगदान दिया है, या निधेनावस्था वाले उनके उत्तरज-विशों को वित्तीय सहायता ।

24. संलग्न और अधोनस्थ संगठन :-

(क) आकाशवाणी ।

(ख) फिल्म प्रभाग ।

(ग) पंचवर्षीय योजना प्रचार एकक ।

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ।

(ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो ।

(च) प्रकाशन प्रभाग ।

(छ) अनुसंधान और निर्देशन प्रभाग ।

(ज) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय ।

25. एशियन ब्राडकास्टिंग यूनियन, कामनवेल्थ ब्राडकास्टिंग एसोसिएशन और नान-अलाइन्ड न्यूज एजेंसी पूल से संबंधित सभी मामलों ।

अंश अन्तराल

भाग I—संघ विषय

1. सघ रेलों की वाहन मजदूरी संदाय, व्यवसाय-विवाद, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और बालकों के नियोजन का विनियमन।
2. पत्तन के बारे में—पत्तन श्रम से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों का विनियमन।
3. खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।

भाग II—समवर्ती विषय

4. कारखाने।
5. श्रम कल्याण—श्रम की औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि संबंधी शक्तों, भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन, उपदान, नियोजन का दायित्व और कर्मकार प्रतिकार, स्वास्थ्य और रोग बीमा जिसमें अशक्तता पेंशन, श्रम पेंशन, कारखानों में कार्य दशाओं में सुधार सम्मिलित हैं। औद्योगिक उपक्रमों में कैंटीन।
6. बेकारी बीमा।
7. व्यवसाय संघ, उद्योग और श्रम-विवाद।
8. श्रम संबंधी आंकड़े।
9. ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के सिवाय रोजगार और बेरोजगारी।
10. शिल्पकारों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

भाग III—हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली के संघ एम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कार्य।

11. उपर्युक्त भाग II में वर्णित मदें।

भाग IV—उपर्युक्त भाग I, II और III में वर्णित मामलों में से श्रम के संबंध में आनुवंशिक कार्य।

12. अन्य देशों से की गई सधियों और करारों का कार्यान्वयन।
13. विधियों के विरुद्ध अपराध।
14. जांच और आंकड़े।
15. फीस, किन्तु वे फीस नहीं जो किसी न्यायालय में ली जाती हैं।
16. (उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) सब न्यायालयों की शक्तियाँ और अधिकारिता।

भाग V—प्रकीर्ण कार्य

17. रोजगार कार्यालय।
18. भारत में और विदेशों में दोनों जगह फोरम और पर्यवेक्षक के रूप पर शिक्षकों, शिल्पकारों, तकनीकज्ञों के प्रशिक्षण के लिए स्कीम, प्रशिक्षण।
19. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
20. त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन।
21. युद्ध क्षति (प्रतिकार बीमा) अधिनियम, 1943 और स्कीम।
22. कोयला खानों से भिन्न खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियों का और खान और अन्न खान कल्याण के मुख्य विभागों के संगठन का प्रशासन।
23. भारतीय पत्तन श्रम अधिनियम, 1931 का प्रशासन और बनाए विनियम और पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन निर्मित पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण) स्कीम।

24. चाय जिला उत्पदासी श्रमिक अधिनियम और उत्पदासी श्रम नियंत्रक संगठन का प्रशासन।

25. उत्पदास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अन्तर्गत भारत में विदेशों को होने वाले सभी उत्पदास और उत्पदासियों की वापसी।

26. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रशासन।

27. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) का प्रशासन।

28. केन्द्रीय सन्न उपक्रमों में श्रम विषयक विधियों का प्रशासन।

29. श्रम संबंधी आंकड़े, श्रम ब्यूरो के निदेशक का संगठन।

30. मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों, केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और प्रशासन।

31. कारखानों के मुख्य सलाहकार का संगठन जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान, उत्पादित और उद्योग के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रादेशिक संग्रहालय हैं।

32. बागान श्रमिक और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) का प्रशासन।

33. सरकारी श्रम अधिकारियों की भर्ती, तैनाती, अन्तरण और प्रशिक्षण।

34. श्रम-जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 का प्रशासन।

35. कर्मकारों की शिक्षा संबंधी स्कीम।

36. प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के सम्बन्ध में स्कीम।

37. उद्योग में अनुशासन।

38. अलग-अलग उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्डों का गठन।

39. मोटर परिवहन कर्मकारों के काम की दशाओं का अधिनियमन।

40. देश में श्रम विषयक विधियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन।

विधि और न्याय मंत्रालय

क. विधि कार्य विभाग

1. विधिक मामलों पर मंत्रालयों को सलाह, जिसके अन्तर्गत विधियों का निर्वहन, विधिक कार्यवाहियाँ और हस्तान्तरण लेखन आते हैं।

2. भारत का महाध्यायवादी, भारत का महासालिसिटर तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, राज्यों के विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं में भारत सरकार के मंत्रालय अशामोगी हैं।

3. केन्द्रीय सरकार की ओर से और केन्द्रीय अधिकरण स्कीम में भाग लेने वाले राज्यों की सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मामलों का संचालन।

4. सिविल वादों में सम्मनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन, भरण-योपण आदेशों के प्रवर्तन और भारत में निर्वसीयत मरने वाले विदेशियों की सम्पदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ व्यक्तिकारी व्यवस्था।

5. सिविल के अनुच्छेद 299 (i) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से सिविल आदेशों और सम्पत्ति-संबंधी हस्तान्तरण पत्रों के निष्पादन के लिए अधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना और केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में वाद-पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने के

लिए और उम्मीद जताते करने के लिए अधिकाधिक ता प्राधिकृत किया जाना ।

6 भारतीय विधि सेवा ।

7 विविध विधि के मामलों में विदेशों के साथ सविधान और करार ।

8 विधि आयात ।

9 विधिक दृष्टि ।

10 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का परिवर्धन और उसको अनुपूरक शक्तियाँ प्रदत्त करना, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति, भारत के सविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय की निर्देश ।

11 उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति ।

12 नोटरी अधिनियम, 1952 का प्रशसन ।

13 नावधिकरण विषयक अधिकारिता ।

14 आयकर अपील अधिकरण ।

15 विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड ।

16 निधनों के लिए विधिक सहायता ।

ख विधायी विभाग

1 विधेयको का प्रारूपण, जिसके अन्तर्गत प्रवर समितियों में प्रात्य-कारों का कार्य है, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण और प्रख्यापन, जब भी अपेक्षित हो राज्य अधिनियमों की राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमिति, कानूनी नियमों और आदेशों की सवीक्षा ।

2 सविधान आदेश सविधान (संशोधन) अधिनियमों को प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचनाएँ ।

3 (क) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन;

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5(1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उप विधियों के प्राधिकृत हिन्दी अनुवादों का प्रकाशन ।

4 अन्रिखित केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का, साधारण कानूनी नियमों और आदेशों का सकलन और प्रकाशन तथा अन्य समरूप प्रकाशन ।

5 संसद राज्यों के विधान मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग ।

6 यथासंभव, सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए मानक विधि शब्दावली तैयार करना तथा उसका प्रकाशन ।

7 सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाए गए सभी विनियमों और ऐसे अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना ।

8 केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों तथा उनके द्वारा बनाए गए विनियमों का राज्या की राजभाषाओं में अनुवाद करने और सभी राज्य अधिनियमों और अध्यादेशों का, यदि ऐसे अधिनियम अथवा अध्यादेश हिन्दी से भिन्न किसी अन्य भाषा में हो, हिन्दी अनुवाद करने की व्यवस्था करना ।

9 विधि-पुस्तकों और विधि-पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन ।

निम्नलिखित विषय जो भारत के सविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत) —

10 विवाह और विवाह विच्छेद, विरु और अन्वय क वसक सम्पत्ति, इच्छापत्र होना और उत्तराधिकार अधिभक्त पुत्र और विधवा

11 कृषि भूमि से मिश्र सम्पत्ति का हस्तान्तरण, विधवा को दस्तावेजों का पंजीयन ।

12 सन्निदाये, किन्तु इनके अन्तर्गत कृषि भूमि संबंधी सविधान के भागों हैं ।

13 अभियोज्य दोष ।

14 विवाला और शाध क्षमता ।

15 न्याय और न्यासी, महाप्रशासक और शासकाय न्यासी ।

16 साक्ष्य और शपथें ।

17 व्यवहार प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत परिसीमा और माध्यस्थ हैं ।

18 पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिक सत्सायें ।

अन्य विषय

19 वक्क अधिनियम, 1954 ।

20 निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अधिनियम सम्पत्तियों के बाबत कार्य ।

21 दरगाह क्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 का प्रशासन ।

ग. न्याय विभाग

1 भारत के मुख्य न्यायाधिरति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिरतों का नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना, उनके वेतन अनुपस्थिति छुट्ट विषयक अधिकार (जिसके अन्तर्गत छुट्ट के भत्ते हैं) पेंशनें और यात्रा भत्ते ।

2 राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिरतियों और न्यायाधिरतों का नियुक्ति, पदत्याग और उनका हटाया जाना, आदि, उनके वेतन अनुपस्थिति छुट्ट विषयक अधिकार (जिसके अन्तर्गत छुट्ट भत्ते हैं) पेंशनें और यात्रा भत्ते ।

3 संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों का नियुक्ति ।

4 उच्चतम न्यायालय का गठन और संगठन (जिसके अन्तर्गत अधिकारिता और शक्तियाँ नहीं आती किन्तु ऐसे न्यायालय का अवग्रह आता है) और उसमें ल जाने वाला फीस ।

5 उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों से सम्बद्ध उपबन्धों के सिवाय इन न्यायालयों का गठन और संगठन ।

6 संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और संगठन तथा ऐसे न्यायालयों में ल जाने वाल फीस ।

7 संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय फस और स्टाम्प शुल्क ।

8 अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का सृजन ।

9 संघ राज्य क्षेत्रों के जिला जजों तथा वहाँ के उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों को सेवा क शर्तें ।

10 किस संघ राज्य क्षेत्र में किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता का विस्तार या किम संघ राज्य क्षेत्र का किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता से अवर्जन ।

संसद य कार्य और पर्यटन मन्त्रालय

क संसद य कार्य विभाग

1 संसद के दोनों सदनों के ग्राहवान और सभासमान को तारीखें लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण ।

59 GI/85-4

(च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधकगण के स्तरों के लिए पुनर्रचर्चा तथा विशेष पाठ्यक्रम।

III. मनकता और अनुशासन

20 (क) अपराध निवारण अधिनियम 1947; केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जिसके अन्तर्गत विधिक प्रभाग, तकनीक प्रभाग, रीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग आते हैं); खाद्य संबंध अपराधों के शाखा; और आर्थिक अपराध शाखा।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त उस दशा में मंजूरी देना जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसा मंजूरी केन्द्रिय सरकार द्वारा दी जाए।

टिप्पणी.—किसी ऐसे अपराध के लिये जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा न किया गया हो, किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त मंजूरी प्रशासन विभाग द्वारा उस दशा में दी जायेगी जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसा मंजूरी केन्द्रिय सरकार द्वारा दी जाये।

(ग) केन्द्रीय मनकता आयोग।

(घ) लोक सेवकों के मध्य मनकता और अनुशासन संबंधी सभी नीति विषयक मामले।

(ङ) मंद गदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध।

IV. सेवा की शर्तें

21. रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के विषय, अखिल भारतीय और मंत्र लोक सेवाओं संबंधी साधारण प्रश्न (उनसे निम्न जिनका विन में संबंध है), जिनमें आचरण नियम भी आते हैं।

22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (रेल विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन-कर्मचारियों तथा रक्षा अनुदान तथा विकास विभाग के नियंत्रण के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर, की सेवा शर्तें, जो उनमें निम्न हैं जिनका विन में संबंध है और जिनका विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक उनसे सेवा के साधारण शर्तों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

23 (क) मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित (लेकिन इसमें पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं आते हैं) सभी सेवा नियमों का निम्नलिखित को छोड़कर प्रशासन:—

(i) कर्मचारियों के वेतन हांचे के पुनरीक्षणों से संबंधित प्रस्ताव;

(ii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के लिये प्रस्ताव;

(iii) वेतन आयोग की नियुक्ति सिफारिशों का प्रसंकरण और उनका कार्य-व्यय;

(iv) महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यावा भत्ते;

(v) सेवा शर्तों अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती विनियमितायों वाले अनुपमो हितवाचों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा;

(vi) पदचरितः विनियम प्रकृति के सेवा नियमों में संगोष्ठियों से संबंधित मामले।

(ख) सेवा-शर्तों और महत्वपूर्ण आवर्ती विनियमितायों वाले अनुपमो हितवाचों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के लिये प्रस्तावों का उपक्रमण।

(ग) खंड (क) की गद (vi) में उल्लिखित प्रमुखतः वित्तीय प्राकृति के सेवा नियमों सहित सेवा नियमों में संगोष्ठियों से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना।

(घ) दीर्घावधि विनियम निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा नियमों या वित्त मंत्रालय के परामर्श से नियमित और उदात्तरण।

24. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का अनुदान।

25. रेल कर्मचारियों में निम्न सिविल कर्मचारियों के लिये दृष्टी यात्रा सुविधाएं।

26. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949।

27. रेल विभाग के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के विषय, ऐसे सेवकों की छुट्टी और प्रत्यावर्तन संबंधी साधारण नीति।

28. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना) नियमों का प्रशासन।

29. केन्द्रीय सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों में वर्ग IV तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिये बर्धिया।

30. भारत सरकार के कार्यालयों के लिये काम के घंटे और अवकाश-दिन।

31. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन जिनमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्टः प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों।

32. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या या श्रेणी में अथवा उसकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों से हो जिनमें वित्तीय प्रश्न निहित हों।

33. सरकारी सेवकों द्वारा किये गये विधिक व्यर्थों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति।

34. पदेन सचिवालय हैमियन प्रदान करने के लिये प्रस्थापनायें।

35. सिविल पदों पर व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां।

36. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ।

V. ज्येष्ठ और मध्यवर्गीय प्रबंधन

37. ज्येष्ठ प्रबंधन (अर्थात् सयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्षों) के सभी पहलू, जिनके अन्तर्गत उनके लिये वार्मियों की अभिवृद्धि भी है।

38. (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी।

(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति।

(ग) केन्द्रीय स्थापना बोर्ड।

(घ) मध्यम वर्गीय प्रबंधक गण (निदेशको उप सचिवों और अवसर सचिवों तथा उनके समकक्षों) के भविष्य का विकास।

VI. सरकार-कर्मचारियों संबंध जिनके अंतर्गत कर्मचारी-वृन्द की शिकायतें और कल्याण भी है।

39. (क) भारत सरकार के आर्थिक और गैर-आर्थिक कर्मचारियों के सेवा मान्य।

(ख) सयुक्त परामर्शदाता तंत्र; कामिक और प्रशिक्षण विभाग के लिये विभागीय परिपत्र।

(ग) कर्मचारीवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिए तंत्र।

(घ) कर्मचारीवृन्द कल्याण जिसके अंतर्गत खेल-कूद, सामुदायिक क्रियाकलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैम्पिंग, महत्वासे स्टोर आदि है।

(ङ) सरकार-कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले जिनके इस मंत्रालय के संबंधमें किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत प्रावधान नहीं है।

VII. मंत्र लोक सेवा आयोग

40. मंत्र लोक सेवा आयोग।

राष्ट्रीय याजना क विषय की वाबत ममद के प्रति उत्तरदायित्व।

ख. गान्धिकी विभाग

- 1 आरुडा सग्रह क मानक और प्रमाण तथा पद्धतियां।
- 2 कन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।
- 3 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण।
- 4 भारतीय सांख्यिकी संस्थान।
- 5 संगणक (कंप्यूटर) केन्द्र।

6 भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबन्धन के केन्द्रीय फ्रेमवर्क और उस सेवा के प्रशिक्षण, भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से सम्बन्धित सभी मामल।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

- 1 परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का परीक्षण (मानकीकरण) करना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

- 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मन्त्र म नीति विषयक वस्तुओं और मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना।

- 2 मन्त्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति (एस ए सी सी)।

- 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का विकास।

- 4 भविष्य विज्ञान।

- 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों का समन्वय जिनमें अनेक संस्थाओं और विभागों की रुचि हो और जिनमें उनकी क्षमता हो।

- 6 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षणों, अनुसंधानों, डिजाइन और विकास, जहाँ वहाँ आवश्यक हो, के कार्यों को हाथ में लेना या वित्तीय तौर पर उन्हें समर्थन देना।

- 7 वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों और निवासियों की सहायता और सहायता अनुदान देना।

- 8 अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं —

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहकारिता करारों के मन्त्र में बातचीत और उनका कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रियाकलापों के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं की जिम्मेदारी, और

(ख) विदेशों में वैज्ञानिक महारिक्तियों (अतिथियों) की नियुक्ति।

टिप्पण इन कृत्यों का पालन विदेश मंत्रालय के निकट सहायक से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

- 9 वैज्ञानिक सर्वेक्षण —

(1) भारतीय सर्वेक्षण,

(2) नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन।

- 10 भारतीय मासम विज्ञान विभाग।

- 11 (1) खगोल भौतिकी संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ ऐस्ट्रो फिजिक्स)

(11) भुम्बकत्व संस्थान।

(111) इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मॉटेरालोजी।

- 12 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्र राष्ट्रीय परिषद।

- 13 राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति विकास बांड।

- 14 नेशनल बायोटेक्निकल बोर्ड।

15 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाले मामल, उदाहरण के तौर पर वित्त, न्याय और मानव नागरिकता तथा व्यापार।

- 16 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रबन्ध सूचना प्रणाली और तन्त्रबद्धी समन्वय।

- 17 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन का विकास हेतु अन्तःसंस्थागत अन्तर विभागीय समन्वय संबंधी मामल।

- 18 देशी प्रौद्योगिकी से संबंधित मामल खास तौर से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग के अर्धन प्रौद्योगिकी से भिन्न वे सामल जिनमें ऐसी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण निहित हो।

- 19 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि तथा राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के निमित्त उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय।

ख. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग।

- 1 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद में संबंधित सभी मामल।

- 2 राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से संबंधित सभी मामल।

- 3 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि से संबंधित सभी मामल।

- 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (एन आई एम. एस. ए. टी.)

- 5 अनुसंधान और विकास इकाइयों का पंजीकरण और उन्हें मान्यता प्रदान करना।

- 6 यू. एन. सी. टी. ए. डी. एड. डब्ल्यू. आई. पी. ओ. से संबंधित मामल।

- 7 विदेशी सहायता के बारे में नेशनल रजिस्टर।

- 8 भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों की अस्थायी बस्तों के लिए एक पूल के सृजन से संबंधित मामल।

- 9 नेशनल रजिस्टर ऑफ साइंटिफिक मैनपावर।

इस्पात और खान मंत्रालय

(क) इस्पात विभाग

- 1 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में इस्पात मयंत्र, रिरालिग उद्योग तथा लौह-मिश्रित धातुओं, जिनके अन्तर्गत सभी भारी विकास आता है।

- 2 पब्लिक सेक्टर में लौह खाना का विकास।

- 3 अन्य अयस्क खाना तथा कोयला प्रक्षालितों का विकास और इस्पात मयंत्रों के लिए खनिज का प्रसम्पन।

- 4 लाहा तथा इस्पात तथा लाहा मिश्रित धातुओं का उत्पादन, वितरण, कामते, आयात और निर्यात।

- 5 सभी लाहा और इस्पात उद्योगों का योजना, विकास और नियंत्रण और उनकी सहायता।

- 6 इस्पात उद्योग में प्रयुक्त लाह अयस्क, मैंगन अयस्क, चुना, सिल मेनाइट, वायनाइट, और अन्य खनिजों और अन्य मिश्रित धातुओं का उत्पादन, प्रदाय, कामते लगाना और वितरण, जिसमें खनिजों के अनुदान या उद्यम संबंधित बात नहीं है।

- 7 स्टील अयारिटा ऑफ इंडिया लिमिटेड और उनकी समस्तियों (कम्पनियां)।

- 8 निम्नलिखित उपक्रमों से संबंधित मामल अर्थात् —

(1) दि मैयूर ऑइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड।

(2) दि बानाना आर्म (इंडिया) लिमिटेड।

(3) दि मंगन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

(4) दि मैयूर स्टील ट्रेडिंग एंजियरिंग।

- 9 जा बिमा अन्य विभाग का विनिर्दिष्टता आवंटित किए गए हैं।

उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन अन्य पब्लिक सेक्टर उद्यम या उपक्रम।

10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी से संबंधित सत्ता, मालिक या अधिनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

ख. खान विभाग

1. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य संघ विधियों के अधीन खानों तथा कोयले और लिग्नाइट तथा भण्डार्य वानू से भिन्न, खनिजों के विकास का विनियमन, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न और इनके बारे में अनुषंगी कार्य हैं।

2. सभी ऐम्स, अन्य धातुयें और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य विभाग को आवंटित नहीं हैं, जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, मोना, हीरे, मसा और निकल।

3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।

4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण।

5. भारतीय खान व्यूरो।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधिनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

7. दि सिस्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड।

8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट आवंटित किए गए हैं, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधिन पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपक्रम।

9. सैटलजिकल ग्रेड सिलिकॉन।

परिवहन मंत्रालय

क. रेल विभाग

1. सरकारी रेलें—सब विषय, जिनके अन्तर्गत वे विषय भी हैं, जो रेल राजस्व और व्यय से संबंधित हैं किन्तु जिन में रेल निरक्षणालय और रेल लेखा परीक्षा नहीं आते हैं।

2. गैर-सरकारी रेलें—वहां तक वे विषय जहां तक उनके लिए भारतीय रेल अधिनियम में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किसी अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षितता, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ों, इत्यादि विषयक विनियमों में, यह उपबन्ध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) करेगा।

3. रेल सम्पत्ति के भ्रूषण से संबंधित अपराधों, सरकारी रेलों और गैर सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों से भिन्न, की बाबत संसदीय प्रश्न।

ख. नागर विमानन विभाग

1. वायुयान और विमान नौचालन; हवाई अड्डा की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, विमान नौचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय, विनियमन और संगठन।

2. वायुयान की सुरक्षा के लिए बैकन तथा अन्य व्यवस्थाएं।

3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन।

4. इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन (आई.सी.ए.ओ.)।

5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.)।

6. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी.ए.टी.सी.)।

7. कामनवेल्थ गेडवाइजरी एरोनाटिकल रिसर्च काउंसिल।

8. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम।

9. भारतीय टोटल निगम।

10. मुख्य आयुक्त रेल सुरक्षा।

11. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण।

12. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के बिन्दु अपराध।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फर्में किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ला जाने वाले फर्में नहीं आते हैं।

15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन।

ग. जल भू-नल परिवहन विभाग

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची-I के अंतर्गत हैं :

1. समुद्रीय नौवहन और नौपरिवहन, वाणिज्यिक समुद्री बड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था।

2. दीपसम्भ और दीपपोत।

3. महापत्तन अर्थात् कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, और कांडला के पत्तन।

4. मोटर गाड़ियों का अनिवार्य बंसा।

5. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का प्रशासन।

6. राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधिन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

7. नौवहन और नौपरिवहन जिनके अंतर्गत ऐसे अन्तर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है जो संसद द्वारा विधि द्वारा यत्नोदित, जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम।

8. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग।

9. मत्स्य ग्रहण नौका उद्योग।

10. प्लवमान-यान उद्योग।

II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

11. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग।

12. नगरपालिका म.माओं के अंतर ट्रांसवे।

13. अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात।

14. मोटर यान अधिनियम, 1939 का प्रशासन और मोटर यानों पर कराधान।

15. यत्नोदित गाड़ियों से भिन्न गाड़ियां।

III. अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

16. मुख्यभूमि और द्वीपों के बीच नौवहन सेवाओं का संगठन और अनुरक्षण।

IV. अन्य विषय जो पूर्ववर्ती उप-शर्तों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं :

17. केन्द्रिय सड़क विधि।

18. सड़क सफाई से संबद्ध समन्वय और अनुमति।

19. केन्द्रिय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म जिनके अन्तर्गत निष्पत्ति तथा संविधान की कठ अनुसूची के पैरा 20 के

सत्यमेव जयते । अतः सत्यमेव जयते । अतः सत्यमेव जयते ।
अतः सत्यमेव जयते । अतः सत्यमेव जयते । अतः सत्यमेव जयते ।

13 भागत परतार व िण गयत गाम्भी अर मुद्रा, जिम्क
अनगत शमकिय प्रपञ्चन भी हे।

14 तगर विकास जिसके गन्तव्य तब प्रता नमई स्थिति तब
मुम्मी और आपकी हान की तब मा ह। इस क्षेत्र में गन्तव्य
महकालिना और तबनीकी महकालिना।

15 नगर और ग्राम यात्रता महानगरीय क्षेत्रों व विकास ग्राम यात्रता से सम्प्रधित मामल। इस क्षेत्र में अन्तर्गटीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

16 दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अजन, विनाम और व्यर्थ की स्कीम।

17 दिल्ली विहाम प्राधिमरण ।

18 दिल्ली का मास्टर प्लान दिल्ली मघ राज्य क्षेत्र म मास्टर प्लान तथा गन्दी वस्ती सपाई विषयक वाम का समन्वय।

19 स्वतंत्रता सेनानिया क सम्मान में भारको का परिनिर्माण ।

20 दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 का प्रशासन।

21 दिल्ली किगार नियन्त्रण अधिनियम 1958।

22 सरकारी वस्तिया का विकास ।

23 स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगम का (जिनके अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं वा (जिनके अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है), जिला बाडों का और अन्य स्थानाय स्वायत्त प्रशासना का (जिनके अन्तर्गत पंचायती राज सस्थाये नहीं आती हैं) गठन और उनकी शक्तिया ।

24 दिल्ली नगर निगम का जल-प्रदाय और मल-व्ययन उपक्रम।

25 जल प्रदाय, मल-व्ययन और जल निकास (ग्रामीण जल प्रदाय को छाडकर जा ग्रामीण विपिन विभाग को सीधा गया है)। पेय जल आपूर्ति आर सुफाई वा प्रबन्ध। इस क्षेत्र मे अनुरोधाय सहकारिता आर तकनीकी सहायता।

26 स्थानीय स्वायत्त प्रशासन की कन्द्रीय परिषद ।

27 दिल्ली में सरकारी भूमियाँ का आवंटन ।

28 इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

29. ऐसी परियाजनाया के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग का अर्पित आवृत्ति हैं, इस सूची में सम्मिलित विये विषयो के अन्तर्गत वाली पब्लिक सेक्टर परियाजनाये ।

30 शहरी भूमि (सीमा वन्दो और विनियमन) अधिनियम, 1976।

31 दिल्ली नगरीय कला आयोग, नगराय कला आयाग अधिनियम,
1973।

32 राजघाट समाधि स्मृति का प्रकाशन ।

जल ससाधन मन्त्रालय

1 लघु और आप्रानवार्तिक सिचाई वार्यों, नलकूपों, आर भोम जल
अनुपेण सहित सिचाई, कृषि प्रयाप्तता के लिए सिचाई वाढ नियन्त्रण,
जलपस्तता-खाद्य, जल निर्वार आर समुद्री कटाव रोष से मरधित सामान्य
नीति, तक्तीकी सहायता, अनसप्तान और सभा मामले ।

2 अन्तराज्यिक नदियाँ और नदी घाटियाँ का विनियमन और विकास।

३ नदी वार्ड अधिनियम, १९५६ का प्रकाशन।

4 अन्तर्गम्य जन विवाद अप्रतिग्रह 19 6 का प्रमाण।

12 मानव वस्ती, जिसमें यूनाइटेड किंगडम वस्तीजन फार ह्युमन

5. केन्द्रीय न्याय परिषद।

6. केन्द्रीय वाह नियंत्रण बोर्ड।

7. कल्याण बजट परियोजना।

8. विश्व जल मन्त्रि, 1960।

9. मिचौड़ी और वाह निर्देशन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग और सम्मेलन।

10. संघ राज्य क्षेत्रों में मिचौड़ी और वाह नियंत्रण स्वीमें।

11. जल और विद्युत परामर्श सेवा (ज. वि. प. से.)

कल्याण मंत्रालय

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत आते हैं :-

1. दान सहायता आपूर्तियों/वस्तुओं की शूलक-भूत प्राप्त हेतु भारत-संयुक्त राज्य, भारत, यूनाइटेड किंगडम, भारत-जर्मन, भारत-स्विट्जरलैंड और भारत-मरीडर करारों का मंचालन और उनके अन्तर्गत आने वाला आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

भाग-II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3 के अन्तर्गत आता है (केवल विधान की बाबत) :-

2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा उस सीमा के सिवाय जितना कि किसी अन्य विभाग को आवंटित कर दी गई हो।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अन्तर्गत आते हैं जहाँ तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं :-

3. निश्चय और अनियोज्य व्यक्तियों की सहायता और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा ने संबंधित उपाय, उस सीमा तक छोड़कर जहाँ तक वे किसी अन्य विभाग को आवंटित हैं।

भाग-IV

माध्याह्न और पारिवारिक :-

4. समाज कल्याण, मजदूर कल्याण योजना परियोजना कानून, अनु-संयोजन, मूल्यांकन, मापदंडों और प्रशिक्षण।

5. सामाजिक रक्षा में संबद्ध मामलों पर अन्य देशों के साथ अभिसमय।

6. अल्पसंख्यक वर्गों की, जिनमें अनाथ बालक सम्मिलित है, रक्षण और विकास के लिए सहायता और गैर-संस्थागत सेवाएँ तथा आवासन।

7. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बालकों की अपात निधि (यूनिसेफ)।

8. शारीरिक और मानसिक रूप से निश्चयों को शिक्षा प्रशिक्षण, पुनर्वास और कल्याण।

9. गैर-रिक्त रूप से निःशक्त और संरक्षितता लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान।

10. राष्ट्रीय अना केंद्र निम्न में केन्द्रीय तेल मंत्रालय, देहदातुन केन्द्र वगैर प्रशिक्षण केन्द्र तथा आंशिक रूप से बधिर बालकों का

विद्यालय, हैदराबाद, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा का माध्यम विभाजन, जहाँ शिक्षा और अन्य राष्ट्रीय संस्थान।

11. केन्द्रीय मानव कल्याण बोर्ड।

12. सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

13. विभाजित, किशोर, अवागमनी, आवर्तित और कोरपरेटिव फार अमेरिकन रिप्लिक एक्स्टेन्सिव के अन्य कार्यक्रम।

14. किशोर अभ्यासियों की परीक्षा।

15. सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अंग्रेजान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, सूचना का आदान-प्रदान, और तकनीकी मार्गदर्शन, जिनमें सुरक्षात्मक सेवाएँ सम्मिलित हैं।

16. नगरपाली मजदूरी सभी मामलों।

17. मारक द्रव्य व्यवस्थापन के शिक्षा और नगरपाली कल्याण से संबंधित पहलू।

18. इन विभाग को आवंटित विषयों में संबंधित पूर्ण और धार्मिक विकास।

19. इन विभाग को आवंटित विषयों के संदर्भ में स्वीडिश प्रयासों का उत्पन्न और विकास।

20. राष्ट्रीय नौक मजदूरी तथा जिम्मे विज्ञान संस्थान।

21. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान।

22. अतिरिक्त विज्ञान मैथिलीकरण कागजोपेन आर इंडिया कानपुर (अनिमको)

23. केसर (कोरपरेटिव फार अमेरिकन रेमिटेन्स टु यूरोप) की गतिविधियों का संयोजन।

24. सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संयोजन या अतिरिक्त कार्यालय अथवा अन्य संयोजन।

25. निम्नलिखित अधिनियम का प्रयोजन :-

(क) अन्तराष्ट्र परीक्षा अधिनियम, 1958; और

(ख) बालक अधिनियम, 1960।

26. अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, निम्नसूचित जातियाँ और अल्पसंख्यक जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, जिनके अन्तर्गत ऐसी जातियाँ, जनजातियाँ और वर्गों के विशेषाधिकारों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी हैं।

27. (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकार का विज्ञान पदव्या, आदि, तथा

(ii) विशेषाधिकार को रिपोर्ट।

28. किन राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्थानों का प्राप्ति और निवासन को बाधित निर्देश जारी करना।

29. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विभाग।

नोट--अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य-क्रमों को समग्र माने, यात्रा और मनस्व के लिए कल्याण मंत्रालय नोटोय संयोजन होगा, इन मनुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विभाग स्थानों के संबंध में नीति, एवं योजना, परीक्षाएँ पूरा करने हदरादि एवं उनके समन्वय को भी जिम्मेदारों मन्वड, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य-मंत्रालयों और मंत्र राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की रहेगी। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्रों के लिए नोटोय मंत्रालय अथवा विभाग होगा।

[illegible]

3 इलेक्ट्रानिक प्रथमण उपकरण (संगणक) से सम्बन्धित आवश्यकताओं का समन्वय।

4. धातुत्मय ग्रेड मिलितों के अक्षाधिकारिक से संबंधित सभी प्रयोगिकी।

5. नैशनल सिलिकोन फेसिलिटी।

6. संगणक आधारीत सूचना, प्रयोगिकी और प्रक्रमण संबंधी सभी मामले, जिनके अंतर्गत यन्त्र-मन्त्री मामली (हार्डवेयर) सामग्री यन्त्र और (सॉफ्टवेयर) आती है, प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकल्पों, जैसे आई. एफ. आई. पी., आई. बी. आई. सी. सी. से सुसंगत मामले।

महासागर विकास विभाग

1. महासागर से संबंधित ऐसे मामले जो किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को विशिष्टतया आवंटित न किए हों।

2. महासागर से संबंधित नीतियों, समन्वय, विनियमन उपाय और विकास सहित, तथा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे :—

(i) अनुसंधान (मौलिक अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित उपयोगों का विकास,

(ii) प्रौद्योगिकीय विकास,

(iii) निर्जीव और सजीव समुद्री साधनों की उपलब्धता का पता लगाने और उनका मानचित्रांकन करने के लिए सर्वेक्षण,

(iv) परिरक्षण, संघारण और संरक्षण,

(v) समुचित कौशल और प्रशिक्षित वर्ग का विकास,

(vi) सहयोग, तकनीकी सहयोग, सहित, और

(vii) उपर्युक्त से संबंधित कानून।

3. मुले सागर में समुद्री पर्यावरण।

4. महासागर आयोग।

5. सर्वभारतीय समुद्र विज्ञान संगम।

6. महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिकरण अथवा बोर्ड।

अन्तरिक्ष विभाग

1. अन्तरिक्ष विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष उपयोग से संबंधित सभी मामले, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) अन्तरिक्ष से संबंधित मामलों में अनुसंधान (जिसके अन्तर्गत मौलिक प्रयोग भी हैं) तथा उसके उपयोगों का विकास;

(ii) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले;

(iii) अन्तरिक्ष उपयोग से संबंधित सभी मामले;

(iv) वाह्य अन्तरिक्ष के विकास और उसके उपयोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं।

(क) वाह्य अन्तरिक्ष के उपयोग से संबंधित परियोजनाएं और उद्योग;

(ख) राकेटों और उपग्रहों का डिजाइन, विनिर्माण और उनका छोड़ा जाना; और

(ग) अन्तरिक्ष उपयोग से संबंधित कार्य।

2. अन्तरिक्ष विज्ञान और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए और अन्तरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित भी हैं :—

(i) वैज्ञानिक कार्य में लगे सत्याग्रही और संगठनों के और विश्व-

विद्यार्थियों को अन्तरिक्ष विज्ञान में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए राह, यत्ना, और

(ii) अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों का छात्रवृत्ति देना और व्यक्तियों को जिनमें विदेश जाने वाले व्यक्ति भी हैं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना।

3. अन्तरिक्ष से संबंधित मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिकारों में अन्तरिक्ष से संबंधित मामले और अन्य देशों से संबंध; और

(ii) विदेशी छात्रवृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से पत्र-व्यवहार।

4. विभाग के नियंत्रणाधीन कामों से संबंधित सभी मामले।

5. विभाग के बजट के नामे खालने योग्य कार्यों का निष्पादन और भूमि की खरीद।

6. विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपकरण प्राप्त करना।

7. विभाग से संबंधित वित्तीय मजूरी।

8. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहनदबाब से संबंधित सभी मामले।

9. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण (एन० आर० एस० ए०) से संबंधित सभी मामले।

10. राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा प्रबन्ध प्रणाली से संबंधित सभी विषय जिसके अन्तर्गत सुदूर सुग्राह्यता पर मुख्य रूप से आधारित समेकित आकड़ों की तैयारी और ऐसी जानकारी के विश्लेषण और प्रसारण में सहायता भी है।

मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए अनुसचिवीय सहायता।

2. कामकाज के नियम।

राष्ट्रपति सचिवालय

1. राष्ट्रपति के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना।

प्रधान मंत्री कार्यालय

1. प्रधान मंत्री के लिए सचिवीय सहायता की व्यवस्था करना।

योजना आयोग

1. तकनीकी कामकाज सहित देश के भौतिक, पूंजी संबंधी और मानव साधनों का निर्धारण तथा जो संसाधन कम पाए जाएं उनकी वृद्धि के लिए प्रस्थापनाओं का तैयार किया जाना।

2. देश के साधनों के अधिकाधिक प्रभावशाली और संतुलित उपयोग के लिए योजनाओं का तैयार किया जाना।

3. उन प्रक्रमों का परिनिश्चय करना जिनमें योजना पूर्वािकताओं के अवधारण पर कार्यान्वित की जानी चाहिए और हर एक प्रक्रम को पूर्ति के लिए साधनों का आवंटन।

4. योजना के सभी पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए जिस प्रकार का संतुलित आवश्यक है उसका अवधारण करना।

5. योजना के हर एक प्रक्रम के निष्पादन में हुई प्रगति को समय-समय पर आंकना।

6. राष्ट्रीय विभाग में जो सम्मेलन ।
7. पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम
8. परिप्रेक्षी ।
9. जनशक्ति निदेशालय ।

टिप्पण — योजना अयोग, माटे तौर पर, योजना तथा योजना संगठन से संबंध रखने वाले तत्वों की प्रकृति से संबंध रहेगा । योजना में सम्मिलित विनिर्दिष्ट स्कीमों की तात्त्विक और व्यंजित ऐसी मामलों है जो केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों में व्यवहृत किए जाने हैं ।

(जैल सिंह)

राष्ट्रपति

[74/2/1/85-मंत्रि]

एल० आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1985

S.O. 696(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-fourth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, for the Schedules the following Schedules shall be substituted, namely :—

“THE FIRST SCHEDULE

(Rule 2)

MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS AND OFFICES

(MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA TATHA KARYALAYA)

1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya) :

- (i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag).
- (ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

(iii) Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag).

(iv) Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag).

2. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya) :

- (i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).
- (ii) Department of Textiles (Vastra Vibhag).
- (iii) Department of Supply (Poorti Vibhag).

3. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya) :

- (i) Department of Posts (Dak Vibhag).
- (ii) Department of Tele-communications (Door-sanchar Vibhag).

4. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) :

- (i) Department of Defence (Raksha Vibhag).
- (ii) Department of Defence Production and Supplies (Raksha Utpadan aur Poorti Vibhag).
- (iii) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan aur Vikas Vibhag).

5. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya) :

- (i) Department of Coal (Koyala Vibhag).
- (ii) Department of Power (Vidyut Vibhag).
- (iii) Department of Non-conventional Energy Sources (Gair-Paramparik Oorja Srota Vibhag).

6. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya) :

Department of Environment, Forests and Wildlife. (Paryavaran, Van Tatha Vanya Jeev Vibhag).

7. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).

8. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) :

- (i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).
- (ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).
- (iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).

9. Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya aur Nagrik Poorti Mantralaya) :

- (i) Department of Food (Khadya Vibhag).
- (ii) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag).

10. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya) :

- (i) Department of Health (Swasthya Vibhag).
- (ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag).

11. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya) :

- (i) Department of Internal Security (Antariksha Suraksha Vibhag).
- (ii) Department of States (Rajya Vibhag).
- (iii) Department of Official Language (Rajbhasha Vibhag).
- (iv) Department of Home (Grih Vibhag).

12. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya) :

- (i) Department of Education (Shiksha Vibhag).
- (ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakaram aur Khel Vibhag).
- (iii) Department of Women's Welfare (Mahila Kalyan Vibhag).
- (iv) Department of Arts (Kala Vibhag).
- (v) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).

13. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya) :

- (i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).
- (ii) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag).
- (iii) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag).
- (iv) Department of Public Enterprises (Sarkari Udyam Vibhag).

14. Ministry of Information and Broadcasting Soochana aur Prasaran Mantralaya).

15. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).

16. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya) :

- (i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).
- (ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag).
- (iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).

17. Ministry of Parliamentary Affairs and Tourism Sansadiya Karya aur Paryatan Mantralaya) :

- (i) Department of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Vibhag).
- (ii) Department of Tourism (Paryatan Vibhag).

18. Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension Karmik aur Prashikshan, Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya) :

- (i) Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).
- (ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag).
- (iii) Department of Pension and Pensioners' Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag).

19. Ministry of Petroleum and Natural Gas Petroleum aur Prakritik Gas Mantralaya).

20. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya) :

- (i) Department of Planning (Yojana Vibhag).
- (ii) Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag).

21. Ministry of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Mantralaya).

22. Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Mantralaya) :

- (i) Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag).
- (ii) Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

23. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya) :

- (i) Department of Steel (Ispat Vibhag).
- (ii) Department of Mines (Khan Vibhag).

24. Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya) :

- (i) Department of Railways (Rail Vibhag).
- (ii) Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag).
- (iii) Department of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Vibhag).

25. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya).

26. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya).

27. Ministry of Welfare (Kalyan Mantralaya).

28. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

29. Department of Electronics (Electroniki Vibhag).

30. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag).

31. Department of Space (Antariksh Vibhag).

32. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya).

33. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya).

34. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya).

35. Planning Commission (Yojana Ayog).

THE SECOND SCHEDULE

(Rule 3)

DISTRIBUTION OF SUBJECTS AMONG THE DEPARTMENTS (VIBHAG)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(KRISHI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)

Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :

1. Liaison with international Agri-Organisations like Food and Agriculture Organisation of the United

Nations, handling of CARE goods concerning agriculture etc.

2. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning agriculture and implementation of decisions made thereat.

3. Convention on Locust Control.

4. Plant Quarantine.

5. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest; as far as these relate to :—

(a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, infant-milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Meat and Meat products;

(b) Development of agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture (Krishi Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets,

(c) Shellac Industry;

(d) Processing of fish (including canning and freezing);

(e) Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry; and

(f) Technical assistance and advice to fish processing industry.

6. Fishing and fisheries inland and marine.

7. Fishing and fisheries beyond territorial waters (including Deep-Sea Fishing Station, Bombay).

8. Agricultural and Livestock Census.

9. All India Service—Indian Agricultural Service.

10. Sugarcane Development Scheme.

11. Matters relating to damage to crops and loss of live-stock due to natural calamities.

12. Co-ordination of relief measures necessitated by natural calamities, other than epidemics.

13. Matters relating to loss of human life and property due to all natural calamities, other than epidemics.

14. Indian People's Famine Trust.

Part II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :—

15. Adulteration of agricultural products other than foodstuffs.

16. Economic Planning (Agricultural Economics and Statistics).

17. Professions (Veterinary Practice).

18. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting animals or plants including locusts.

19. Price control of agricultural commodities except foodgrains, sugar, vanaspathi, oil seeds, vegetable oils, cakes and fats, jute, cotton and Tea.

20. Production of Oil Seeds.

21. Pattern of financial assistance to various State Undertaking Dairy Development Scheme either through their own agencies or through the Cooperative Unions.

22. Operation Flood I and II, and all matters pertaining thereto.

23. Prevention of Cruelty to Animals.

Part III

For the Union Territories the subjects mentioned in Parts I and II above, so far as they exist in regard to these Territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

24. Agriculture (other than agricultural education and research), protection against pests and prevention of plant diseases.

25. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.

26. Courts of Wards.

27. Co-operation in agricultural sector, agricultural credit and indebtedness.

28. General Policy relating to the marketing of agricultural produce, including pricing, exports etc.

29. Insurance (Crop and Cattle Insurance).

30. General Policy in the field of Co-operation and Co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in the respective fields).

31. Matters relating to National Co-operative Organisation.

32. National Co-operative Development Corporation.

33. Incorporation, regulation and winding up of Co-operative Societies with objects not confined to one State.

34. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

Part IV

General and Consequential :—

35. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and international organisations in so far as agricultural and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries in the field of agriculture and

allied subjects but excluding such matters in the field of agricultural research and education and allied subjects as are specifically assigned to the Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).

36. Agriculture and horticulture.
37. Bio-aesthetic Planning.
38. Animal Husbandry including—(a) pounds and cattle trespass; (b) cattle utilisation and slaughter.
39. Agricultural Production—Grow more food and fodder.
40. Land Reclamation.
41. National Land Use and Conservation Board.
42. Development of Cotton and Jute.
43. Soil Survey in connection with development programmes.
44. Financial assistance to State Soil Conservation and Forestry Development Schemes.
45. Fertilisers and Manures (Formulation of Demands, fixation of targets and distribution of fertilisers).
46. Administration of (a) Fertiliser (Control) Order, 1957; (b) Fertiliser (Movement Control) Order, 1960.
47. Administration of Insecticides Act, 1968.
48. Agricultural Implements and Machinery.
49. Organisation and development of Extension Education and Training in the Country.
50. Intensive Agricultural District Programme.
51. Intensive Agricultural Areas.
52. Crop campaigns, crop competitions and farmers organisations.
53. Schemes received from States and Union Territories for the settlement of landless agricultural labourers.
54. Mechanised Farms.
55. All Attached and Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
56. Public Sector Projects falling under the subjects in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.
57. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.
58. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.
59. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.

B. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG)

Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

1. Relations with foreign and international agricultural research and educational institutions and organisations, including participation in international conferences, associations and other bodies dealing with agricultural research and education and follow up of decisions at such international conferences, etc.
2. Fundamental, applied and operational research and higher education including coordination of such research and higher education in agriculture, animal husbandry, dairying and fisheries, including agricultural statistics, economics and marketing.
3. Coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions in so far as it relates to food and agriculture including animal husbandry dairying and fisheries.
4. Schemes for financing to the Indian Council of Agricultural Research, and the Commodity Research programmes other than those relating to tea, coffee and rubber.
5. Sugarcane research.

Part II

For Union Territories the subjects mentioned in Part I above, so far as they exist in regard to these Territories and in addition the following subject which falls within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India :—

6. Agricultural Education and Research.

Part III

General and consequential :—

7. All matters relating to foreign aid received from foreign countries and International Organisations in so far as agricultural research and education and allied subjects are concerned, including all matters relating to assistance afforded by India to foreign countries in the field of agricultural research and education and allied subjects.
8. Plant introduction and exploration.
9. All India Soil and Land Use Survey relating to research, training co-relation, classification, soil mapping and interpretation.
10. Financial assistance to State Governments and Agricultural Universities in respect of agricultural research and educational schemes and programmes.
11. National Demonstrations.
12. Indian Council of Agricultural Research and its constituent Research Institutes, Stations, Laboratories and Centres.

13. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

14. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Department.

15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.

C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)

1. All matters relating to panchayati Raj.

2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holdings and other related matters.

3. Administration of the Land Acquisition Act, 1894, and other matters relating to acquisition of land for purposes of the Union.

4. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.

5. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans, excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.

6. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey for revenue purposes, alienation of revenues.

7. Duties in respect of succession to agricultural land.

8. Nodal responsibility for all matters relating to the minimum Needs Programme in the rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification, housing for landless rural labour and the nutrition programmes.

9. Rural Water Supply.

10. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto;

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment such as National Rural Employment Programme (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and other programmes evolved from time to time;

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.

11. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc.

12. Desert Development Programmes.

13. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.

14. Warehousing in rural areas, including rural godowns.

15. Town and country planning so far as it relates to rural areas.

16. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937.

17. Cooperatives relatable to the items in this list.

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

19. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

20. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO).

D. DEPARTMENT OF FERTILIZERS (URVARAK VIBHAG)

1. Production of Fertilizers.

2. Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited.

3. Public sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

4. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

MINISTRY OF COMMERCE (VANIYA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIYA VIBHAG)

I. General International Trade Policy.

1. International Commercial Policy.

2. International Agencies connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ESCAP, ECA, ECLA, EEC, EFTA, GATT).

3. International Commodity Agreements other than agreements relating to wheat

4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

II. Foreign Trade

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreement on Tariffs and Trade and Common Wealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion and protection of interests of Indian traders abroad.

6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to :

(i) import of feature films;

(ii) export of Indian films-both feature length and shorts; and

- (iii) import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry

7. Chief Controller of Imports and Exports

III. State Trading

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including :

- (i) State Trading Corporation and its subsidiaries excluding Handicrafts and Handlooms Export Corporation and Central Cottage Industries Corporation.
- (ii) Minerals and Metals Trading Corporation and its Subsidiaries.

IV. Trading with the enemy; enemy property

9. Trading with the enemy; enemy firms and enemy property; reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy firms; Custodian of Enemy Property for India.

10. International Customs Tariff Bureau including residuary work relating to Tariff Commission.

11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufactures including the following :

- (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937;
- (b) marine products;
- (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);
- (d) fuels, minerals and mineral products;
- (e) specific export-oriented products (including plantation crops etc. but excluding jute products and handicrafts) which are directly the charge of this Department.

12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including :

- (a) Export Credit and Guarantee Corporation.
- (b) Export Inspection Council.
- (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.
- (d) Trade Fair Authority of India.
- (e) Free Trade-Zones.

13. Projects and programmes for stimulating and assisting the export efforts.

14. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of Plantation crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.

15. Processing and distribution for domestic consumption and exports of Instant tea and Instant Coffee.

16. (i) Tea Trading Corporation of India.
- (ii) Tea Board.
- (iii) Coffee Board.
- (iv) Rubber Board.
- (v) Cardamom Board.
- (vi) Tobacco Board.

B. DEPARTMENT OF SUPPLY

(POORTI VIBHAG)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

2. Disposal of surplus stores.

3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General, Ship Repairs.

4. Administration of—

- (a) Directorate General of Supplies and Disposals;
- (b) Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi;
- (c) National Test House, Alipore, Calcutta.

C. DEPARTMENT OF TEXTILES

(VASTRA VIBHAG)

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of jute, jute products, handicrafts and all textiles and woollens including handlooms, powerlooms, ready made garments and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester, acrylic, etc.).

2. Textiles Commissioner.

3. Jute Commissioner.

4. Jute Corporation of India Limited.

5. Cotton Corporation of India Limited.

6. All India Handicrafts Board.

7. All India Handlooms Board.

8. The National Textile Corporation Limited.

9. Sericulture.

10. Central Silk Board.

11. Handloom Development Commissioner.

12. Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad.

13. Bombay Textile Research Association, Bombay.

14. The Silk and Art Silk Mills' Research Association, Bombay.

15. The South India Textile Research Association, Coimbatore.

16. Wool Research Association, Bombay.

17. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.

18. Northern India Textile Research Association, New Delhi.

19. Development and expansion of export production in relation to textiles, woollens, handlooms, ready-made garments silk and cellulosic fibres, jute and jute products and handicrafts.

20. Handicrafts and Handlooms Export Corporation and its subsidiary.

21. Textile Committees.

22. Commissioner of Payments

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(SANCHAR MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF POSTS

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of posts with other countries.

2. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the Department of Posts.

3. Posts, including Post Office Savings Bank (Administration), Post Office Certificates (Administration) Post Office Life Insurance Fund (Administration) and Broadcast Receiver Licences.

4. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

5. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters in this list.

6. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court.

B. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of Telecommunications with other countries.

2. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the telecommunications.

3. Telegraphs, including Telerphones, Wireless and other like forms of communications.

4. Indian Telephone Industries, Bangalore and the Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

5. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.

6. Inquiries and statistics for the purpose of any other matter in this list.

7. Fees in respect of any of the matters in this list but not including fees taken in any court ;

MINISTRY OF DEFENCE

(RAKSHA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)

1. Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution, and after its termination to effective demobilisation.

2. The Armed Forces of the Union, namely, Army, Navy and Air Force.

3. The Reserves of the Army, Navy and Air Force.

4. The Territorial Army and the Auxiliary Air Force.

5. The National Cadet Corps, the Auxiliary Cadet Corps and the Lok Sahayak Sena.

6. Works relating to Army, Navy, Air Force and Ordnance Factories.

7. Remounts, Veterinary and Farms Organisation.

8. Canteen Stores Department (India).

9. Civilian Services paid from Defence Estimates.

10. Hydrographic surveys and preparation of navigational charts.

11. Formation of Cantonments, delimitation/excision of Cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution and powers within such areas of Cantonment Boards and authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas.

12. Acquisition, requisitioning, custody and relinquishment of land and property for defence purposes. Eviction of unauthorised occupants from defence land and property.

13. Matters relating to ex-Servicemen including pensioners.

B. DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES (RAKSHA UTPADAN AUR POORTI VIBHAG)

1. Defence Production and Inspection Organisation.

2. Hindustan Aeronautics Ltd.

3. Bharat Electronics Ltd.

4. Mazagon Docks Ltd., Bombay.

5. Garden Reach Workshops Ltd., Calcutta.

6. Praga Tools Corporation Ltd., Hyderabad

7. Bharat Earth Movers Ltd.

8. All matters connected with Aeronautics other than matters with which the Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag) is concerned and matters relating to aerodynamics with its aeronautical aspects connected with the development

for projects in the field of space research with which Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) is concerned] including :

- (a) development of the aeronautics industry and coordination among users ;
- (b) coordination of research and development in the field of aeronautics, including aircraft, missiles ; and
- (c) financial assistance to academic institutions, research laboratories, and other agencies or bodies for furtherance of studies and research in aeronautics

9 Planning for substitution of import ; requirements for defence purposes, particularly in the fields of electronics, instrumentation, vehicles and ship-building, and the preparation of detailed schemes in this regard.

10. Implementation of such schemes through the utilisation of the industrial capacity in the country for research and development work and for manufacture.

2 DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT (RAKSHA ANUSANDHAN TATHA VIKAS VIBHAG)

1 Rendering advice to Raksha Mantri and to the three services and inter services organisations on all scientific aspects of Military operations, equipment and logistics.

2 Formulation of Research, Design and Development Plans on—

- (a) Armaments
- (b) Explosives
- (c) Electronics
- (d) Engineering
- (e) Rockets and Missiles
- (f) Vehicles
- (g) Aeronautics
- (h) Naval Oceanography items
- (i) Fire Research
- (j) Other Machinery and Equipments used by the three services.

3 Administration of the Defence Research and Development Organisation including the various laboratories and Establishments in the Organisation

4 Administration of the Defence Research and Development Service Rules, 1978 and other Service Rules pertaining to the Defence Research and Development Organisation (DRDO)

5 Defence Research and Development Council.

6 All matters relating to the scientific and technical personnel under the control of the Department

7 Financial assistance to academic institutions, research laboratories and other agencies or bodies

for furtherance of studies and research leading to promotion of Defence Research and Development

8 Coordination of Scientific and Technological research and development work in the country with the work of Defence Research and Development Organisation

9 Liaison with Research and Development Organisation in foreign countries particularly on aspects related to the field of Defence.

MINISTRY OF ENERGY

(OORJA MANTRALAYA)

A DEPARTMENT OF COAL

(KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947)

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States

B DEPARTMENT OF POWER

(VIDYUT VIBHAG)

1 General Policy in the field of energy

2 Research, development, technical assistance and all matters relating to Hydro-electric and thermal power.

3. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910)

4. Administration of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

5. Central Electricity Board.

6. Central Electricity Authority.

7. Power Schemes in Union Territories

8. The Damodar Valley Corporation.

9. National Projects Construction Corporation Limited.

10. Bhakra Management Board and Beas Project (except matters relating to irrigation).

11 (i) National Thermal Power Corporation.

(ii) National Hydro-electric Power Corporation.

(iii) Rural Electrification Corporation.

(iv) North Eastern Electric Power Corporation.

C DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(APARAMPARIK OORJA SROTA VIBHAG)

1. Research and development of bio-gas and programmes relating to bio-gas units.

2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).

3. Solar Photovoltaic devices, including their development, production and applications.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA) DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILD LIFE

(PARYAVARAN, VAN AUR VANYA JEEV VIBHAG)

1. Environment and Ecology, including environment in coastal waters, in mangroves and coral reefs but excluding marine environment on the high seas.

2. Botanical Survey of India and Botanical Gardens.

3. Zoological Survey of India.

4. National Museum of Natural History.

5. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.

7. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

8. Biosphere Reserve Programme.

9. National Forest Policy and Forestry Development in the country, including Social Forestry.

10. Forest Policy and all matters relating to forests and forest administration in so far as the Andaman and Nicobar Islands are concerned.

11. Indian Forest Service.

12. Wild life preservation and protection of wild birds and animals.

13. Fundamental research including co-ordination thereof and higher education in Forestry.

14. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park.

15. National Landuse and Wastelands Development Council.

16. National Wastelands Development Board

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(VIDESH MANTRALAYA)

1. External Affairs.

2. Relations with foreign States and Commonwealth countries.

3. Indian Council for Cultural Relations.

4. All matters affecting foreign diplomatic and Consular Officers and U.N. Officers and its specialized agencies in India.

5. Passports and visas excluding the grant of visas or endorsements for entry into India but including the grant of entry permits to South Africans of Non-Indian origin under the Reciprocity (South Africa) Rules, 1944 and the grant of entry visas for Ceylon nationals except missionaries.

6. Extradition of criminals and accused persons from India to foreign and Commonwealth countries and vice versa and general administration of the Indian Extradition Act, 1903 (XV of 1903), and extra-territoriality.

7. Preventive detention in India for reasons of State connected with External and Commonwealth affairs

8. Repatriation of the nationals of foreign and Commonwealth States from India and deportation and repatriation of Indian nationals of foreign and Commonwealth countries to India.

9. Immigration to India from the Union of South Africa or any other country to which the Reciprocity Act, 1943 (9 of 1943) may apply.

10. All Consular functions.

11. Travel arrangements for traders, muleteers, porters and pilgrims from India to Tibet region of China and vice versa.

12. Liaison work connected with the cultural scholarships schemes of the Department of Education and nomination of private students of Indian origin domiciled abroad to reserve seats in medical and engineering colleges in India.

13. Political pensions paid to foreign refugees and descendants of those who rendered services abroad

14. Ceremonial matters relating to foreign and Commonwealth Visitors and Diplomatic and Consular Representatives.

15. Matters in respect of Pondicherry, Goa, Daman and Diu, involving relations with France and Portugal.

16. Relations with States in special Treaty relations with India such as Bhutan.

17. Himalayan expeditions, permission to foreigners to travel to Protected Areas other than those with which the Ministry of Home Affairs (Grih Mant-raya) is concerned.

18. Coordination and development measures in border areas.

19. United Nations, Specialised Agencies and other International Conferences.

20. Indian Foreign Service.

21. Indian Foreign Service Branch 'B'.

22. Foreign Service Training Institute.

23. External Publicity.

24. Political treaties, agreements and conventions with foreign and Commonwealth countries.

25. (a) Pilgrimages to places outside India, including the administration of the Port Haj Committee Act, 1932 and the Rules made thereunder and Indian Pilgrim Ships Rules, 1933, and pilgrim parties from India to shrines in Pakistan and vice versa.

(b) Protection and preservation of Non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of Pant-Mirza Agreement of 1955.

26. Abducted Persons (Recovery and Restoration).

27. Evacuation of Non-Muslims from Pakistan to India.

28. Protection of rights of the Minority Communities in India and Pakistan (except rehabilitation of Muslim migrants who have returned from East Pakistan to West Bengal under the Nehru-Liaquat Pact; rehabilitation of Muslims internally displaced in West Bengal at the time of communal disturbances on the partition of the country; and restoration of mosques and other places of religious worships to Muslims in West Bengal).

29. Non-Muslim migration from Pakistan and Muslim migration from India.

30. Recovery of advances granted to the evacuees from Burma, Malaya, etc., during the years 1942-47 and residual work relating to refugees given asylum in India during World War II.

31. Notification regarding commencement or cessation of a state of war.

32. Foreign Jurisdiction.

33. Piracies and crimes committed on the High Seas or in the air; offences against the law of nations committed on land or the High Seas or in the air.

34. Inquiries and statistics for the purposes of any of the subjects allotted to this Ministry.

35. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry.

36. Offence against laws with respect to any of the subjects allotted to this Ministry.

37. Hospitality Grant of the Government of India.

38. Delineation of the land frontier of India.

39. Border raids and incidents on the land borders of India.

40. Diplomatic flight clearances for non-scheduled chartered flights of foreign civil and military aircraft transiting India.

41. Matters relating to the Continental Shelf, Territorial Waters, Contiguous Zone and question of fishery rights in the High Seas and other questions of International Law.

42. Economic and technical assistance given by India to the Government of Nepal under the Colombo Plan for Co-operative Economic Development.

43. Purchase, inspection and shipment of Stores from abroad for the Central Government other than those the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

NOTE: Commonwealth countries should be taken to include British Colonies, Protectorates and Trust Territories.

MINISTRY OF FINANCE

(VITTA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)

I. Exchange Control

1. Administration of the Foreign Exchange Regulation Act, other than enforcement work mentioned under the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag) in the Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya).

2. Foreign exchange budgeting.

3. Control of the foreign exchange resources including scrutiny of proposals for imports from the foreign exchange point of view.

4. Foreign investment.

5. Import and export of gold and silver.

6. Approvals for commercial borrowing abroad.

II. Foreign aid for Economic Development

7. Technical and economic assistance received by India under.—

(a) The Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.

(b) The United States Point Four Programme.

(c) The United Nations Technical Assistance Administration Programmes.

(d) Ad hoc offers of Technical Assistance from various foreign countries.

8. Technical assistance given by India to the Member countries of the Colombo Plan under Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan.

9. All matters relating to the Meetings of Colombo Plan Council and the Consultative Committee of the Plan and :—

(i) U.S. Technical Cooperation Mission.

(ii) U.S. Development Loan Fund.

(iii) Colombo Plan.

(iv) Norwegian Aid.

(v) Ford Foundation and Rockefeller Foundation.

(vi) Loans and Credit from foreign countries.

(vii) Loans and Credit from IBRD and IMF, Export-import Banks etc.

10. All matters relating to the India Consortium.

11. All matters relating to grant of loans and credits to other countries, except Nepal, Bhutan and Bangladesh.

12. Policy issues relating to the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) and contributions to the specialised Agencies of the United Nations and other U.N. Bodies.

13. All matters relating to the Foreign Volunteers Programmes in India, including the United Nations Volunteers (except outgoing volunteers under UNV).

14. Technical assistance received by India or given to foreign governments, international Institutions and Organisations, except such as are relatable to subjects allocated to any other Department.

III. Internal Finance

15. Currency and Coinage, that is to say, questions relating to—

(a) the Security Press and the Mints, including the Assay Department and Silver Refinery Project;

(b) Coinage;

(c) Note Issue.

16. Functions of the Treasurer of Charitable Endowments for India.

17. Investment Policy, including Investment Policy of LIC, UTI and GIC.

18. Investment pattern for Employees' Provident Fund and other like Provident Funds.

IV. Economic Advice

19. Advice on matters which have a bearing on internal and external aspects of Economic Management, including prices.

20. Credit, fiscal and monetary policies.

V. Budget

21. Ways and Means.

22. Preparation of Central Budget other than Railway Budget, including supplementary excess grants and when a proclamation by the President as to failure of Constitutional machinery is in operation in relation to a State or a Union Territory, preparation of the budget of such State or Union Territory.

23. Borrowing and Floatation of Market Loans by the Central and State Governments.

24. Borrowing of Public Bodies such as Corporations, Municipalities etc.

25. Administration of the Public Debt Act.

26. Fixation of interest rates, including Borrowing Rates, Productivity Test Rates, etc.

27. Accounting and Audit Procedures, including classification of transactions.

28. Financial matters relating to partition, Federal Financial Integration and Reorganisation of States.

29. Contingency Fund of India and Administration of Contingency Fund of India Act, 1950 (49 of 1950).

30. Treasury bills, including ad hoc to replenish the Central balances.

31. Sterling Pensions—Transfer of responsibility to U.K. Government and actual calculation of the liability involved.

32. Conspectus of Central and State Government Budgets.

33. Finance Commission.

34. Taxation Enquiry Commission.

35. Small Savings, including the administration of the National Savings Organisations.

36. Duties and Powers of the Comptroller and Auditor General.

37. Laying of Audit Reports before the Parliament and coordination in the Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag) of all Audit Reports, PAC's Reports and Estimates Committee's Reports.

38. Financial Emergency.

VI. Stock Exchanges

39. Administration of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

40. Regulation of Stock Exchanges.

VII. Stock Issues

41. Control over the Issues of Capital by Joint Stock Companies.

VII. A. Miscellaneous Acts.

42. Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873).

43. Section 20 of the Indian Trusts Act, 1850 (2 of 1882), dealing with investments.

44. Metal Tokens Act, 1889 (1 of 1889).
45. Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890).
46. Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906).
47. Indian Securities Act, 1920 (1 of 1920).
48. Currency Ordinance, 1940 (4 of 1940).
49. International Monetary Fund and Bank Act, 1945 (47 of 1945).
50. Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947).
51. Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951).
52. Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959).
53. Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).
54. Compulsory Deposit Scheme Act, 1963 (21 of 1963).
55. Legal Tender (Inscribed Notes) Act, 1964 (28 of 1964).
56. Asian Development Bank Act, 1966 (18 of 1966).
57. Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968).
58. Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971).
59. Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (56 of 1971).
60. Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).

VIII. Insurance

61. Policy relating to General Insurance ; Administration of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) ; Insurance Companies Association Pool ; Subsidiaries of the Life Insurance Corporation.
62. Policy relating to Life Insurance ; Nationalisation of the Life Insurance Business ; Administration of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956); Life Insurance Tribunal.

63. Office of the Controller of Insurance.

64. The responsibility of the Central Government relating to matters concerning Centrally administered areas in respect of any of the entries from 61 to 63 above.

IX. Banking

65. All Indian banks, whether nationalised or not.
66. All foreign banks so far as their operations in India are concerned.
67. All matters relating to the Reserve Bank of India.
68. All matters relating to Cooperative Banking which are the concerns of this Department.

69. All matters relating to long term financial institutions, excluding Unit Trust of India, Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation.

70. Chit Fund and other non-banking companies accepting deposits.

71. Other matters relating to Banking in India.

72. Administration of all Statutes, Regulations and other laws connected with entries from 65 to 71 above.

X. Management of the Indian Economic Service

73. Centralised aspects of managing the Indian Economic Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that services.

B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)

1. Financial rules and regulations and delegation of financial powers.

2. Financial sanction relating to all Ministries and offices of the Government of India, which are not covered by powers delegated or conferred by the rules or by any general or special orders.

3. Review of the staffing of Government establishments with a view to securing economy.

4. Advice to Ministries and Government Undertakings on Cost Accounts matters and attending to Cost Investigation work on their behalf.

5. Indian Audit and Accounts Department.

6. Defence Accounts Department.

7. Organisation of the Controller General of Accounts dealing with :

- (i) General principles of Government accounting relating to Union or State Governments and form of accounts, and framing or revision of rules and manuals relating thereto ;

- (ii) Reconciliation of cash balance of Union Government with Reserve Bank in general and, in particular, of Reserve Deposits pertaining to Civil Ministries or Departments;

- (iii) Overseeing the maintenance of adequate standards of accounting by Central Civil Accounts Offices;

- (iv) Consolidation, of monthly accounts, preparation of review of trends of revenue realisation and significant features of expenditure etc. and preparation of annual accounts (including Summary, Civil Appropriation Accounts) showing under the respective heads, the annual receipts and disbursements for the purpose of the Union Government;

- (v) Administration of Central Treasury Rules;
- (vi) Coordination and assistance in the Introduction of management accounting system in Civil Ministries or Departments;
- (vii) Cadre Management of Group 'A' (Indian Civil Accounts Service) and Group 'B' Officers of the Central Civil Accounts Offices; and
- (viii) Organising of training and examinations for the Central Civil Accounts staff belonging to Group 'C' and 'D'.

8. Release of Grants and Loans for the State Plans including advance Plan Assistance towards expenditure on relief measures in the event of natural calamities.

9. State Finance.

10. Plan Budget.

11. Scrutiny of Central and State Legislation having financial and economic implications.

12. Planning and Development Finance.

C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)

1. All matters relating to Central Boards of Revenue.

2. Grants-in-aid to the National Institute of Public Finance and Policy.

3. Stamp duties on bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of share debentures, proxies and receipts.

4. Supply and distribution of all kinds of stamps.

5. All questions relating to income tax (except questions relating to the Income-tax Appellate Tribunal) corporation tax, capital gains tax, excess profits tax, business profits tax and estate duty, wealth tax, expenditure tax and gift tax and also questions relating to Railway Passenger Fares Act.

6. Administration of excise in the Union Territories, i.e. all questions relating to—

- (a) Alcoholic liquors for human consumption.
- (b) Opium, Indian hemp and narcotic drugs and narcotics.

7. Medicinal and toilet preparations containing alcohol, or any substance included in 6(b).

8. Opium as regards cultivation, manufacture and sale for export.

9. International agreements relating to dangerous drugs and their Implementation.

10. All matters relating to Customs (Sea and Land) including the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), Tariff Valuations, Customs Cooperation Council, Customs nomenclature and similar matters, duties on goods imported or exported; prohibitions and restrictions on imports and exports imposed in the interest of revenue; and interpretation of Customs Tariff.

11. All matters relating to Central Excise and Gold Control administration.

12. Sales Tax :—

- (i) The administration of Sales-Tax Laws Validation Act, 1956 (7 of 1956).
- (ii) Levy of tax on the course of inter-State trade or commerce-problems arising out of the administration of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956).
- (iii) Declaration of goods as of special importance in inter-state trade or commerce under article 286(3) of the Constitution, laying down of the conditions, and restrictions to which the State laws providing for the levy of tax on them would be subjected.
- (iv) All questions relating to replacement of sales tax by additional excise duty including administration of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).
- (v) All Bills, etc. relating to sales-tax levy in States coming up for the previous instructions, recommendations or assent of the President.
- (vi) Legislative matters concerning sales-tax in the Union Territories.
- (vii) Problems arising out of the invalidation of sugarcane cess levies of State including Validation of such levies.

13. All matters relating to pre-partition duty refund claims on salt.

14. Subordinate Organisations :—

- (a) Income Tax Department;
- (b) Customs Department;
- (c) Central Excise Department; and
- (d) Narcotics Department.

15. Preventive detention for reasons connected with the conservation of foreign exchange or prevention of smuggling; persons subjected to such detention.

16. Enforcement, viz. investigation, adjudication and prosecution of cases arising out of breaches, under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973); the Directorate General of Revenue Intelligence-cum-Directorate of Enforcement.

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)

I. The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:—

- 1. Purchase of foodstuffs for civil and military requirements and their disposal.
- 2. Participation in international conferences, Associations and other bodies concerning food, e.g. International Wheat Council.

International Sugar Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute and implementation of decisions made thereat.

3 Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.

4 Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.

5. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other foodstuffs including sugar.

6. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to :

(a) Fruit and Vegetable processing industry (including freezing and dehydration);

(b) Sugar Industry (including development of gur and khandsari; and

(c) Foodgrain milling industry.

7. Central Warehousing Corporation and the Warehousing Corporation.

II. The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :—

8. Trade and Commerce in and supply and distribution of foodgrains.

9. Trade and commerce in and the production, supply and distribution of sugar and foodstuffs other than foodgrains.

10. Price control of foodgrains, foodstuffs and sugar.

III. For the union territories of Delhi, the Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep, the subjects detailed in Parts I and II as well as the Food Administration.

IV. General and Consequential :

11. Matters relating to the following offices:—

(i) Subordinate Offices under the Department of Food

(ii) Directorate of Sugar, New Delhi.

(iii) National Sugar Institute, Kanpur.

12. Matters relating to the Development Council for Sugar Industry, New Delhi.

13. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department

14. Enquiries and statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department

15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court

B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.

2. Inter State Trade : [the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955].

3. Control of futures trading [the forward Contracts (Regulation) Act, 1952]

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980; persons subjected to detention thereunder.

6. Consumer Cooperatives.

7. Public Distribution System.

8. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

9. The National Consumer Protection Council.

10. Regulation of Packaged Commodities.

11. Training in Legal Meteorology.

12. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats

13. Price control of and inter-State trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats

14. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

II. Trade Marks etc.

15. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

16. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

17. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures) Act, 1956. The Standards of Weights and Measures Act, 1976.

18. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act. 1952.

19. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANT-RALAYA)

A. DEPARTMENT OF HEALTH (SWASTHYA VIBHAG)

I. Union Business

1. Union agencies and institutes for research or for the promotion of special studies in medicine and nutrition including all matters relating to the :—

- (i) Central Research Institute, Kasauli.
- (ii) The All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
- (iii) The Antigen Production Unit, Calcutta.
- (iv) The Malaria Institute of India, Delhi.
- (v) The Central Drugs Laboratory, Calcutta.
- (vi) College of Nursing, New Delhi.
- (vii) Lady Reading Health School and Ram Chand Lohia Infant Welfare Centre, Delhi.
- (viii) Hospital for Mental Diseases, Ranchi.
- (ix) Ram Manohar Lohia Hospital & Nursing Home, New Delhi.
- (x) Safdarjung Hospital, New Delhi.
- (xi) The Civil and Military Dispensary and the X-ray Installation, Simla.
- (xii) The dispensaries at Dum Dum and Santa Cruz Airports.
- (xiii) Medical Stores, Depots and Factories.
- (xiv) B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy.
- (xv) Medical College, Pondicherry.
- (xvi) Contributory Health Service Scheme for Central Government Servants and members of their families in Delhi and New Delhi.
- (xvii) Serologist and Chemical Examiner to the Government of India, Calcutta.

2. Port quarantine (sea and air) seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.

3. Port and Air Port Health Organisations.

4. Medical Examination of Seamen.

5. International sanitary regulations.

6. World Health Organisation (WHO).

7. Rockefeller Foundation and Ford Foundation.

8. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and the Central Food Laboratory set up thereunder

9. Higher training abroad in medical and allied subjects.

10. Assistance under the Colombo and Point Four Programme

11. National Malaria Eradication Programme.

12. National Malaria Control Programme.

13. Matters relating to epidemics. Problems connected with the supply of medicines, effect of malnutrition and shortage of drinking water leading to various diseases as a result of natural calamities.

II. List of business for Legislative and Executive purposes in respect of Union Territories

14. Public health and sanitation; hospitals; and dispensaries.

15. Pilgrimages other than pilgrimages to places outside India.

16. Burials and burial grounds; Cremations and cremation grounds.

17. Inns and inn-keepers.

18. Supply and distribution of cinchona and quinine.

19. Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in the Department.

20. Charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

III. List of business with which the Central Government deal in a Legislative capacity only for the Union and in both Legislative and Executive capacities for all Union Territories.

21. The medical profession and medical education.

22. The nursing profession and nursing education.

23. The pharmaceutical profession and pharmaceutical education.

24. The dental profession and dental education.

25. Homoeopathy.

26. Lunacy and mental deficiency.

27. Drugs standards.

28. Objectionable advertisements relating to drugs and medicines.

29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases affecting human beings.

30. Adulteration of foodstuffs and drugs.

31. Indigenous system of medicine

32. The Central Health Service.

IV. Miscellaneous Business

33. The Medical Council of India

34. The Central Council of Health.

35. Resettlement of demobilised medical and auxiliary medical personnel.

36. Red Cross except problems relating to protection of prisoners of war and other war victims

37. Dental Council of India

38. Indian Nursing Council

39. Pharmacy Council of India.
40. Indian Pharmacopoeia Committee.
41. B C G. Vaccination against Tuberculosis.
42. Concession of medical attendance and treatment for Central Government servants other than (i) those in Railway service; (ii) those paid from Defence Services Estimates; (iii) officers governed by the All India Service (M.A.) Rules, 1954; (iv) officers governed by the Medical Attendance Rules, 1955.
43. Medical Examination and Medical Boards for Central Civil Services other than those controlled by the Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and those paid from Defence Estimates excepting Civilian Services.
44. Indian Red Cross Society.
45. The Lady Harding Medical College and Hospital, New Delhi and the Kalavati Saran Children Hospital, New Delhi.
46. Vallabh Bhai Patel Chest Institute.
47. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay.
48. Spas and Health Resorts.
49. Collection and Collation of information with regard to local bodies, all States and Union Territories.
50. Trachoma Pilot Project.
51. Leprosy Control Scheme.
52. Reimbursement of customs duty on gifts of non-consumable medical stores received from abroad.
53. The Indian Council of Medical Research, New Delhi.
54. The All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
55. Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta.
56. Central Institute of Research on Indigenous Systems of Medicines, Jamnagar.
57. Post-Graduate Training Centre, Jamnagar.
58. Physiotherapy Training Centre, King Edward Memorial Hospital, Bombay.
59. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Madras.
60. All India Mental Health Institute, Bangalore.
61. Nutrition Research Institute, Coonoor.
62. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.
63. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in this list.
64. Fees in respect of any of the matters in this list, but not including fees taken in any court.

GI/85-7

'B' DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (PARIVAR KALYAN VIBHAG)

1. Policy and organisation for Family Planning.
2. Maternity and Child Welfare.
3. Organisation and direction of education training and research in all aspects of family planning including higher training abroad.
4. Production and supply of aids to family planning.
5. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to family planning.
6. Inquiries and statistics relating to family planning.
7. International Institute of Population Studies, Bombay.
8. Development and production of audio-visual aids, extension, education and information in relation to population and family planning.
9. Grant-in-aid for the family planning programme to voluntary organisations and local bodies.
10. Hindustan Latex Ltd.
11. National Institute of Family Planning, New Delhi.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURKSHA VIBHAG)

- I. Police
 1. Assam Rifles.
 2. Border Security Forces.
 3. Matters relating to National Policy Academy, the Central Detective Training School, the Bureau of Police Research and Development, the National Civil Defence College and the National Fire Service College.
 4. Matters relating to Indian Police Service including I.P.
 5. Matters relating to the Central Industrial Security Force.
 6. Matters relating to Civil Defence, Home Guards and Mobile Civil Emergency Force.
 7. Extension of the powers and Jurisdiction of members of a police force belonging to any State, to any area outside that State, but not so to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside the State.
 8. Inter-State Police Wireless System.
 9. Central Reserve Police.
 10. Police Medals.

II. Law and Order

11. The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985).

12. The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984—Establishment of special and Additional Courts, and all other matters, under that Act.

13. The administration of the North East Frontier Agency areas (i.e.) tribal areas of Assam specified in Part B of the Table appended to para 20 of the Sixth Schedule to the Constitution excluding administrative control over the execution of road works in those areas.

14. Intelligence Bureau, Coordination Wing, Central Forensic Science Laboratory, New Delhi, and Central Finger Print Bureau of the Central Bureau of Investigation.

15. Grant of visas and endorsements for entry into India, and the control of foreigners in India including grant of permission to travel to protected Areas in Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Nagaland, North East Frontier Agency and Manipur.

16. Grant of visas for India to Pakistan Nationals for permanent stay in India.

17. Deportation of nationals of foreign States from India.

18. Repatriation to Pakistan of released Pakistani prisoners.

19. Government servants having families in Pakistan—cases regarding grant of permission to Government servants to visit Pakistan.

20. Indian Frontier Administrative Service.

21. Matters relating to the Central Secretariat Security Organisation.

22. Prevention of the bringing into India of undesirable literature under Section 19 of the Sea Customs Act.

23. The Essential Services Maintenance Act, 1981.

24. Requisitioning of the services of Government servants for any duty during the period of operation of any Proclamation issued under clause (I) of Article 352 of the Constitution.

25. Preventive detention, except to the extent specifically allotted to any other Central Ministry or Department; persons subjected to such detention.

26. Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention.

27. Criminal Law.

28. Criminal Procedure.

29. Matters relating to the State of Nagaland.

30. Matters relating to the State of Sikkim.

31. The Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980.

32. Parliament Questions relating to crime on railways other than offences relating to pilferage of railway property.

33. Arms, fire-arms, ammunitions and matters relating to the Explosive Substances Act, 1908.

34. Development of Fuel Services.

III. Rehabilitation

35. Relief and Rehabilitation of displaced persons from former East Pakistan.

Relief includes :—

Establishment of camps, payment of cash doles, provision of other amenities and necessities.

Rehabilitation includes :—

Housing, training and employment; resettlement on land in business, industries and other non-agricultural occupations

36. Relief and Rehabilitation of repatriated Indian nationals.

37. Relief and Rehabilitation of Tibetan refugees.

38. Relief and Rehabilitation of displaced persons from Chhamb area in Jammu and Kashmir, Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority.

39. Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranya Development Authority.

40. Administration of Central Camps, work site camps and Karmi Shibir for displaced persons from former East Pakistan.

41. Rehabilitation Industries Corporation.

42. Residuary problems relating to displaced persons from former East Pakistan in West Bengal.

43. Residuary problems of refugees from Bangladesh.

44. Residuary problems of migrants from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir.

45. Development of such special areas as may be indicated by Prime Minister from time to time.

46. Relief and Resettlement of persons affected in the border areas of Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat and Rajasthan during the Indo Pak conflict, 1971.

47. Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan.

48. Administration of the following Acts :—

(a) Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).

(b) Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951).

(c) Displaced persons (Debts adjustment) Act, 1951 (70 of 1951).

(d) Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

(e) Displaced persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954).

(f) Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954 (15 of 1954).

(g) Matters relating to Goa, Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act, 1964.

49. Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.

50. Restoration of movable property received from former West Pakistan, now Pakistan, to the displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan.

51. Verification and payment of claims of displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan, who were Government servants in the undivided provinces, and local bodies in respect of pension, provident fund, leave salary and security deposits.

Ad-hoc schemes for payment of pension, G.P. Fund, leave salary and ex-gratia relief to displaced Government servants from former West Pakistan, now Pakistan, grant of relief to the contractors in respect of their verified claims; grant of relief to pensioners migrated from former East Pakistan and West Pakistan, now Pakistan, between 1-1-1961 and 25-3-1971.

52. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this part.

N.B.—Except where specified, the programmes of relief and rehabilitation are executed and administered through the State Governments.

DEPARTMENT OF STATES

(RAJYA VIBHAG)

1) Centre-State Relations

1. Establishment and formation of new States; matters arising therefrom [excepting those pertaining to allocation of service personnel, integration of Services and other matters relating to State Services allotted to the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasnik Sudhar Vibhag)] and alternation of areas, boundaries and names of existing States.

2. Matters relating to the Rules of former Indian States referred to in clause (22) of Article 366 of the Constitution and their families.

3. Constitutional provisions with respect to the State of Jammu & Kashmir and other matters relating to that State excluding those with which the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) is concerned.

Special provisions in Article 371 of the Constitution with respect to the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Bombay.

Inter-State Relations

Inter-State Council.

Inter-State Migration.

(c) Union Territories

7. Regulations applicable to the Andaman, Nicobar and Lakshadweep Islands.

8. Indian Administrative Service Cadre of the Union Territories, matters falling within the purview of State Government.

9. For the Union Territories of Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman and Diu, Mizoram and Pondicherry :

The following subjects which fall within the scope of matters enumerated in List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India :

(i) Public Order (but not including the use of naval, military or air force of the Union in aid of the civil power).

(ii) Police including railway and village police.

(iii) Prisons, reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature and persons detained therein; arrangements with other States for the use of persons and other institutions.

(iv) Constitution and powers of Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee.

(v) Delhi Fire Service.

(vi) Betting and gambling.

(vii) General questions relating to public services.

(viii) Offences against laws with respect to any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

(ix) Jurisdiction and powers of courts with respect to any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

(x) Fees in respect of any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution but not including fees taken in any court.

(xi) Extension of State Acts to the Union Territories.

(xii) Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters in List II of the Seventh Schedule to the Constitution.

(xiii) General questions relating to administration on subjects other than those dealt with in other departments.

10. For the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

All matters except :—

(a) forests, education, road and bridge works and ferries thereon; and

- (b) organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

11. For the Union Territory of Lakshadweep :—

All matters relating to these islands except organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

C. DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
(RAJBHASHA VIBHAG)

1. Implementation of the provisions of the Constitution relating to Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963, except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.

2. Prior approval of the President for authorising the limited use of a language other than English in the proceedings in the High Court of a State.

3. Nodal responsibility for all matters relating to the progressive use of Hindi as the official language of the Union, including Hindi teaching schemes for Central Government employees and publication of magazines, journals, and other literature related thereto.

4. Coordination in all matters relating to progressive use of Hindi as the official language of the Union including administrative terminology, syllabi, text-books, training courses and equipment (with standardised script) required therefor.

5. Constitution and Cadre management of the Central Secretariat Official Language Service.

6. Matters relating to Kendriya Hindi Samiti including its Up-samitis.

7. Coordination of work relating to the Hindi Salahkar Samitis set up by the various Ministries/Departments.

8. Matters relating to the Central Translation Bureau.

D. DEPARTMENT OF HOME
(GRIH VIBHAG)

1. Notification of assumption of office by the President and the Vice-President.

2. (i) Grants of pardons, reprieves, suspension, remission or commutation of a sentence of death; and

(ii) Petitions for remission of sentences (other than death sentences) or for pardon from prisoners sentenced by courts in states for offences against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends.

3. Issue of notifications of appointment and resignation of the Prime Minister and other Ministers and Parliamentary Secretaries of the Union.

4. Rules for the authentication of papers in the name of the President.

5. Model Rules of Business for State Government.

6. Nominations to Rajya Sabha and Lok Sabha.

7. Issue of notifications of appointment, resignation and removal of Governors, Lieut-Governors.

8. Bills passed by legislatures of States (except Jammu and Kashmir) reserved by Governors for the consideration of the President; and prior consultation with the Central Government by the State Governments as regards State Legislation.

9. Prior approval of the President to the promulgation of ordinances by Governors of States.

10. Appointment of Lieutenant Governors, Chief Commissioners and Administrative Officers in Union territories.

11. Property accruing to the Union by escheat or lapse or as bona vacantia.

12. Special provision relating to the language spoken by a substantial proportion of the population of a State.

13. Matters relating to the Emergency provisions of the Constitution (other than those relating to financial emergency).

14. Conventions with other countries in judicial matters including questions relating to International Court of Justice and references from the United Nations Organisation relating to obscene publications.

15. Citizenship and naturalisation.

16. Immigration from Foreign and Commonwealth countries, except the Union of South Africa, or any other country to which the Reciprocity Act applies.

17. Entry of persons, other than returning emigrants from Commonwealth countries, except those to which the Reciprocity Act applies.

18. Matters relating to Code of Conduct of Legislators.

19. Code of Conduct for Ministers.

20. Employment of wives or dependents of Government servants in foreign Missions in India.

21. Exchange of visits between Civil and Military Officers.

22. Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State.

23. Census of Population.

24. Official dress.

25. Emoluments, allowances, privileges and rights in respect of leave of absence of the President and Governors; salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries of the Union.

26. National Anthem.

27. National Flag of India; President's and Governor's Standards.

28. State Emblem.

29. Warrant of Precedence.
30. Awards and decorations.
31. National Festivals.
32. Matters relating to National Integration.

NOTE:—The Department of Home will be the nodal Department for overall policy, but the actual implementation of any individual aspect thereof will be the responsibility of the Ministry or Department concerned with that aspect.

33. Progressive use of National Calendar for official purposes.

34. Changes in geographical names.

35. Formalities to be observed on the death of high dignitaries in India.

36. Political pensions.

37. Compassionate allowance to dependents of mutiny veterans.

38. Home Minister's Discretionary Fund for the grant of relief to persons who served the nation by their work in political, social, philanthropic or other fields when they are in need of special assistance.

39. Poisons.

40. Vital Statistics including registration of births and deaths.

41. Newspapers, books and printing presses.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF EDUCATION

(SHIKSHA VIBHAG)

1. Pre-Primary Education.
2. Elementary Education.
3. Basic Education.
4. Secondary Education, Education and Vocational Guidance.
5. University education; Central Universities. Rural Higher Education; Foreign Aid Programme relating to Higher Education, Technical Education, Planning and Development of School Education.
6. Institutions of higher learning (other than Universities).
7. Bal Bhavan, Children's Museum.
8. Social Education and adult education.
9. Physical Education.
10. Audio Visual Education.
11. Books [other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana Prasarana Mantralaya) is concerned] and Book

Development [excluding stationery paper and newsprint industries with which the Ministry of Industrial Development (Audyogik Vikas Mantralaya) is concerned].

12. Production of University level text-books in Regional Languages.

13. The Copyright Act, 1957 and International Conventions on Copyrights.

14. Educational Research.

15. Publications, information and statistics.

16. Teachers' training.

17. Development and propagation of Hindi, including multi-lingual dictionaries.

18. Grant of Financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.

19. Propagation and development of Sanskrit.

20. Rehabilitation and other problems relating to displaced teachers and students.

21. Central Advisory Board of Education.

22. UNESCO and Indian National Commission for Cooperation with UNESCO.

23. All scholarships including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by this Department but excluding scholarships to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, denotified, nomadic and semi-nomadic Tribes, General Scholarships Scheme.

24. Education and Welfare of Indian students overseas; Education Departments of Indian Missions overseas; Financial assistance to educational institutions and Indian Students' Associations abroad.

25. Educational Exchange Programmes; exchange of teachers, professors, educationists, scientists, technologists, etc.; programme of exchange of scholars between India and foreign countries.

26. Grant of permission to teachers of Universities, colleges and institutions of higher learning to accept assignments abroad.

27. Admission of foreign students in Indian Institutions.

28. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

29. Ad hoc scientific research, other than research in higher mathematics, nuclear science and atomic energy, in universities and educational institutions.

30. Vigyan Mandirs.

31. General policy regarding partial financial assistance to Scientists going abroad for studies in fields other than mathematics, nuclear science and atomic Energy.

32. Expansion, Development and Co-ordination of Technical Education.

33. School of Planning and Architecture.

34. Regional Schools of Printing.

35. Grants-in-aid to State Government institutions, non-Government institutions, professional bodies and technical institutions of Union Territories for technical education. Grants-in-aid for post graduate studies in basic sciences, grants-in aid for development of higher scientific and technological education and research in educational institutions; Grants-in-aid for fundamental research in science and technology; grants to individuals for fundamental research.

36. All India Council for Technical Education.

37. Conduct of National Diploma and National Certificate examinations of the All India Council for Technical Education.

38. Practical training facilities for students of engineering and technological institutions.

39. Recognition of professional technical qualifications for purposes of recruitment to posts under Government of India.

40. National Research Professorships and Fellowships.

41. Holding of Foreign Examination in the fields of professional and technical education in India.

42. University Grants Commission.

43. National Council for Educational Research and Training.

44. National Book Trust.

45. Administrative Staff College of India, Hyderabad.

46. Indian School of Mines and Applied Geology, Dhanbad.

47. Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Bombay, Kanpur, Madras and Delhi.

48. Indian Institute of Science, Bangalore.

49. The Tata Institute of Social Sciences, Bombay.

50. International Students Houses in India and abroad.

51. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL VIBHAG)

1. Games, sports, boy scouts, girl guides, National Discipline Scheme, etc.

2. Youth Welfare activities, youth festivals, work camp, etc.

3. Sports Authority of India.

4. Youth Affairs.

5. Youth hostels.

C. DEPARTMENT OF ARTS

(KALA VIBHAG)

1. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).

2. National Theatre.

D. DEPARTMENT OF CULTURE

(SANSKRITI VIBHAG)

1 National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum. the Victoria Memorial and the India War Memorial and all other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.

2. Archaeology Archaeological Museums.

3. The Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958 and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

4. Grants to Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

5. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

6. History of Freedom Movement.

7. Jalianwala Bagh National Memorial Trust.

8. Administration of Gandhi Smriti Samiti and Gandhi Darshan.

9. The delivery of Books (Public Libraries) Act and the Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).

10. Promotion of fine arts.

11. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.

12. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits; General Development of Museums.

13. National Gallery of Modern Art, New Delhi.

14. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

15. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and Export of antiquities.

16. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

17. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochna aur Prasaran Mantralaya).

18. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

19. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

20. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of Modern Indian Languages

21. Publication of rare manuscripts.

22. Grants to all-India Cultural Institutions.

23. Grants to Indo foreign Cultural Societies.

24. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.

25. Distribution of gift books received from abroad.

26. Appointment of Cultural Attaches abroad.

27. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

28. Individuals (including cultural lecturers), sponsored by Government for visits abroad.

29. Presentation of books to foreign countries.

30. Establishment of libraries abroad.

31. Translation of Indian classics into foreign languages.

32. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

33. Presentation of Indian art objects abroad.

34. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

35. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.

36. Revision of Gazetteers.

37. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities.

38. Publication, information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.

39. International Congress of Orientalists.

40. Anthropological Survey of India.

41. National Archives of India.

42. Rashtriya Manava Sangrahalaya.

43. National Council of Science Museums, Calcutta.

44. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

45. Administration of Cinematograph Act, 1952, in respect of —

(i) Examination and certification of cinematograph films for public exhibition by the Central Board of Film Censors;

(ii) Central Board of Film Censors.

E. DEPARTMENT OF WOMEN'S WELFARE (MAHILA KALYAN VIBHAG)

1. Family Welfare.

2. Woman and child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.

3. References from the United Nations Organisation relating to traffic in Women and children.

4. Care of pre-school children.

5. Coordination of National Nutrition Programme, Nutrition feeding of pre-school children and Nutrition education of women.

6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

8. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

9. Administration of Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956.

10. Dowry Prohibition Act, 1961.

MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)

I. Industrial Policy.

1. General Industrial Policy.

2. Administration of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

3. Industrial Management.

4. Productivity in industry.

II. Industrial Co-operation.

5. Co-operation in the Industrial sector, excepting Co-operative Sugar Factories.

III. Industries and Industrial and Technical Development.

6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department, but including industries relating to bread, oilseeds meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

7. Administration of the Indian Boilers Act, 1923 and the regulations made thereunder. Central Boilers Board.

8. Explosives—Administration of the Explosives Act, 1884, and the rules made thereunder, but not the Explosive Substances Act, 1908.

9. Cables.

10. Light Engineering Industries (e.g. Sewing machines, typewriters, weighing machines, bicycles, etc.).

11. Light industries (e.g., Plywood, stationery, matches, cigarettes, etc.).

12. Light Electrical Engineering Industries.

13. Raw films.

14. Hard Board.

15. Paper and newsprint.

16. Tyres and Tubes.

17. Salt.

18. Cement.

19. Automotive Research Association, Poona.

20. Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore.

21. Cement Research Institute of India. Faridabad, Haryana.

22. Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Bombay.

23. Technical Development, including Directorate General of Technical Development:

IV. Small Scale Industries

24. Co-ordination of the Development of small-scale Industries :—

(i) Small Industries Board.

(ii) National Small Industries Corporation Limited.

(iii) Setting up of new Industries, for providing employment, in places where there are heavy concentrations of displaced persons from West Pakistan.

25. Village and cottage industries

26. Coordination of matters relating to Rural Industrialisation.

27. Soaps and Detergents.

V. Patents and Designs etc.

28. Standardisation of international products and raw materials.

29. Designs Act, 1911.

30. Patents Act, 1970.

VI. Materials Planning

31. Coordinated assessment of demands for raw materials, by sectors, industries and large-units, in relation to particular groups of products and to available capacities.

32. Assessment of domestic availability of raw materials with due regard to the feasibility of import substitution.

33. Assessment of requirements of imports of raw materials, with due allowance for inventories.

34. Determination of principles, priorities and procedures for allocation of raw materials.

35. Coal Industry.

36. The Coir Board.

37. Any other matters connected with materials planning.

VII. Other Subjects.

38. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

39. Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

40. Coordination of matters of general policy of non-financial nature affecting all public sector industrial and commercial undertakings.

41. Manufacture of heavy engineering equipment for all industries.

42. Heavy electrical engineering industries.

43. Machinery Industries including Machine Tools and Steel Manufactures.

44. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.

45. All types of diesel engines.

B. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
(KAMPANI KARYA VIBHAG)

1. Administration of the Companies Act, 1956.

2. Administration of the Companies (Donations to National Funds) Act, 1951.

3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

4. Profession of Accountancy (Chartered Accountants Act, 1949), profession of Costs and Works Accountancy (Cost and Works Accountants Act, 1959); Profession of Company Secretaries (Company Secretaries Act, 1980).

5. Collection of Statistics relating to companies.

6. Legislation relating to law of Partnership, and the exercise of certain functions under Chapter VIII of the Indian Partnership Act, 1932 in centrally administered areas (The administration of the Act vests in the State Governments).

7. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.

8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.

C. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

1. Drugs and Pharmaceuticals.

2. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968))

3. Molasses—distribution and pricing.

4. Alcohol.—Industrial and potable including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).

5. Dye-stuffs and dye-intermediates.

6. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.

7. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

9. Public sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

10. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

11. Bhopal Gas Leak Disaster.—Special Laws relating thereto.

12. Petro-Chemicals.

13. Industries relating to production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon, Polyester, Acrylic, etc.).

14. Synthetic Rubber.

15. Plastics, including fabrications of plastic and plastic moulded goods.

16. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by this Department.

17. All public sector units relating to the above matters.

18. All attached and subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SARKARI UDYAM VIBHAG)

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.

2. The Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi.

3. The Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur.

4. The Triveni Structurals Limited, Allahabad.

5. The Thungabhadra Steel Products (India) Limited, Durgapur.

6. The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited.

7. The Engineering Projects (India) Limited.

8. Bharat Brakes and Valves Ltd.

9. Bharat Heavy Electricals Limited.

10. Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd.

GI/85—8

11. Bharat Pumps and Compressors Ltd.

12. Bharat Wagon and Engineering Co. Ltd.

13. Bhautwaite and Co. Ltd.

14. Burn Standard Co. Ltd.

15. H.M.T. Bearings Ltd.

16. H.M.T. Ltd.

17. H.M.T. International Ltd.

18. Jessop and Co. Ltd.

19. The Lagan Jute Machinery Co. Ltd.

20. Maruti Udyog Ltd.

21. Richardson and Cruddas (1972) Ltd.

22. Scooters India Ltd.

23. Weighbird (India) Ltd.

24. Braitwaite, Burn and Jessop Construction Ltd.

25. Hooghly Dock and Port Engineers Ltd.

26. Andrew Yule and Co. Ltd.

27. Banarhat Tea Co. Ltd.

28. Basmatia Tea Co. Ltd.

29. Bharat Leather Corporation Ltd.

30. Bharat Ophthalmic Glass Ltd.

31. Cement Corporation of India Ltd.

32. Cycle Corporation of India Ltd.

33. Hindustan Cables Ltd.

34. Hindustan Paper Corporation Ltd.

35. Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd.

36. Hindustan Salts Ltd.

37. Hooghly Printing Co. Ltd.

38. Hoolungoree Tea Co. Ltd.

39. Instrumentation Ltd.

40. The Mandya National Paper Mills Ltd.

41. The Mim Tea Co. Ltd.

42. Murphulani (Assam) Tea Co. Ltd.

43. Nagaland Pulp and Paper Co. Ltd.

44. National Bicycle Corporation of India Ltd.

45. The National Industrial Development Corporation Ltd.

46. National Instruments Ltd.

47. National Newsprint and Paper Mills Ltd.

48. The National Small Industries Corporation Ltd.

49. Raigarh Tea Co. Ltd.

50. Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.

51. Hindustan Newsprint Ltd.

52. Damodar Cement and Slag Ltd.

53. Sambhar Salts Ltd.

54. Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.

55. Tyre Corporation of India.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)

I. Radio

1. All business connected with All India Radio (except issuing of B.R. Licences) embracing news services in the home programmes, programmes for the foreign countries and Indian overseas, radio journals, researches in the field of broadcast engineering, monitoring of foreign broadcasts, programme exchange and transcription services, television, supply of community receiving sets to State Governments under the community listening scheme, etc.

2. Development of Broadcasting throughout the Union, installation and maintenance of Radio Stations transmitters.

II. Films.

3. (i) Import of films feature-length and shorts for Theatrical and non-Theatrical use;
- (ii) Export of Indian films-feature-length and shorts;

(iii) Import and distribution of cine-film (un-exposed) and other goods required by the film industry.

4. (i) Production and distribution of documentaries and newsreels and other films and film strips for internal and external publicity.

(ii) Creation of distribution and exhibition chains for films.

5. Development and promotional activities relating to film industry, including teaching and research.

6. (i) Legislation under entry 60 of the Union List, viz., "Sanctioning of Cinematograph Films for Exhibition".

(ii) Administration of Cinematograph Act, 1952, including regulation of exhibition by means of cinematograph in Union Territories, but excluding examination and certification of cinematograph films for public exhibition by the Central Board of Film Censors;

7. Grant of State awards for films produced in India.

8. Grants to Children's Film Society.

9. Implementation of the recommendations of the Film Enquiry Committee.

10. The National Film Corporation and the Indian Motion Pictures Export Corporation (IMPEC).

III. Advertising and Visual Publicity.

11. Production and release of all display advertisements of the Government of India through the media of press, posters, folders calendars, blotters, leaflets, hoarding, cinema slides, etc. also release of classified advertisements on behalf of the Government of India.

12. Preparation of media lists.

IV. Press

13. Presentation and interpretation of the policies and activities of the Government of India through the medium of the press.

14. Advising Government on information problems relating to the Press, keeping Government informed of the main trends of public opinion as reflected in the Press and liaison between Government and the Press.

15. Publicity to and for the Armed Forces.

16. General conduct of Government relations with the Press excluding the administration of Sections 95 and 96 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

17. Administration of the Press and Registration of Books Act, 1867 relating to Newspapers.

18. Administration of the Newspaper (Price and Page) Act, 1956.

19. Implementation of the recommendations of the Press Commission.

V. Publications

20. Production, sale and distribution of popular pamphlets, books and journals on matters of national importance for internal as well as external publicity with a view to imparting to the general public at home and abroad upto date and correct information about India.

VI. Research and Reference

21. (i) To assist the Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya) in collection, compilation and preparation of material involving research into published works, etc.; and

(ii) Building up of a compendium of knowledge on important subjects and to prepare guidance and background notes on current and other topics for the use of the Media Units of the Ministry.

22. Publicity for the Five Year Plan.

23. Financial assistance to distinguished musicians, both vocal and instrumental, dancers and dramatists who have contributed substantially to the success of All India Radio and other Units of this Ministry or their survivors in indigent circumstances.

24. Attached and subordinate Organisations :—

- (a) All India Radio.
- (b) Films Division.
- (c) Five Year Plan Publicity Unit.
- (d) Directorate of Advertising and Visual Publicity.
- (e) Press Information Bureau.
- (f) Publications Division.
- (g) Research and Reference Division.
- (h) Office of the Registrar of Newspapers for India.

25. All matters relating to the Asian Broadcasting Union, Commonwealth Broadcasting Association and the Non-aligned News Agency Pool.

MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)

PART I. Union subjects

1. In respect of Union Railways.—payment of wages, trade disputes, hours of work from employees not covered by the Factories Act, and regulation of employment of children.

2. In respect of Docks.—regulation of safety, health and welfare measures concerning dock labour.

3. Regulation of labour and safety in mines and oilfields.

PART II. Concurrent subjects

4. Factories.

5. Welfare of labour.—industrial, commercial and agricultural conditions of labour; provident funds, family pension, gratuity employers liability and workmen's compensation; health and sickness insurance, including invalidity pensions, old age pensions, improvement of working conditions in factories; canteens in industrial undertakings.

6. Unemployment Insurance.

7. Trade Unions; industrial and labour disputes.

8. Labour statistics.

9. Employment and unemployment except rural employment and unemployment.

10. Vocational and technical training of craftsmen.

PART III. Additional business for Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Delhi.

11. Items mentioned in Part II above.

PART IV. Incidental business with respect to any of the matters mentioned in Parts I, II and III above.

12. The implementing of treaties and agreements with other countries.

13. Offences against laws.

14. Inquiries and Statistics.

15. Fees, but not fees taken in any court.

16 Jurisdiction and powers of all courts (except the Supreme Court).

PART V. Miscellaneous Business.

17. Employment Exchanges.

18 Schemes for training of instructors, craftsman, technicians at foreman and supervisory level, both in India and abroad, apprentice training.

19. International Labour Organisation.

20. Tripartite Labour Conferences.

21. War Injuries (Compensation Insurance) Act, 1943, and Scheme.

22. Administration of laws connected with safety and welfare in mines other than coal mines; organisations of the Chief Inspector of Mines and Mica Mines Welfare.

23. Administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and the Regulations made thereunder and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.

24. Administration of the Tea Districts Emigrant Labour Act and the Organisation of the Controller of Emigrant Labour.

25. All emigration under the Emigration Act, 1922 (7 of 1922) from India to overseas countries and the return of emigrants.

26. Administration of the Minimum Wages Act.

27. Administration of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).

28. Administration of Labour laws in central sphere undertakings.

29. Labour Statistics; Organisation of Director, Labour Bureau.

30. Organisation of Chief Labour Commissioner and Constitution and administration of Central Government Industrial Tribunal, Central Government Labour Courts, National Industrial Tribunal.

31. Organisation of Chief Adviser Factories, including Central Labour Institute, productivity and TWI Centres and Regional Museums of Safety, Health and Welfare.

32. Plantation Labour and administration of Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).

33. Recruitment, posting, transfer and training of Government Labour Officers.

34. Administration of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

35. Schemes regarding workers' education.

36. Schemes regarding workers' Participation in management.

37. Discipline in industry.

38. Constitution of Wage Boards for individual industries.

39. Regulation of working condition of motor transport workers.

40. Evaluation of the implementation of Labour Laws in the country.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

(VIDHI KARYA VIBHAG)

1. Advice to Ministries on legal matters, including interpretation of laws, legal proceedings and conveying.

2. Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

3. Conduct of cases in the Supreme Court on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

4. Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits, for the execution of decrees of Civil courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.

5. Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

6. Indian Legal Service.

7. Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

8. Law Commission.

9. Legal Profession.

10. Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers; persons entitled to practice before the Supreme Court; references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

11. Persons entitled to practice before High Courts.

12. Administration of the Notaries Act, 1952.

13. Admiralty jurisdiction.

14. Income-tax Appellate Tribunal.

15. Foreign Exchange Regulation Appellate Board.

16. Legal aid to the poor.

B. LEGISLATIVE DEPARTMENT

(VIDHAYEE VIBHAG)

1. The drafting of Bills, including the business of the Draftsmen in Select Committees; drafting and promulgation of Ordinances and Regulations; enactment of State Acts as Presidents' Acts whenever required; scrutiny of statutory Rules and Orders.

2. Constitution Orders; notifications for bringing into force Constitution (Amendment) Acts.

3. (a) Publication of Central Acts, Ordinance and Regulations;

(b) Publication of authorised translations in Hindi of Central Acts, Ordinances, Orders, Rules, Regulations and bye-laws referred to in section 5(1) of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

4. Compilation and publication of unrepealed Central Acts, Ordinances and Regulations of general statutory Rules and Orders, and other similar publications.

5. Elections to Parliament, to the Legislatures of States, to the Offices of the President and Vice-President; and the Election Commission.

6. Preparation and publication of standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages.

7. Preparation of authoritative texts in Hindi of all Central Acts and of Ordinances promulgated and Regulations made by the President and of all rules, regulations and orders made by the Central Government under such Acts, Ordinances and Regulations.

8. Making arrangements for the translation into official languages of the States of Central Acts and of Ordinances promulgated and Regulations made by the President and for the translation of all State Acts and Ordinances into Hindi if the texts of such Acts or Ordinances are in a language other than Hindi.

9. Publication of law books and law journals in Hindi.

The following subjects, which fall within list III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards Legislation only)—

10. Marriage and divorce; infants and minors; adoption; wills; intestate and succession; joint family and partition.

11. Transfer of property other than agricultural land, registration of deeds and documents.

12. Contracts, but not including those relating to agricultural land.

13. Actionable wrongs.

14. Bankruptcy and insolvency.

15. Trusts and trustees, Administrators General and Official Trustees.

16. Evidence and oaths.

17. Civil procedure including Limitation and Arbitration.

18. Charitable and religious endowments and religious institutions.

Other Subjects

19. The Wakf Act, 1954.

20. Work in respect of Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950.

21. Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955.

C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)

1. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances.

2. Appointment, resignation and removal etc. of Chief Justice and Judges of High Courts in States; their salaries, rights in respect of leave of absence (including leave allowances), pensions and travelling allowances.

3. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial officers in Union Territories.

4. Constitution and organisation (excluding jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but including contempt of such Court) and the fees taken therein.

5. Constitution and organisation of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners except provisions as to officers and servants of these courts.

6. Administration of justice and constitution and organisation of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.

7. Court fees and Stamp duties in the Union Territories.

8. Creation of all India Judicial Service.

9. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories.

10. Extension of the Jurisdiction of a High Court to a Union Territory or exclusion of a Union Territory from the jurisdiction of a High Court.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM

(SANSADIYA KARYA AUR PARYATAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SANSADIYA KARYA VIBHAG)

1. Dates of summoning and prorogation of the two Houses of Parliament : dissolution of Lok Sabha, President's address to Parliament.

2. Planning and coordination of legislative and other official business in both Houses.

3. Allocation of Government time in Parliament for discussion of motions given notice of by Members.

4. Liaison with Leaders of Groups and Deputy Chief Whips.

5. Lists of Members of Select and Joint Committees on Bills.

6. Appointment of Members of Parliament on Committees and other bodies set up by Government.

7. Functioning of Consultative Committees of Members of Parliament for various Ministries.

8. Implementation of assurances given by Ministers in Parliament.

9. Government's stand on Private Members' Bills and Resolutions.

10. Secretarial assistance to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.

11. Salaries and Allowances of Members of Parliament Act.

12. Salaries and Allowances of the Officers of Parliament Act.

13. Advice to Ministries on procedural and other Parliamentary matters.

14. Coordination of action by Ministries on the recommendations of general application made by Parliamentary Committees.

15. Officially sponsored visits of Members of Parliament to places of interest.

16. Matters connected with powers, privileges and immunities of Members of Parliament.

B. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)

1. Development of Tourism.

2. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels/Motels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(KARMIK AUR PRASHIKSHAN, PRASHA- SANIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)

I. Recruitment, Promotion and Morale of the Services.

1. Reservation of posts in Services for certain classes of citizens.

2. General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railways Services and services under the control of the Department of Atomic Energy (Paramanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Elektroniki Vibhag), the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical Services under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag).

3. General policy regarding age limits, medical standards, educational qualifications and recognition of non-technical degrees/diplomas for appointment to Government service.

4. General policy matters regarding classification of posts and grant of gazetted status in relation to Services other than Railway Services.

5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its attached offices except that for the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

6. Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

7. General policy regarding employment assistance to persons of Indian origin coming from various countries.

8. Concessions to War Service candidates in respect of appointments to Civil posts and services.

9. General policy regarding resettlement of displaced Government servants from areas now in Pakistan and retrenched temporary employees.

10. Concessions to political sufferers in the matters of first appointment or reappointment to the public services.

11. General policy regarding grant of extension to or re-employment of superannuated officers.

12. Issue of certificates of eligibility for appointment of Civil Services and posts under the Union in respect of persons other than Indian citizens.

13. (a) Deputation of Indian experts abroad under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) and on bilateral basis of the developing countries of Asia, Africa and Latin America.

(b) Deputation of officers or placements with the United Nations and its allied agencies as also with other international agencies like ILO, FAO, etc.

14. General policy regarding verification of character and antecedents suitability of candidates for appointment to Government service.

15. Policy matters relating to issue of No Objection certificate to serving personnel for registration with the Employment Exchange for higher posts.

16. Matters relating to Personal Staff of Ministers.

17. Re-deployment of staff rendered surplus in Central Government offices as a result of :—

(i) administrative reforms

(ii) studies made by the S.I.U.

(iii) winding up of long term but temporary organisations.

18. Advising Ministries on proper management of various cadres under their control.

II. Training.

(19) (a) Formation and coordination of training policies for the All India and Central Services.

(b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Institute of Secretariat Training and Management.

(c) Training programmes for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

(d) Preparation and publication of training material and of information of training techniques, facilities and programmes.

(e) Liaison with training institutions within the States and abroad.

(f) Refresher and special courses for Middle and Senior Management levels.

III. Vigilance and Discipline.

20. (a) The Prevention of Corruption Act, 1947; the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division, and the Administration Division); the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.

(b) Accord of sanction for the prosecution of any person for any offence investigated into by the Delhi Special Police Establishment where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

Note : Sanction for the prosecution of any person for any offence not investigated into by the Delhi Special Police Establishment shall be accorded by the Administrative Department where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

(c) Central Vigilance Commission.

(d) All policy matters pertaining to vigilance and discipline among public servants.

(e) Relationship between Members of Parliament and the Administration.

IV. Service Conditions.

21. General questions (other than those which have a financial hearing) including Conduct Rules relating to All India and Union Public Services except in regard to services under the control of the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

22. Conditions of service of Central Government employees (excluding those under the control of the Department of Railways (Rail Vibhag), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag),

the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical personnel under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag), other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests.

23. (a) The administration of all service rules including F.Rs, S.Rs. and C.S.Rs. (but excluding those relating to Pension and other retirement benefits) except :—

- (i) proposals relating to revisions of pay structure of employees ;
- (ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees ;
- (iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendation and implementation thereof ;
- (iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances ;
- (v) any new facility to Government employees by way of service conditions of fringe benefits which involve significant recurring financial implications ; and
- (vi) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character.

(b) Initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits, involving significant recurring financial implications.

(c) Issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vi) of clause (a).

(d) Relaxation and liberalisation of any service rules having a long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance.

24. Grants to the Indian Institute of Public Administration.

25. Leave travel concession for civil employees other than Railway employees.

26. The Central Services (Temporary Service) Rules, 1949.

27. General policy regarding retrenchment and revision of temporary Government servants except those under the Department of Railways (Rail Vibhag).

28. Administration of the Central Services (Safeguarding of National Security) Rules.

29. Uniforms for Class IV and other Government servants in the Central Secretariat, and its attached offices.

30. Working Hours and Holidays for Government of India offices.

21. Administration of service rules with financial content under specific delegation made by the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

32. Advice on proposals in respect of the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) relating to the number or grade of posts to the strength of a service or to the pay and allowances of Government servants or any other conditions of their service having financial implications.

33. General policy regarding reimbursement of legal expenses incurred by Government Servants.

34. Proposals for grant of ex-officio Secretarial status.

35. Honorary appointments of persons in civil posts.

36. Oath of allegiance to the Constitution.

V. Senior and Middle Management.

37. All aspects of Senior Management (i.e. Joint Secretaries and above and their equivalents) including developments of personnel for it.

38. (a) Establishment Officer to the Government of India.

(b) Appointments Committee of the Cabinet.

(c) Central Establishment Board.

(d) Career Development for Middle Management (i.e. Directors, Deputy and Under Secretaries and equivalents).

VI. Government Employees Relations, including Staff Grievances and Welfare.

39. (a) Service Associations of the industrial and non-industrial employees of the Government of India.

(b) Joint Consultative Machinery ; Departmental Council for the Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).

(c) Machinery for the redress of staff grievances.

(d) Staff welfare including sports, cultural activities, Grih Kalyan Kendras, Canteens, Cooperative Stores etc.

(e) Other matters involving Government Employees relations not specifically provided for under any other entry relating to this Ministry.

VII. Union Public Services Commission

40. Union Public Service Commission.

VIII. Centralised aspects of Managing IAS, Inter-Ministry cadres including a Career Planning for the members thereof.

41. (a) Creation of new All India Services.

(b) Rules and Regulations under the All India Services Act, 1951.

(c) All matters relating to the Indian Administrative Service including the Indian Civil Service.

(d) All India Civil List and History of Services

(e) Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers' Service and Central Secretariat Clerical Service.

IX. Career Planning and Manpower Planning.

42. (a) General Policy questions regarding Career Planning and Manpower Planning for the All India and Central Government Services.

(b) All matters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

X. Personnel Management Agencies.

43. Co-ordination of the work of personnel management agencies within various Ministries and Departments.

XI. Research in Personnel Administration etc :

44. Research in Personnel Administration ; liaison with State Governments, professional institutions etc., in personnel matters.

XII. Allocation of Personnel and integration of Services as a Result of States re-organisation.

45. (a) Allocation of service personnel affected by re-organisation of States.

(b) Division and integration of services affected by the re-organisation of States other than the Union Territories.

(c) Protection of service conditions of personnel affected by re-organisation of States. /

(d) Other matters relating to State Services affected by the re-organisation of States.

B. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES

(PRASHASNIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT VIBHAG)

1. Administrative Reforms.

2. Organisation and methods.

3. Policy and Coordination of issues relating to

(i) Redressal of Public Grievances in general; and

(ii) Grievances pertaining to Central Government agencies.

C. DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

(PENSION AUR PENSION BHOGI KALYAN VIBHAG)

1. Administration of all schemes relating to retirement benefits to Central Government employees including—

(i) Gratuity;

(ii) Pension rules Central Service (Pension) Rules 1972, Pension Regulations for Army 1961 (Parts I and II), Pension Regulations for Air Force 1961, Navy (Pension) Regulations 1964, Freedom Fighters Pension, Commutation of Pension, Disability Pension, Family Pension;

(iii) Pension structure and relief to pensioners;

(iv) New facilities or fringe benefits to Government pensioners; and

(v) Matters relating to amendment, relaxation of Pension Rules/other rules concerning retirement benefits.

The action in respect of (iii) above will be in consultation with and subject to concurrence by Ministry of Finance (Vitta Mantralaya). The action in respect of (iv) and (v) above involving significant recurring financial implications or having predominantly financial character only will be in consultation with and subject to concurrence by Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

2. Pension matters which are administered by the Department of Railways (Rail Vibhag) will be outside the purview of the Department.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)

1. Exploration for, and exploitation of petroleum resources, including natural gas.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, including natural gas and petroleum products.

3. Oil Refineries, including Lube Plants.

4. Additives for petroleum and petroleum products.

5. Tube Blending and greases.

6. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Ministry.

7. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

8. Planning, development and regulation of oilfield services.

9. Public sector projects falling under the subjects included in this list. Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry/Department.

10. The Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948).

11. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959).

12. The Petroleum Pipelines [(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)].

13. The Esso (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974)].

14. The Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974).

15. The Burmah-Shell [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976)].

16. The Caltex [(Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Act, 1977 (17 of 1977).

17 Administration of the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder.

MINISTRY OF PLANNING

(YOJANA MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PLANNING

(YOJANA VIBHAG)

Responsibility to Parliament in regard to the subjects of national planning.

B. DEPARTMENT OF STATISTICS

(SANKHYIKI VIBHAG)

1. Standards and norms and methods of collection of Statistics.

2. Central Statistical Organisation.

3. National Sample Survey.

4. Indian Statistical Institute.

5. Computer Centre.

6. Centralised aspects of managing the Indian Statistical Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that service.

MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION

(KARYAKRAM KARYANAVAYAN MANTRALAYA)

1. Monitoring the implementation of projects and programmes.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI VIBHAG)

1. Formulation of policy statements and guidelines in science and technology.

2. Science Advisory Committee to the Cabinet (SACC).

3. Promotion of new areas of science and technology.

4. Futurology.

5. Coordination of areas of science and technology in which a number of institutions and departments have interests and capabilities.

6. Undertaking or financially sponsoring scientific and technological surveys, research design and development, where necessary.

7. Support and Grants-in-aid to Scientific Research Institutions, Scientific Associations and Bodies.

8. International Scientific and Technological Affairs, including :—

(a) the negotiations and implementation of Scientific and Technological Cooperation Agreements and responsibility for the scientific and technological aspects of activities of international organisations; and

(b) appointment of scientific Attaches abroad.

Note : These functions shall be exercised by the Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag) in close cooperation with the Ministry of External Affairs (Videh Mantralaya).

9. Scientific Surveys :

(i) Survey of India;

(ii) National Atlas & Thematic Mapping Organisation.

10. India Meteorological Department.

11. (i) Institute of Astro-physics;

(ii) Institute of Geo-magnetism;

(iii) Institute of Tropical Meteorology.

12. National Council of Science & Technology Communication.

13. National Science and Technology Entrepreneurship Development Board.

14. National Biotechnology Board.

15. Matters commonly affecting scientific and technological institutions e.g. financial, personnel, purchase and import policies and practices.

16. Management Information Systems for Science and Technology and coordination thereof.

17. Matters regarding Inter-Agency Inter-Departmental coordination for evolving science and technology missions.

18. Matters concerning domestic technology particularly the promotion of ventures involving the commercialisation of such technology other than those under the Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

19. All other measures needed for the promotion of science and technology and their application to the development of security of the nation.

B. DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(VIGYAN AUR AUDYOGIK ANUSANDHAN VIBHAG)

1. All matters concerning the Council of Scientific and Industrial Research.

2. All matters relating to National Research Development Corporation.

3. All matters relating to Central Electronics Limited.

4. National Information System on Science and Technology (NISSAT).

5. Registration and Recognition of R&D Units.

6. Matters relating to UNCTAD & WIPO.

7. National register for foreign collaborations.

8. Matters relating to creation of a pool for temporary placement of Indian Scientists and Technologists.

9. National register of Scientific Manpower.

MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF STEEL

(ISPAT VIBHAG)

1. Steel plants in the public and private sectors, the re-rolling industry and ferro-alloys, including all future developments.

2. Development of iron ore mines in the public sector.

3. Development of other ore mines and coal washeries and mineral processing for the steel plants.

4. Production, distribution, prices, imports and exports of iron and steel and ferro-alloys.

5. Planning, development and control of, and assistance to, all iron and steel industries.

6. Production, supply, pricing and distribution of iron ore, manganese ore, limestone, sillimanite, kyanite and other minerals and alloys used in steel industry, excluding grant of mining leases or matters connected therewith.

7. The Steel Authority of India Limited and its subsidiaries.

8. Matters relating to the following undertakings, namely :—

(1) The Mysore Iron and Steel Company Ltd.

(2) The Bolani Ores (India) Ltd.

(3) The Manganese Ore (India) Ltd.

(4) The Metals Scrap Trading Corporation.

9. Other Public Sector Enterprises or Undertakings falling under the subjects included in this list, except such as are specifically allotted to any other Department.

10. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. DEPARTMENT OF MINES

(KHAN VIBHAG)

1. Regulation of mines and development of minerals other than coal and lignite and sand for stowing under the Mines and Minerals (Regulation and

Development) Act, 1957, and other Union Law including questions concerning various States and incidental business in respect of these.

2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.

3. Planning development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

4. Geological Survey of India.

5. Indian Bureau of Mines.

6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

7. The Sikkim Mining Corporation Limited.

8. Public Sector enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except such as are specifically allotted to any other Department.

9. Metallurgical Grade Silicon.

MINISTRY OF TRANSPORT

(PARIWAHAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF RAILWAYS

(RAIL VIBHAG)

1. Government Railways—All matters, including those relating to Railway revenues and expenditure, but excluding Railway Inspectorate and Railway Audit.

2. Non-Government Railways—Matters in so far as provision for control by the Department of Railways (Rail Vibhag) (Railway Board) is provided in the Indian Railways Act, or in the contracts between the Government and the Railways, or in any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares etc.

3. Parliament Questions regarding offences relating to pilferage of railway property other than offences relating to crime on Government Railways and Non-Governmental Railways.

B. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (NAG VIMANAN VIBHAG)

1. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic of aerodromes excepting Sanitary Control of navigation.

2. Beacons and other provision for the safety of aircraft.

3. Carriage of passengers and goods by air.

4. International Civil Aviation Organisation (ICAO)

5. International Air Transport Association (IATA)

6. Commonwealth Air Transport Council (CATC)

7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.

8. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

9. Hotel Corporation of India

10. Chief Commissioner of Railway Safety.

11. International Airports Authority of India

12. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.

13. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

14. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.

15. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.

C. DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (JAL-BHOOTAL PARIWAHAN VIBHAG)

1. The following subjects which fall within list I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.

2. Lighthouses and lightships.

3. Major ports i.e. the ports of Calcutta, Bombay, Madras, Visakhapatnam, Cochin and Kandla.

4. Compulsory insurance of motor vehicles.

5. Administration of the Road Transport Corporation Act, 1950.

6. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

7. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.

8. Ship-building and Ship-repair industry.

9. Fishing vessels industry.

10. Floating craft industry.

In respect of the Union Territories :

11. Roads other than National Highways.

12. Tramways within municipal limits.

13. Inland waterways and traffic thereon.

14. Administration of the Motor Vehicle Act, 1939 and taxation of motor vehicles.

15. Vehicles other than mechanically propelled ones.

In respect of the Union Territories of Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands.

16. Organisation and maintenance of mainland-islands and intershipping services.

Other subjects which have not been included in the previous sub-heads.

17. Central Road Fund.

18. Coordination and Research pertaining to Road Works.

19. Road Works financed in whole or in part by the Central Government including road works in Sikkim and the tribal areas of Assam specified in parts A and B of the table appended to para 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

20. Motor vehicles legislation.

21. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.

22. Planning of Road and inland waterways Transport.

23. Promotion of Transport Cooperatives in the field of motor transport and inland water transport.

24. Development of townships of Gandhidham.

25. Legislation relating to and co-ordination of the development of minor ports.

26. Centralised arrangements for the servicing and repairs of staff cars belonging to the Central Government, except those under the control and use of Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

27. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions: -

(i) Those belonging to the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya), the Department of Railways (Rail Vibhag) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag);

(ii) Buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil works budget; and

(iii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union Territories, excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Railways, P&T and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of this Ministry. Location or dispersal of offices in or from the Metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952.

8. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation) Act, 1949.

9. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

10. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamala Market.

11. Formulation of housing policy and programme (except nodal responsibility for housing for landless rural labour which is assigned to the Department of Rural Development). Review of the implementation of the Plan Schemes. Collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques. General measures for reduction of building costs.

12. Human Settlement, including the United Nations Commission for Human Settlement and International Cooperation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlement.

13. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.

14. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpuri Removal Schemes. International Co-operation and technical assistance in this field.

15. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas. International Co-operation and technical assistance in this field.

16. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.

17. Delhi Development Authority.

18. Master Plan of Delhi, Co-ordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the Union Territory of Delhi.

19. Erection of memorials in honour of freedom fighters.

20. Administration of the Delhi Development Act, 1957.

21. The Delhi Rent Control Act, 1958.

22. Development of Government Colonies.

23. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), District Boards and other Local Self-Government Administrations, excluding Panchayati Raj institutions.

24. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

25. Water Supply, sewage and drainage (excluding rural water supply which is assigned to the Department of Rural Development). Drinking water supply and sanitation. International co-operation and technical assistance in this field.

26. The Central Council of Local Self-Government.

27. Allotment of Government land in Delhi.

28. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

29. Public Sector Projects falling under the subject included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.

30. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

31. Delhi Urban Art Commission, Delhi Urban Art Commission Act, 1973.

32. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALAYA)

1. General Policy, technical assistance, research and all matters relating to irrigation, including minor and megalicity irrigation works, tubewells and ground water exploration, irrigation for agricultural purposes, flood control, anti-water logging, drainage and anti-sea erosion.

2. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys.

3. Administration of the River Boards Act, 1956.

4. Administration of the Inter-State Water Disputes Act, 1956.

5. Central Water Commission.

6. Central Flood Control Board.

7. Farraka Barrage Project.

8. Indus Water Treaty, 1960.

9. International Commissions and Conferences relating to irrigation and flood control.

10. Irrigation and Flood Control Schemes in Union Territories.

11. Water and Power Consultancy Service (WAPCOS).

MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)

Part I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Operation of Indo-US, Indo-UK, Indo-German, Indo-Swiss and Indo-Swedish Agreements for duty free receipt of donated relief supplies/goods and materials connected with the distribution of supplies coming there under.

Part II

The following subject which falls within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only) :

2. Social Security and Social Insurance save to the extent allotted to any other Department.

Part III

For the Union Territories, the following subject which falls within List II or List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India, in so far as they exist in regard to such Territories :

3. Relief of the disabled and unemployable and measures relating to social security and social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

Part IV

General and Consequential :

4. Social Welfare : Social Welfare Planning, Project formulation, research, evaluation, statistics and training.

5. Conventions with other countries in matters relating to social defence and references from United Nations Organisation relating to prevention of crime and treatment of offenders.

6. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans and orphanages.

7. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

8. Education, training, Rehabilitation and Welfare of the physically and mentally handicapped.

9. National Institute for the Physically Handicapped and Mentally Retarded.

10. National Centre for the Blind including the Central Braille Press, Dehra Dun, Training Centre for the Adult Deaf, and School for the partially deaf children, Hyderabad; Model School for Mentally retarded Children, New Delhi and other national institutes.

11. Central Social Welfare Board.

12. Social and Moral Hygiene Programme.

13. Beggary; Juvenile vagrancy, delinquency and other CARE Programmes.

14. Probation of Juvenile offenders.

15. Research, evaluation, training, exchange of information and technical guidance on all social defence matters, including correctional services.

16. All matters relating to prohibition.

17. Educational and social welfare aspects of drug addiction.

18. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Ministry.

19. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

20. National Institute of Public Cooperation and Child Development.

21. National Institute of Social Defence.

22. Atomic Glass Manufacturing Corporation of India, Kanpur (AAGMCO).

23. Coordination of activities of CARE.

24. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this List.

25. Administration of the following Acts :—

(a) Probation of Offenders Act, 1958; and

(b) Children Act, 1960.

26. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, denotified nomadic and semi-nomadic tribes and other Backward Classes including scholarships to students belonging to such Castes, Tribes and Classes.

27. (i) Appointment, resignation etc. of Special Officer for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc., and

(ii) Reports of the Special Officer.

28. Issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

29. Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

NOTE : The Ministry of Welfare will be the nodal Ministry for overall policy, planning and co-ordination of programmes of development for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

30. Reports of the Commission to Investigate into the conditions of Backward Classes.

31. (i) Scheduled Areas;

(ii) Matters relating to autonomous districts of Assam excluding roads and bridge works and ferries thereon; and

(iii) Regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas and for Tribal Areas specified in Part 'A' of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

32. (i) Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes; and

(ii) Issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

33. (i) Appointment, resignation etc. of Special Officer for Linguistic Minorities; and

(ii) Report of the Special Officer.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(PARMANU OORJA VIBHAG)

1. All matters relating to Atomic Energy in India, e.g. :

- (i) Administration of the Atomic Energy Act, 1962 including control of radio-active substances and regulation of their possession use, disposal and transport;
- (ii) Research including fundamental research in matter Connected with atomic energy and the development of its uses in agriculture biology, industry and medicine.
- (iii) Atomic minerals—Survey, prospecting drilling development, mining acquisition and control.
- (iv) All activities connected with the development and the use of atomic energy, including :
 - (a) projects and industries concerned with substances and minerals prescribed under the Atomic Energy Act, their products and by-products;
 - (b) generation of electricity through the use of atomic energy;
 - (c) design, construction and operation of research, development and power reactors; and
 - (d) establishment and operation of facilities and plants including diversification
 - (i) for the production of materials and equipment required for research into and the use of atomic energy and for research in the nuclear sciences;
 - (ii) for the separation of isotopes, including plants adaptable to the separation of isotopes as by product including the production of heavy water as a main or subsidiary product.
 - (v) Supervision of State undertakings concerned with prescribed or radio-active substances, including—
 - (a) Indian Rare Earths Ltd.
 - (b) National Fertilizers Ltd., in so far as production of heavy water is concerned.
 - (c) Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)
 - (d) Uranium Corporation of India Ltd. (UCI)

2. Financial assistance for the furtherance of studies in the nuclear sciences and for building up an adequately trained manpower for the development of the atomic energy programme, including—

- (i) Assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in the nuclear sciences; and

- (ii) Grant of scholarships in scientific subjects to students in Universities and other educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the nuclear sciences.

3. International relations in matters connected with atomic energy including—

- (i) Matters relating to atomic energy in the United Nations Specialised Agencies, International Atomic Energy Agency and in relations with other countries; and
- (ii) Correspondence with institutions, Universities etc. abroad in connection with foreign fellowships and the training of Indian scientists.

4. All matters relating to personnel under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

5. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

6. Procurement of stores and equipment required by Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

8. All matters connected with the advancement of higher mathematics, including—

- (i) Matters relating to the promotion and co-ordination of advanced study and research;
- (ii) International relations in higher mathematics, including in particular, matters relating to the Indian National Committee for Mathematics and the International Mathematical Union,
- (iii) Grants to institutions and associations engaged in the advancement of higher mathematics; and
- (iv) Grant of scholarships and other forms of financial aid for the advanced study and research.

9. All matters relating to the Tata Memorial Centre, Bombay.

10. All matters relating to the Tata Institute of Fundamental Research.

11. All matters relating to the Saha Institute of Nuclear Physics.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

(ELECTRONIKI VIBHAG)

1. Developments of Electronics and Coordination amongst its various users.

2. All matters relating to the personnel under the control of the Department.

3. Coordination of requirements relating to electronic processing equipment (computers)

4. All technology pertaining to silicon, other than metallurgical grade silicon.

5. National Silicon Facility.

6. All matters concerning computer based information, technology and processing including hardware and software, standardization of procedures and matters relevant to international bodies such as IFIP, IBI, ICC.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

(MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)

1. Matters relating to the Ocean and not specifically allocated to any other Department/Ministry.

2. Policies including coordination, regulatory measures and development relating to the Ocean and covering, inter alia—

- (i) research (including fundamental research) and the development of uses relating thereto;
- (ii) technological development;
- (iii) surveys to map and locate the availability of non-living and living marine resources;
- (iv) preservation, conservation and protection;
- (v) development of appropriate skills and manpower;
- (vi) collaboration, including technical collaboration; and
- (vii) laws relating to the above.

3. Marine environment on the high seas.

4. Ocean Commission.

5. The Pan Indian Ocean Science Association.

6. Ocean Science and Technology Agency or Board.

DEPARTMENT OF SPACE

(ANTARIKSH VIBHAG)

1. All matters relating to Space, Science, Space Technology and Space Applications, including—

- (i) research (including fundamental research) in matters connected with Space and the development of its uses;
- (ii) all matters connected with Space Technology;
- (iii) all matters connected with Space Applications; and
- (iv) all activities connected with the development and use of outer Space, including—
 - (a) projects and industries concerned with the utilisation of outer Space;
 - (b) the design, manufacture and launching of Rockets and Satellites, and
 - (c) work connected with Space Applications.

2. Financial Assistance for the furtherance of research and study in Space Science and Space Technology and for building up adequate trained manpower for the development of the Space programme including :

- (i) assistance to institution and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in Space Science; and
 - (ii) grant of scholarships to students in educational institutions, and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of Space Science.
3. International relations in matters connected with Space, including—
- (i) matters relating to Space in the United Nations specialised agencies and relation with other countries; and
 - (ii) correspondence with Universities and other educational institutions abroad in connection with foreign scholarships and the training of Indian scientists.

4. All matters relating to the personnel under the control of the Department.

5. Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department.

6. Procurement of stores and equipment required by the Department.

7. Financial sanctions relating to the Department.

8. All matters relating to the Physical Research Laboratory, Ahmedabad.

9. All matters relating to National Remote Sensing Agency (NRSA).

10. All matters relating to the National Natural Resources Management System including the generation of integrated data mainly based on remote sensing and assistance in the analysis and dissemination of such information.

CABINET SECRETARIAT

(MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)

1. Secretarial assistance to the Cabinet and Cabinet Committees.

2. Rules of Business.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

(RASHTRAPATI SACHIVALAYA)

1. To provide secretarial assistance to the President.

PRIME MINISTER'S OFFICE

(PRADHAN MANTRI KARYALAYA)

1. To provide secretarial assistance to the Prime Minister.

PLANNING COMMISSION

(YOJANA AYOG)

1. Assessment of the material, capital and human resources of the country, including technical personnel, and formulation of proposals for augmenting such of these resources as are found to be deficient.

2. Formulation of Plan for the most effective and balanced utilisation of the country's resources.

3. Definition of stages in which the Plan should be carried out on a determination of priorities and allocation of resources for completion of each stage.

4. Determination of the nature of the machinery necessary for the implementation of the Plan in all its aspects.

5. Appraisal from time to time of the progress achieved in the execution of each stage of the Plan.

6. Public Co-operation in National Development.

7. Hill areas development programme.

8. Perspective planning.

9. Directorate of Manpower.

NOTE:—The Planning Commission (Yojana Ayog) will be concerned broadly with technical questions relating to planning and the planning organisation itself. The policy and details of specific schemes included in the Plan are matters to be dealt with by the Central Administrative Ministries and State Governments.

ZAIL SINGH, President

[No. 74/2/1/85-Cab.]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.